



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 4, 1999/कार्तिक 13, 1921

No. 548]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 1999/KARTIKA 13, 1921

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1999

विषय : भारत में एसोटीन के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच-अंतिम निष्कर्ष।

सा.का.नि. 749(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क को पहचान और निर्धारण) नियम 1997 के अधीन।

(क) प्रक्रिया :

1. भारत में एसोटीन के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच आरंभ करने का नोटिस 16-6-99 को जारी किया गया था और 19-6-99 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। नोटिस की एक प्रति निम्नलिखित सभी जात उद्योगिक पक्षों को प्रेषित की गयी थी :—

घरेलू उत्पादक

- हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एच.ओ.सी.) मुम्बई
- हरडिलिया केमिकल्स लिमिटेड (एच.सी.एल.) मुम्बई
- राजाराम बापू पाटिल एस.एस.के. लि., बाल्वा, जिला सांगली (यहां बाद में बाल्वा के रूप में संदर्भित)
- चाल्यन विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली उद्योग लि. सुरत (यहां बाद में चाल्टन के रूप में संदर्भित)
- कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि., महाराष्ट्र (यहां बाद में कृष्णा के रूप में संदर्भित)
- नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई (नोसिल)
- कोरडाइट फैक्टरी अरुणकाडु, नीलगिरी
- सरसिल्क लि., आन्ध्र प्रदेश

सरसिल्क लि. को नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा गया था जो कि डाक प्राधिकारियों की "फैक्टरी बंद" का निष्पत्ति के साथ वापस आ गया था।

आयातक

- सी.जे. शाह एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- हर्श कुमार एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- क्रिसेन्ट ओर्गेनिक्स लि., मुम्बई
- एरोमा एजेंसीज, मुम्बई
- विनमार इण्टरनेशनल इंडिया प्राइवेट लि., मुम्बई

67

प्रयोगकर्ता उद्योग

- (i) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मुंबई
- (ii) ग्लैक्सो इंडिया लि०, मुम्बई
- (iii) कोग्रन लि०, मुम्बई
- (iv) चारखा केमिकल्स लि०, मुम्बई
- (v) एशियन पेट्स लि०, मुम्बई
- (vi) बेयर (इंडिया) लि०, मुम्बई
- (vii) बाम्बे आक्सीजन कारपोरेशन, मुम्बई
- (viii) हितकारी मल्टी फिल्टर्स लि०, मुम्बई
- (ix) गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स लि०, बड़ोदरा
- (x) आई सी आई लि०, प० बंगाल

निर्यातक

- (i) जार्जिया गल्फ कारपोरेशन, यू.एस.ए.
- (ii) मित्सुई केमिकल्स, टोकियो
- (iii) कुम्हो केमिकल कम्पनी, सियोल, कोरिया
- (iv) मेरिसोल/मेरिकेम ससोल, दक्षिण अफ्रीका
- (v) कोलमार पेट्रोकेमिकल्स ए.जी, स्टिटजरलैण्ड
- (vi) आई.सी.सी. केमिकल कारपोरेशन, न्यूयार्क

विदेशी एसोसिएशन

- (i) केमिकल सेफ्टी मैनेजमेंट सेण्टर, जापान केमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन - जे.सी.आई.ए., टोकियो 100, जापान ।
- (ii) केमिकल ऐण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन - (सी.ए.आई.ए.) आकलैण्ड पार्क 2008, दक्षिण अफ्रीका । (मेजा गया नोटिस वापस लौट आया)
- (iii) कोरियन पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन - (के.पी.आई.ए.) चोगू - कू, सियोल, कोरिया ।
- (iv) केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी.एम.ए.) वर्जीनिया - 22209, यू.एस.ए.

भारतीय एसोसिएशन

- (i) इंडियन केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई

2. प्रार्थना पत्र और प्रश्नावली के साथ नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों की सरकारों को दिल्ली स्थित उनके उच्चायोग/ राजदूतावासों जैसे कनाडा, चीन, चीनी ताइपेई, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, डी.पी.आर, कोरिया आर.पी. नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, यू.के. और यू.एस.ए. के माध्यम से प्रेषित की गई थी ।

3. उसी दिन प्रश्नावलियाँ सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को भी प्रेषित की गयी थी, जिन्हें कहा गया था कि वे अपना प्रत्युत्तर 26-7-99 तक प्रस्तुत कर दें ।

4. निम्नलिखित पक्षों द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया था :-

- (i) बेयर (इंडिया) लि०, मुम्बई
- (ii) गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, बड़ोदरा

उनके अनुरोधों को तथा सांविधिक अवधि में जाँच पूरी कर लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मै० बेयर्स (इंडिया) लि० को 30-7-99 तक समय वृद्धि की अनुमति दी गयी थी और मै० जी एस एफ सी को सूचित किया गया था कि वे अपना दृष्टिकोण सार्वजनिक सुनवाई के समय प्रस्तुत कर सकते हैं ।

5. दिनांक 16-6-1999 के नोटिस और प्रश्नावली के प्रत्युत्तर निम्नलिखित पक्षों से प्राप्त हुए थे :-

घरेलू उत्पादक

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुम्बई
- (ii) हरडीलिया केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई
- (iii) नोसिल, मुम्बई
- (iv) कोरडाइट फैक्टरी, अलवण्डाई
- (v) कृष्णा, महाराष्ट्र

आयातक

- (i) हरेश कुमार ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (ii) किसेन्ट इंटरनेशनल लि०, मुम्बई

प्रयोगकर्ता उद्योग

- (i) केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई
- (ii) बेयर (इंडिया) लि०, मुम्बई
- (iii) गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स लि०, बड़ोदरा

निर्यातक

- (i) मित्सुई केमिकल्स इंक, जापान
- (ii) मेरिसोल, दक्षिण अफ्रीका
- (iii) कुम्हो पी एंड बी केमिकल्स इंक., सियोल, कोरिया (मै० सैमसंग कारपोरेशन के माध्यम से)
- (iv) सासोल साल्वेट्स, दक्षिण अफ्रीका (मै० किसेन्ट आर्गेनिकल्स मुम्बई के माध्यम से)

6. नोटिस का प्रत्युत्तर निम्नलिखित द्वारा भी प्रस्तुत किया गया :-

(i) अरविन्दों फार्मा लि०, हैदराबाद

7. जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए अधिकारियों के दल ने मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, कोचीन, मै० हरडीलिया केमिकल्स लि०, मुम्बई, नोसिल, मुम्बई, मै० केसर पेद्रो प्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई, और किसेन्ट आर्गेनिक्स लि०, मुम्बई के परिसरों का दौरा किया। जांच के परिणामों को संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था और जांच रिपोर्ट की एक प्रति को सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया था।

8. सभी इच्छुक पक्षों की एक सार्वजनिक सुनवाई 10.9.99 को आयोजित की गयी थी जिसके लिए नोटिस 10.8.99 को प्रेषित किया गया था। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने द्वारा दिये गये मौखिक दलीलों की लिखित प्रस्तुति 16-9-1999 तक दर्ज कराये तथा दूसरों द्वारा दर्ज कराए गए उत्तरों की प्रतियों को 17-9-1999 तक प्राप्त करें और अपना खंडन, यदि कोई हो, तो 24-9-99 तक प्रस्तुत कर दें। निम्नलिखित पक्षों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया :-

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, मुम्बई
- (ii) हरडीलिया केमिकल्स लि०, मुम्बई
- (iii) राजराम, वाल्वा
- (iv) कृष्णा
- (v) बंयर इण्डिया लि०, मुम्बई
- (vi) केसेन्ट ओर्गेनिक्स लि०, मुम्बई
- (vii) केसर पेद्रो प्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई (काउंसिल के माध्यम से)
- (viii) मित्सुई केमिकल्स इंक, जापान (काउंसिल के माध्यम से)
- (ix) मित्सुई एंड क० लि०, जापान
- (x) सेमसंग कॉर्पोरेशन,
- (xi) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स
- (xii) रैनबोक्सी, नई दिल्ली
- (xiii) एम्बेसी ऑफ नाइवान, नई दिल्ली
- (xiv) साउथ अफ्रीकन हाई कमिशन, नई दिल्ली
- (xv) नोसिल, मुम्बई

(ख) निर्यातकों के दृष्टिकोण

निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं :-

(क) मित्सुई केमिकल्स इन्क०, जापान

(i) प्रथम भारतीय एसोडोन विनैमाता भारत में एकाधिकार की स्थिति में है। (जैसा उन्होंने स्वयं दावा

किया है कि वे घरेलू उत्पादन का 97% तक पर नियंत्रण रखते हैं) और ऐसा लगता है कि वर्तमान प्रार्थना पत्र का उपयोग उस एकाधिकारवादी स्थिति को बनाये रखने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। इस समय जिन मुद्दों की शिकायत की गयी है, उनमें से अधिकांश मुद्दे पिछले वर्षों में भी रहे हैं, जिन वर्षों में प्रार्थियों ने 102% से अधिक उपयोगिता क्षमता को प्राप्त किया था, जिससे स्पष्ट है कि इन कारकों ने उन्हें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि निर्यात में तीव्र गिरावट, जो यह संकेत करता है कि प्रार्थी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अप्रतिस्पर्धी हो चुके हैं, ही वर्तमान प्रार्थना पत्र का कारण है जिसका अभिप्राय भारतीय बाजार के एकाधिकारवादी प्रभुत्व को बनाये रखना है।

(ii) चाही गयी प्रमाणी लेवी की मात्रा से भी यह संकेत मिलता है कि प्रार्थीगण अपने लिए लाभ के एक स्तर को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के वर्तमान रुझान से संबंधित नहीं है। यह पूरी तरह भारतीय घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग की लागत को प्रभावित करके ही होगा। यह कार्रवाई पूरी तरह भारतीय उद्योग के लिए हानिकर लगती है और दो प्रार्थियों के लिए अवास्तविक कीमत/लाभ वसूलने के लिए तथा बाजार में प्रभुत्व बनाये रखने के लिए बहुत संकीर्ण परिप्रेक्ष्य के लिए की गयी लगती है।

(iii) यह प्रार्थना पत्र किसी 'गंभीर क्षति' को दिखाने में असफल रहा है तथा विशेष रूप से आयात और दर्शायी गयी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में भी असफल रहा है।

(iv) यह प्रार्थना पत्र किसी 'गंभीर परिस्थिति' को और विशेष रूप से 'अपूरणीय क्षति' को स्थापित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अनन्तिम शुल्क के अधिरोपण के लिए अनुरोध मानने योग्य नहीं लगता है।

(v) प्रार्थना पत्र कुछ गंभीर मुद्दों पर चुनी हुई और अनुचित रूप से सूचनाएँ प्रदर्शित करता है। इस तरह का एक उदाहरण निम्न और कम होती हुई उत्पादन क्षमता उपयोगिता के रूप में सूचना के संबंध में है। आवेदकों ने आरोप लगाया है कि निम्न और कम होती हुई उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए आयातों का परिणाम है, इस तथ्य को स्पष्ट किये बिना कि इन कम्पनियों की प्रमाणी एसीटोन क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है जो 1994-95 से कोई उत्पादन नहीं कर रही हैं या एसीटोन की नगण्य मात्रा का उत्पादन कर रही हैं। इस प्रकार की कम्पनियों द्वारा एसीटोन का उत्पादन न हो पाना, बढ़े हुए आयात के कारण नहीं है, क्योंकि 1994-95 में भी, जब आयात 9046 टी.पी.ए. तक कम था, उस समय भी उनके द्वारा कोई उत्पादन नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर विचार करना माँगी गयी क्षति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रस्तुत घटनात्मक सूचनाओं से अर्थ निकलता है कि आवेदन कर्ताओं ने जानबूझ कर उन आवश्यक सूचनाओं को छिपाने की दृष्टि से यह कार्य किया है जो उनके लिए हानिकर हो सकती थीं।

(vi) आवेदन कर्ताओं के विभिन्न प्रस्तुतियों के समर्थन में सूचना के स्रोतों का उल्लेख नहीं किया गया है या बाजार सूचना स्रोत के रूप में किया गया है। इस प्रकार के बाजार सूचना स्रोत स्पष्ट रूप से कमजोर हैं और सत्यापन के समय टिक नहीं सकते हैं, इससे प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण हो जाता है।

(vii) विभिन्न आंकड़े जैसे घरेलू माँग के आंकड़े पूर्ण आंकड़े नहीं हैं एवं गणितीय सूत्रों का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं। इसलिए इस प्रकार के आंकड़े सही स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

(viii) लाम के प्रतिष्ठित में गिरावट के संबंध में दिए गए कुछ आंकड़े उस स्थिति को शुद्ध रूप से प्रदर्शित करते हुए दिखाई नहीं पड़ते जो कि प्रार्थी कम्पनी के आडिट किए हुए प्रकाशित कुछ एकाउण्टों में दिए गए हैं। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनापत्र की विश्वसनीयता के संदर्भ में यह कुछ गंभीर समस्या का मामला है।

(ix) एच.ओ.सी. और हरडीलिया द्वारा दिखाया गया 240 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की दर से एसीटोन के नौमरण का आयात मूल्य उनके विचार में एक अपवाद स्वरूप मामला है और सामान्य विचार के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(x) विश्वव्यापीकरण के वर्तमान दौर में, स्थानीय कीमतें भी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रतिबिम्ब हैं। जैसा आवेदन पत्र से संकेत मिलता है कि आवेदनकर्ताओं की भारत के अन्दर बने रहने में समर्थ हो सकने (भारतीय घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग की कीमत पर), और पहले की तरह लाम कमाते रहने की मंशा है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव को पहचान पाने में पूर्णतः असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदनकर्ता इन कार्यवाहियों का उपयोग, लाम के अवास्तविक स्तर के लिए प्रयत्न करने और उसे प्राप्त करने हेतु कर रहे हैं, जिसे वे भारतीय बाजार के अपने एकाधिकारवादी प्रभुत्व की दृष्टि से इस्तेमाल कर सकें।

(xi) दोनों आवेदनकर्ताओं के बिक्री आंकड़ों का परीक्षण यह दिखाता है कि हरडीलिया के बिक्री आंकड़ों ने लगातार वृद्धि को ही प्रदर्शित किया है। वृद्धि का यह प्रतिरूप वर्ष 1998-99 के लिए दिए गए वार्षिक आंकड़ों के अनुसार ही है। जहाँ तक एच.ओ.सी. का संबंध है, दिए गए आंकड़े 1991-92 और उसके बाद से बिक्री के उतार-चढ़ाव वाले रुझान को प्रदर्शित करते हैं। 1998-99 के लिए योजनात्मक बिक्री भी बिक्री के इस उतार-चढ़ाव वाले रुझान का प्रतिबिम्ब है जो पहले एच.ओ.सी. के लिए थी। इसलिए प्रश्नगत आयात, आवेदनकर्ताओं को उनके बिक्री के संदर्भ में कोई गंभीर क्षति पहुँचाने वाला प्रतीत नहीं होता है।

(xii) जहाँ तक तैयार हो चुके स्टॉक का मुद्दा है, एच.ओ.सी. के स्टॉक की स्थिति का परीक्षण स्पष्ट करता है कि इसने भी उतार-चढ़ाव वाले प्रतिमान को प्रदर्शित किया है, यह प्रतिमान 1998-99 और उसके बाद भी बना रह सकता है। जहाँ तक हरडीलिया का संबंध है, समापन स्टॉक के उनके आंकड़ों का परीक्षण उनके पहले के निर्यात की तुलना के संदर्भ में किया गया, उन्होंने 1997-98 और 1998-99 में कोई निर्यात नहीं किया था, इससे स्पष्ट होता है कि स्टॉक का जमा होना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने में असफलता के कारण है। इसलिए प्रश्नगत आयात आवेदनकर्ताओं के स्टॉक की स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है।

(xiii) 86% की दर से नौंगे गये रक्षोपाय शुल्क की एच.ओ.सी. और हरडीलिया की गणना, लगायी गयी पूँजी पर 12% समुचित प्रतिकूल के रूप में प्रयोग करते हुए उनके न्यूनतम उचित कीमत पर आधारित है। आज 12% की यह दर वस्तु रसायनों के विनिर्माताओं के लिए अनुचित रूप से बहुत अधिक है और यहाँ तक कि एच.ओ.सी. और हरडीलिया द्वारा पहले वसूली गयी लाम की दरों से भी अधिक है। वर्ष 1995-96 में एच.ओ.सी. ने 14.20% का लाम अर्जित किया था, किन्तु उस अवधि के दौरान रसायन उत्पादों की कीमतें अपवाद स्वरूप बहुत ऊँची थी और ये कीमतें 1997 में गिरीं।

(xiv) भारत में एसीटोन की माँग बहुत तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के एसीटोन व्युत्पन्नों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल रसायनों में से एसीटोन एक है। इन एसीटोन व्युत्पन्नों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में

किया जाता है जो गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में है। औषध उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले ऐसीटोन की माँग 8% से 10% प्रति वर्ष बढ़ती रही है और ऐसीटोन का उपयोग करने वाले औषध उत्पाद भारत के बड़े निर्यातों में से एक है। ऐसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से ऐसीटोन चाहने वाले बहुत से विनिर्माताओं की कीमत पर केवल दो घरेलू ऐसीटोन उत्पादकों को लाभ होगा। इन ऐसीटोन विनिर्माताओं के विकास में देशी से भारत की सामान्य अर्थ व्यवस्था पर अपूरणीय विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(xv) वे स्वीकार करते हैं कि ऐसीटोन के घरेलू उत्पादकों को ऐसीटोन पर कम आयात शुल्क दर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, भारत में ऐसीटोन पर आयात शुल्क दर अन्य देशों के मुकाबले अभी भी काफी अधिक है।

(xvi) चूंकि ऐसीटोन के घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता भारत में ऐसीटोन की माँग को पूरा नहीं कर सकती, ऐसीटोन प्रयोग करने वालों को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के पश्चात भी आयातित ऐसीटोन खरीदना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों से भी अधिक कीमतों पर ऐसीटोन लेना उन प्रयोगकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बुरी तरह विकृत कर देगा। उन्होंने 1.4.94 से 31.3.99 तक भारत को अपने ऐसीटोन का निर्यात नहीं किया लेकिन आशा करते हैं कि वे निकट भविष्य में अपने उत्पाद की आपूर्ति करके ऐसीटोन के प्रयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करेंगे।

(xvii) रक्षोपाय कार्यवाही आरंभ करना बिल्कुल गलत है और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है क्योंकि अन्ततोगत्वा इन प्रक्रियाओं की पराकाष्ठा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी जो कि साफ तौर पर भारत के कानूनों का उल्लंघन होगा जैसा कि अन्य कानूनों में होता है। विशेषकर वे कानून जैसे एम.आर.टी.पी. अधिनियम जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को परिभाषित किया है।

(xviii) जिन कारकों के आधार पर क्षति का दावा किया गया है वे अन्तर्निहित कारक हैं और कुल मिलाकर भारतीय उद्योग के, तथा विशेषकर रसायन एवं औषध उद्योग के प्रतिरूप हैं जैसे कि सीमा शुल्क टैरिफ बॉक्सा, भारत में प्रचलित कीमतों की प्रणाली, संरचनात्मक कठिनाईयाँ इत्यादि। यह स्थिति विभिन्न सरकारी अध्ययनों तथा प्रकाशित पेपर्स से स्पष्ट है। अतः दर्शायी गयी क्षति आयातों के परिणामस्वरूप नहीं है।

(xix) आवेदन में कुछ आंकड़े उनके संदर्भ में हैं जो स्वयं ऐसीटोन के आयातक हैं। और फिर आवेदन ऐसे आंकड़ों को संदर्भित करता है जो ऐसी हस्तियों के लिए संगत हैं जिन्होंने स्वयं यह स्पष्ट करते हुए कि न तो उनको क्षति पहुँची है तथा न ही क्षति पहुँचने का खतरा है, इस आवेदन को समर्थन नहीं दिया है। ऐसी हस्तियों का संदर्भ एक विषम चित्र प्रस्तुत करता है जिससे यह विचारणीय विषय और अन्धकारमय हो जाता है।

(xx) भारतीय बाजार का अध्ययन यह बताता है कि मात्रा तथा गुणवत्ता की शर्तों के अनुसार माँग तथा आपूर्ति दोनों में फासला है जिससे प्रयोग करने वाले स्थानीय उद्योगों को जबरन आयात करना पड़ता है। किसी भी प्रकार के शुल्क जिससे आयात नियंत्रित हो अथवा नैहंगा हो, से स्थानीय प्रयोगकर्ता उद्योग को घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(xxi) आवेदकों ने भारत में आठ ऐसीटोन विनिर्माताओं की ओर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए आवेदन दिया है। इन आठ विनिर्माताओं को उनके विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से तीन

श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है -

(क)	क्यूमीन प्रक्रिया विनिर्माता	:	एच.ओ.सी. तथा हरडीलिया
(ख)	आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्रक्रिया विनिर्माता	:	नोसिल
(ग)	फरमेन्टेशन प्रक्रिया विनिर्माता	:	कोरडाइट, चात्थन, वालवा, सरसिलक तथा कृष्णा

चूँकि ऊपर दर्शाये गये ऐसीटोन विनिर्माताओं की वित्तीय/आर्थिक स्थितियाँ निश्चित रूप से मित्र हैं, आठों विनिर्माताओं को एक ही श्रेणी में ले लेना घरेलू ऐसीटोन उद्योग के स्तर के संबंध में गलत निष्कर्ष की ओर ले जाएगा। क्यूमीन प्रक्रिया सबसे सामान्य तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया है जिसे संसार के बड़े ऐसीटोन विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऐसीटोन के उत्पादन के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऐसीटोन प्रक्रिया अधिक लागत की प्रक्रिया है जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल के कच्चे माल के रूप में प्रोपिलिन की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। चूँकि प्रोपिलिन की कीमत बढ़ गई है, नोसिल ने अपना ऐसीटोन उत्पादन बन्द कर दिया है और अब वह मिथाइल आइसोब्यूटिल कीटोन (एम.आइ.बी. के.) तथा डाइऐसीटोन अल्कोहल (डी.ए.ए.) के उत्पादन के लिए ऐसीटोन का आयात कर रही है। चूँकि नोसिल ऐसीटोन के एक आयातक है, क्षति के लिए विचार करते समय उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। फरमेन्टेशन प्रक्रिया के विनिर्माता पहले इथनाल का उत्पादन करते हैं और फिर ऐसीटोन विनिर्माण के लिए इथनाल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। चूँकि सदमित अवधि में इथनाल की बिक्री ऐसीटोन के मुकाबले अधिक लाभदायक थी, फरमेन्टेशन प्रक्रिया के विनिर्माताओं ने ऐसीटोन के बदले इथनाल की बिक्री की। फिर भी, यद्यपि फरमेन्टेशन प्रक्रिया के विनिर्माताओं द्वारा उनकी क्षमता के मुकाबले ऐसीटोन का उत्पादन बहुत कम रहा है, उन्हें उस कम उत्पादन से कोई क्षति नहीं हुई है।

(xxii) भारत सरकार की खुली आर्थिक नीति के कारण ऐसीटोन की घरेलू माँग निरंतर बढ़ती रही है। चूँकि आवेदकों की उत्पादन क्षमता इस बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में असमर्थ है, ऐसीटोन इस्तेमाल करने वालों को विदेशी विनिर्माताओं से ऐसीटोन आयात करना पड़ता है। आवेदक घरेलू बाजार को सन्तुष्ट करने में असफल क्यों रहे, इसका कारण है अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी, जो कि उनके निर्यात में गिरावट से पूरी तरह स्पष्ट है। आवेदक यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक होते तो वे अपने उत्पाद का निर्यात बढ़ाकर अपने उत्पादन के लक्ष्य के स्तर को प्राप्त कर सकते थे।

(xxiii) आवेदकों की उपयोगिता क्षमता 1997-98 में 96.7 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 89.7 प्रतिशत हो गई है जिसके लिए हरडीलिया द्वारा 1998-99 में गतिरोधों को दूर करके उत्पादन क्षमता में विस्तारीकरण को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, न कि भारत में ऐसीटोन के बढ़े हुए आयात को। यदि यह इस विस्तारीकरण के लिए नहीं था, तो आवेदकों की उपयोगिता क्षमता 1998-99 में 94.1% होती।

(xxiv) आवेदकों ने 1994-99 के दौरान 87% से 102% की दर से उपयोगिता क्षमता का लाभ उठाया जो रसायन उत्पादों के लिए बहुत ही उच्च दर थी जिसे विश्व के मुख्य रसायन विनिर्माता भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(xxv) ऐसीटोन एक उपयोगी वस्तु उत्पाद है जो संसार भर में बेचा जाता है तथा इसकी कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई हैं। भारत में आयातित ऐसीटोन की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसीटोन

की कीमतों में गिरावट के कारण गिरी हैं। भारत में कीमतों की गिरावट की दर अन्य क्षेत्रों के समान है। भारत में आवेदकों को ऐसीटोन की कीमतें इसलिए गिरानी पड़ी ताकि वे विश्व की इस आर्थिक स्थिति से मुकाबला कर सकें। वर्धित आयात को भारत में ऐसीटोन की कीमतों में गिरावट का कारण नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में आवेदकों के लाभ में गिरावट इसलिए आई क्योंकि ऐसीटोन के विदेशी उत्पादकों के मुकाबले उनकी उत्पादन लागत बहुत अधिक है। आवेदक इस स्थिति में न तो अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकें और न ही पहले से ही उच्च उपयोगिता क्षमता के कारण अपना उत्पादन बढ़ा सकें। अतः वे भारत में ऐसीटोन की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में विफल रहे तथा संदर्भित अवधि में ऐसीटोन के घरेलू उत्पादकों का बाजार अंश गिर गया।

(XXVI) रसायन उद्योग पूरे विश्व में मंदी के दौर से गुजर रहा है और उसका प्रभाव भारतीय रसायन उद्योग पर भी पड़ा है। व्यापार और कीमतों में गिरावट का रुख भारत के लिए अनोखा नहीं है और आवेदक इससे अलग, अप्रभावित रहने का दावा नहीं कर सकते। इसलिए क्षति का जो दावा किया गया है, आयात उसका कारण नहीं है।

(XXVII) संसार भर में रसायन उद्योग एक चक्रीय उद्योग है जिसमें समय-समय पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं।

(XXVIII) रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से संभवतः दो उद्योग बच जाएंगे, किन्तु कई हजार इकाइयाँ पूर्णतः अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगी।

(XXIX) बिजनेस लाइन में 11 अप्रैल, 1999 को और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया में 8 जुलाई 1999 को प्रकाशित रिपोर्टों में एच.ओ.सी ने कुछ और ही बात कही है कि वे अच्छा कर रहे हैं। वे किसी अन्य मंच पर अपनी बात से विमुख नहीं हो सकते कि वे क्षतिग्रस्त हैं।

(XXX) बिजनेस लाइन के 20 जून, 1999 में एच.सी.एल ने घरेलू संरचना द्वारा बढ़ाये जाने पर विश्वव्यापी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के विपरीत प्रभाव जैसी समस्याओं और अन्य सामूहिक कम्पनियों या उनकी सहायक कम्पनियों से आयात आदि की पहचान की। आयात द्वारा पहुँची क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आयात के अलावा अन्य कारकों को उसमें से निकाल देना चाहिए।

(XXXI) मामले में निर्णय के अनुपात के अनुसार जिसे ग्लास के मामलों की कुछ श्रेणियों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, ओ जे 1986 सी 128/7, क्षति के बहुत से कारकों के कारण आयात नहीं बढ़े हैं।

(ख) मेरिसोल/ मेरीकेम ससोल, दक्षिणी अफ्रीका

उन्होंने जाँच आरंभ करने के नोटिस की प्राप्ति स्वीकार की, लेकिन कहा कि ऐसीटोन मेरीसोल उत्पाद श्रृंखला का भाग नहीं है।

(ग) कुम्हो पी तथा बी केमिकल इंक, सियोल, कोरिया

(i) कम्पनी ने 1998-99 के दौरान अपनी क्षमता, उत्पादन, उत्पादन लागत, घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य तथा भारत में प्रति इकाई निर्यात की कीमत संबंधी कुछ विवरण दिया है जो निम्नलिखित हैं-

वर्ष	1998	1999
क्षमता (मी. टन)	75,000	75,000
उत्पादन (मी. टन)	78,859	77,000
उत्पादन लागत (अमरीकी डालर)	308	299
कोरिया के घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य (अमरीकी डालर)	408	426
निर्यात कीमत	330	—
एफ.ओ.बी. कोरिया		

(ii) कम्पनी ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने पिछले तीन सालों में भारत को निम्नलिखित प्रकार से ऐसीटोन का निर्यात किया -

वर्ष	निर्यात (मी. टन)
1996	1040
1997	-
1998	4370
1999	-

(घ) ससोल सालर्वैट्स, दक्षिण अफ्रीका

(i) जब कि ससोल द्वारा विक्रय किये गये ऐसीटोन का विनिर्माण एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें कोयले को गैस युक्त किया जाता है और फिर पेट्रोलियम विनिर्माण उत्पाद तथा रसायन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें से एक ऐसीटोन है, ऐसीटोन के अन्य उत्पादक एक अन्य फीडस्टॉक का प्रयोग करते हैं जैसे नाफ्था, गैस, प्रोपिलिन, बेंजोलीन, क्युमिन और आइसो प्रोपिल अल्कोहल ।

(ii) ऐसीटोन की उनकी विनिर्माण क्षमता 1,70,000 टन है । वे 99.85% (शुद्धतम) की शुद्धता के ऐसीटोन का विनिर्माण करते हैं ।

(iii) उन्होंने मे० किसेन्ट आर्गेनिक्स लि. मुम्बई, जो भारतीय बाजार में ऐसीटोन आपूर्ति की माँग करने वाले उनके एजेंट हैं, ऐसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए जांच के मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया है।

मैसर्स किसेन्ट आर्गेनिक्स लिमिटेड, मुम्बई द्वारा प्रदर्शित दृष्टिकोण जो अधिकांशतः आयातकों के निवेदनों के सदृश हैं, को "आयातकों / उपयोगकर्ता उद्योग के दृष्टिकोण" के अधीन सम्मिलित कर लिया गया है।

ग. निर्वातक सरकारों के दृष्टिकोण

(क) चीनी ताइपेई (ताईवान)

उन्होंने ताइवान से भारत को निर्यात किये गये ऐसीटोन का विवरण प्रस्तुत किया और उन्होंने रक्षोपाय शुल्क जाँच को रोकने हेतु अनुरोध किया क्योंकि ताईवान से आयात किए गए ऐसीटोन की मात्रा कम थी और उन्होंने रक्षोपाय पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुच्छेद 12 के अनुसार पूर्व विचार-विमर्श की इच्छा प्रकट की थी।

(ख) व्यापार एवं उद्योग विभाग, लन्दन

जाँच आरंभ करने की नोटिस की सलाह के लिए उन्होंने अपना आभार प्रकट किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनको जाँच की प्रगति के विषय में सूचित किया जाता रहे।

(ग) दक्षिण अफ्रीका का उच्चायोग, नई दिल्ली

उनका विचार है कि ऐसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भारतीय उद्योग में विद्यमान परिस्थितियों द्वारा उचित नहीं है। भारत की प्रभावी और चालन क्षमता देश की ऐसीटोन की माँग को पूरा करने में समर्थ नहीं रही है और इस कारण से रिपब्लिक आफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारत को ऐसीटोन निर्यात किया जा रहा है।

ऐसीटोन की कीमतें अन्य पेट्रो रसायन जैसे प्रोपिलीन, बेन्जीन और क्यूमीन आदि की तरह 1998-99 में नीचे गिर गयी और इसलिए दक्षिण अफ्रीका द्वारा निर्यात किए गए ऐसीटोन को भी इसी रुझान की तरह नीचे गिरना था। दक्षिण अफ्रीका के ऐसीटोन का निर्यात भारत में मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और यह कि अप्रैल 1999 से ऐसीटोन की कीमतें महत्वपूर्ण रूप से ऊपर बढ़ रही हैं।

(घ) सऊदी अरब का राजदूतावास, नई दिल्ली

सऊदी अरब के शाही राजदूतावास, नई दिल्ली ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि उनकी जानकारी में, सऊदी अरब में ऐसीटोन का विनिर्माण नहीं किया जाता है और उन्हें भारत में ऐसीटोन जमा होने की कोई संभावना नहीं दिखायी पड़ती है।

घ. आयातकों/उपयोगकर्ता उद्योगों के दृष्टिकोण

आयातकों ने आमतौर पर निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाये हैं -

(i) जो उद्योग में हैं उनके लिए यह सार्वजनिक ज्ञान की बात है कि ऐसीटोन एक चकाकार उद्योग है तथा इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव व्यापार चक्र पर निर्भर करता है। साथ ही ऐसीटोन की कीमतें फिनल की कीमतों पर निर्भर करती हैं।

(ii) एक संयंत्र का 85-90% तक के स्तर का उपयोग बहुत ही अच्छा संयंत्र उपयोग है। आवेदक अपनी अनुकूलतम क्षमता के अनुसार उनको संचालित कर रहे हैं तथा उद्योग द्वारा उत्पादन में और अधिक वृद्धि जब तक कि कुछ क्षमताओं में वृद्धि न की जाए, संभव नहीं है। एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. के और भी अनेक आंतरिक/ बाह्य कारक हो सकते हैं जिनसे ऐसीटोन का उत्पादन प्रभावित हुआ हो और ये कारक जल्द ही तौर पर एक कारक "ऐसीटोन का आयात" पर ही नहीं सिमट सकते। उसी संदर्भित अवधि में फिनल का उत्पादन तथा बाजार के प्रति व्यवहार्यता, जैसा कि दस्तावेज में दिखाया गया है, का ऐसीटोन उत्पादन के निम्नतम स्तर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। शायद एच.ओ.सी. तथा एच.सी.एल. भी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ऐसीटोन का उत्पादन करने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्होंने स्वयं भी ऐसीटोन का आयात किया है।

(iii) एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. ने देश में ऐसीटोन उत्पादकों की प्रभावी क्षमता के विषय में सही स्थिति से अवगत नहीं कराया है। ऐतिहासिक तौर पर भारत में ऐसीटोन के आठ विनिर्माता रहे होंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि मैसर्स हरडिलिया केमिकल्स लिमिटेड (एच.सी.एल.), मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.) तथा मैसर्स नेशनल आर्गेनिक्स केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (नोसिल) के अलावा भारत में और कोई ऐसीटोन के विनिर्माता नहीं हैं जिन पर लगातार पूरे वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष, ऐसीटोन की आपूर्ति पर निर्भर किया जा सकता हो। "कोरडाइट" रक्षा उत्पाद मंत्रालय के अधीन है और वह केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसे सशस्त्र बलों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण हेतु स्थापित किया गया था। यह गैर रक्षा इकाइयों की आपूर्ति करने वाला नहीं है। चाल्थन (3000 टी.पी.ए.) वालवा (4500 टी.पी.ए.), सरसिल्ल (1500 टी.पी.ए.) तथा कृष्णा (4500 टी.पी.ए.) बुनियादी तौर पर मोलैसिस पर आधारित अल्कोहल की इकाइयों हैं जिन्होंने कोरडाइट (1320 टी.पी.ए.) की तरह अधिक खर्चीली तथा अव्यवहार्य ऐसीटोन विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना की है। ये अल्कोहल आधारित ऐसीटोन के विनिर्माता अपनी इकाइयों को तब फिर से शुरू करते हैं जब ऐसीटोन को मगमाने मूल्यों पर बेचा जा सके और यह तभी संभव हो सकता है जब या तो आयात कम मात्रा हो और/ या एच.सी.एल./एच.ओ.सी./नोसिल में बड़े पैमाने पर कामबन्दी हो जाए। इन इकाइयों को एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. द्वारा बहुत पहले से, जब देश में ऐसीटोन का आयात शुरू भी नहीं हुआ था, अप्रतिस्पर्धात्मक बना दिया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि अब एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. इन इकाइयों की वर्तमान दुर्दशा के लिए आयातकों को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कोरडाइट/ अल्कोहल इकाइयों को एसिटोन विनिर्माण करने वाली अव्यवहार्य क्षमताओं अर्थात् 14820 टी.पी.ए. को "प्रभावी विनिर्माण क्षमता" से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार नोसिल ने पाया है कि कुछ आई.पी.ए. से एसिटोन का उत्पादन मितव्ययी नहीं है और वे भी उत्तरोत्तर एसिटोन के विनिर्माण से अपने को हटा रहे हैं और एच.सी.एल. से / आयात द्वारा एसिटोन खरीद रहे हैं। उनके एच.सी.एल. से एसिटोन की खरीद ने भी एच.सी.एल. को प्रोत्साहित किया है कि वे उनके प्रोपिलिन का इस्तेमाल करें जो कि आयातों से 65% अधिक कीमती है। इसे देखते हुए नोसिल की 14000 टी.पी.ए. एसिटोन की उत्पादन क्षमता को निकाल देना चाहिए। भारत में विनिर्मित एसिटोन की प्रभावी एसिटोन क्षमता को एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. की 45,950 टी.पी.ए. वाली संयुक्त एसिटोन विनिर्माण क्षमताओं के अनुरूप तथा सहवर्ती समझा जाना चाहिए।

(iv) आवेदकों के लिए यह उचित नहीं है कि वे एक ऐसी वस्तु पर एकोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए याधिका दायर करें जिसका वे स्वयं भी आन्तरिक उपभोग के लिए अथवा भंडारण और बिक्री के लिए आयात करते रहे हैं। और फिर, एच.सी.एल./एच.ओ.सी./नोसिल द्वारा बड़े-बड़े पार्सलों के आयात ने दूसरे इच्छुक भारतीय आयातकों को इन विनिर्माताओं द्वारा की गई कीमतों की सौदेबाजी ने इस प्रकार के आयातों को आसानी से करने में समर्थ कर दिया।

(v) वर्धित आयात घरेलू एसिटोन उत्पादकों की हानि का प्रमुख कारण नहीं है। 1994-95 तक आवेदक एकाधिकार की स्थिति में संचालन कर रहे थे क्योंकि आयात तब तक आयात की उच्च दर प्रणाली (85% वास्तविक शुल्क) पर सीमित थी। सरकार ने अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण की नीति को लागू किया था और 1992-93 में 7-8 वर्षों में आयात शुल्कों में धीरे-धीरे कमी करने की योजना के साथ आयातों का उदारीकरण किया।

(vi) जहाँ रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाँच साल से भी कम समय में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित कर ली है वहाँ लगभग सात साल बाद भी ऐसा कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाए कि एच.सी.एल./एच.ओ.सी./नोसिल ने अपने आपको एसिटोन विनिर्माण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का प्रयास किया। इस सात साल की अवधि में उन्होंने अपनी पुरानी तकनीकों को छोड़कर विश्वव्यापी पैमाने पर उत्पादन करने के लिए विश्व स्तरीय कलात्मक तरीकों को नहीं अपनाया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर बेचने के लिए, एसिटोन का उत्पादन किया जा सके। यदि सात वर्षों के पश्चात वे केवल मार्गावरोध दूर करने में संतुष्ट हैं और उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा अथवा सस्ते मूल्यों पर मूल सामग्री के आयातों के जरिए कीमतों में बड़ी कमी नहीं की है तो उनके ग्राहकों को उनकी अकुशल खरीददारी/विनिर्माण प्रक्रिया के लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) आवेदकों की उच्च उत्पादन लागत ही शायद सालाना उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण है। मुख्य कच्चे माल की अप्रतिस्पर्धात्मक खरीददारी आयात की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों में एसिटोन का उत्पादन करने के लिए आवेदकों की असमर्थता का मुख्य कारण है। यह छानबीन करने की आवश्यकता है कि क्या कच्चा माल जैसे कि बैनजीन तथा प्रोपिलिन अथवा वैकल्पिक मूल सामग्री जैसे कि क्यूमिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर ली गई है। वे इस प्रकार के गम्भीर मुद्दों पर घुप रहे, जिसका कारण वे ही जानते हैं, कि क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर बैनजीन और क्यूमिन लेने की स्थिति में थे जो कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कथित हानि के लिए घातक कारण है। यदि दोनों आवेदकों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संदर्भित अवधि में 120 दिनों से 180 दिनों के लिए विस्तारित ऋणों पर बड़ी मात्रा में क्यूमिन लिया होता तो उनको एसिटोन की कीमतें पर्याप्त मात्रा में गिराने के लिए सक्षम होना चाहिए था।

(viii) अमरीकन गल्फ उत्पादक संसार में क्यूमिन के सबसे बड़े निर्यातक है। एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. सहित क्यूमिन के अधिकांश बड़े खरीददार अमरीका गल्फ क्षेत्रों से क्यूमिन लेते हैं। आई.सी.आई. एस - एल.ओ.आर. के आंकड़ों से यह पाया गया है कि क्यूमिन आयात की सी.आई.एफ. भारतीय आयात की कीमतें प्रायः एफ.ओ.बी. - अमरीका - गल्फ की कीमतों के बराबर होती हैं जिस पर अमरीका के एसिटोन के मुख्य उत्पादक क्यूमिन खरीद रहे हैं। चूंकि अमरीका के विश्वव्यापी एसिटोन के उत्पादकों की तुलना में क्यूमिन का प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों में आयात किया जा सकता था, बड़ी मात्रा में क्यूमिन का आयात न होने से एच.सी.एल./एच.ओ.सी. के लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

(ix) क्षति आयात के कारण नहीं हुई है बल्कि यह आवेदकों का संकीर्ण दृष्टिकोण है और शायद उनकी यह उम्मीद कि या तो कठिनाइयाँ स्वयं ही सुलझ जाएगी अथवा रक्षोपाय शुल्क लगाकर, जैसा कि फिनल के मामले में हुआ था, सरकार उनके बचाव के लिए आ जाएगी।

(x) यह समझ में नहीं आता कि कथित क्षमता का उपयोग न होते हुए भी एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. ने एसिटोन का आयात किया। एच.ओ.सी. का आयात विशेषकर संचारण और बिक्री के लिए था। बताया गया कि एच.सी.एल. द्वारा अपने संयंत्र तक एसिटोन ले जाया गया और उसके बाद उसे एसिटोन के ग्राहकों को बेच दिया गया। यदि जैसा कि एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. द्वारा कहा गया है कि वथित आयात के कारण एसिटोन के घरेलू उत्पादकों को क्षति पहुँची है तो इसका निर्धारण करना भी जरूरी हो जाता है कि एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. द्वारा एसिटोन के आयातों ने किस हद तक इस प्रकार की हानि के लिए योगदान दिया। नोसिल ने अभी तक आयातों द्वारा हानि का स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया है। तथापि उन्हीं तर्कों पर, उनके आयातों से उनको भी हानि पहुँचनी चाहिए थी। इन परिस्थितियों में यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. एसिटोन के आयातक होने का लाभ कैसे उठा सकते हैं और साथ साथ रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण की मांग कर रहे हैं। आवेदकों द्वारा आयातों की बोली लगाने ने भी कीमत को प्रभावित किया जिनके अनुसार बाद में आयात हुआ।

(xi) आवेदकों ने एसिटोन की मांग का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं किया है और उन्होंने इस तथ्य को छिपाया है कि देश में एसिटोन की मांग को पूरा करने के लिए प्रभावी विनिर्माण क्षमता सामान्यतः अपर्याप्त है। घरेलू उत्पादन 70,000 मी. टन की सालाना घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि आवेदक अपनी 100% उपयोग क्षमता पर भी वे घरेलू खपत को पूरा करने में विफल हैं और बहुत पीछे हैं। इसलिए केवल आयात के रास्ते से शेष माँग को पूरा किया जा सकता है। अधिकतर घरेलू उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आवेदकों से खरीदकर कर रहे हैं लेकिन दोनों को मिलाकर भी इतनी पर्याप्त क्षमता नहीं है जो सम्पूर्ण माँग को पूरा कर सके।

(xii) एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. की संचार स्थिति यह स्पष्ट रूप से बताती है कि उनका समस्त उत्पाद घरेलू बाजार में खप जाता है और आयातों का उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(xiii) दोनों आवेदकों की स्थापित क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय संयंत्र क्षमता की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा, आवेदकों द्वारा स्थापित संयंत्र असक्षम तथा तकनीकी तौर पर घटिया है। वे घरेलू बाजार में एसिटोन का अभाव उत्पन्न करते हैं और सदा ही अपने संयंत्र बन्द करके समायोजन करते रहते हैं तथा कीमते बढ़ा देते हैं यहाँ तक कि तब, जब अन्तर्राष्ट्रीय कीमते गिरी हुई होती हैं।

(xiv) ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि एसिटोन की कीमतों में और कमी होगी जो कि पता चला है कि मार्च 99 में 240 अमरीकी डालर प्रति मी. टन सी.आई.एफ. तक गिरी और जो पहले ही जुलाई 1999 में 370 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक बढ़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एसिटोन की कीमतें बढ़ने के कारण एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. के विनिर्माताओं ने मई/जून/जुलाई, 1999 में अपने बिक्री मूल्य 18,000 रु० प्रति मी. टन से बढ़ाकर 23,500/- रु० प्रति मी. टन कर दिए जो 1999 की आखिरी तिमाही में उनके द्वारा उठाई गई हानि से कहीं अधिक है। कीमतों में और अधिक वृद्धि हो रही बताई जाती है।

(xv) एसीटोन का आयात, आवेदकों द्वारा देशी एसीटोन उत्पाद का कम शुद्ध विक्रय मूल्य प्राप्त करने के कारण, बताया गया है। हालाँकि मामला यह नहीं है। कम विक्रय मूल्य मिलने का सच्चा कारण अप्रतिस्पर्धात्मक कीमते हैं जिस पर वे कच्चा माल, जैसे कि प्रोपिलिन, खरीदते रहे। आवेदकों द्वारा लाभ की कमी के लिए अनुचित रूप से आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए जिन्होंने जानबूझ कर खरीदने के तरीके पर अप्रतिस्पर्धात्मक रहना पसन्द किया।

(xvi) क्योंकि यह दावा किया गया है कि 180 दिनों के ऋण पर एसीटोन के आयातों ने आवेदकों के लिए धन की कठिनाईयों उत्पन्न कर दी हैं, उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि स्वयं उन्होंने आयातों का आश्रय लेकर, 180 दिनों के ऋण पर अपनी आवश्यकता का 100% प्रोपिलिन, बेन्ज़िन अथवा क्यूमिन क्यों नहीं लिया।

(xvii) आवेदक जून/जुलाई, 1999 के दौरान एसीटोन का अपना बिक्री मूल्य 21,500/- ₹० से 23,500/- ₹० प्रति मी. टन तक बढ़ा चुके हैं और उनके पास जुलाई, 1999 के दौरान अपने मूल्य वृद्धि 28000/- ₹० प्रति मी. टन और यहाँ तक कि 28000 मी. टन एक्स फैक्टरी तक भी बढ़ाने का अवसर था। एच.सी.एल. के मूल्यों की तुलना में मै० किसेन्ट इंटरनेशनल जैसे व्यापारियों ने 50 टन एसीटोन मै० कोप्रन लि०, मै० इन्धोसोल ड्रग्स और मै० ग्लैक्सो इंडिया लि० को 28,000/- ₹० प्रति मी. टन + उत्पाद शुल्क + करों की मूल कीमत पर बेचा। इस प्रकार एच.सी.एल./एच.ओ.सी. अपनी बिक्री प्राप्ति को बढ़ाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं कर रहे हैं।

(xviii) आवेदकों की नियोजित राशि पर 12% वापसी की उम्मीद अव्यवहारिक है। माँग और आपूर्ति की बाजार शक्तियाँ मूल्य निर्धारित करती हैं इसलिए नियोजित राशि पर 12% वापसी की एक स्पष्ट मांग रखना नगण्य एवं अवास्तविक होगा जब कि पूरे विश्व में एसीटोन के लिए इस प्रकार का कोई मांग नहीं है। आवेदक स्वयं के लिए लाभ का एक स्तर सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वर्तमान प्रवृत्ति से पूर्णतया असंबंधित है।

(xix) प्रोपिलिन और बेन्ज़िन को शुरुआती बिंदु मानते हुए, प्रत्येक आवेदक की कुल औसत प्राप्ति को नए रूप में गणना किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एसीटोन के निर्माण हेतु क्यूमिन के 100% आयात का सहारा लेकर शुरुआती बिंदु मानते हुए, यदि कुल औसत प्राप्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है, तो इसको अपनाया चाहिए था। एच सी एल मार्च 1999 में क्यूमिन का आयात 275 अमरीकी डालर प्रति मी.टन सी आई एफ पर कर रहा है। अधिक प्रतिस्पर्धी रूप में खरीदे गये आयातित आगत पर आधारित उत्पादन की लागत की समुचित संवीक्षा से लाभ में और वृद्धि हुई होती।

(xx) अप्रैल, 1999 से 150 अमरीकी डालर प्रति मी.टन से अधिक एसीटोन की सी आई एफ कीमतों (390 अमरीकी डालर प्रति मी.टन सी आई एफ) में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और प्रोपिलीन और बेन्ज़िन या क्यूमिन, यदि ये कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, की अधिक मूल्यों पर आयात की समावना को ध्यान में रखते हुए एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

(xxi) 86% की रक्षोपाय शुल्क दर गलत मूल्य मान्यता (240 अमरीकी डालर) और 12% की गलत उच्च वापसी पर आधारित है जो कि विशेषतः एसीटोन जैसे सह-उत्पाद जिसका मूल उत्पाद फिनॉल पहले से ही 22% रक्षोपाय शुल्क से संरक्षित है, के लिए पूरे विश्व में वस्तु रसायनों हेतु वास्तविक नहीं है।

उपरोक्त मुद्दों के अलावा कुछ आयातकों ने निम्नलिखित निवेदन भी किया है :-

मै० केसर पेद्रो प्रोड्यक्ट्स लि०, मुम्बई

(क) रक्षोपाय शुल्क का प्रयोजन घरेलू उत्पादकों को मूल्य संरक्षण उपलब्ध कराता है (आवेदन कोटा प्रतिबंध हेतु नहीं है)। यदि जांच पूरी होने के बाद यह पाया जाता है कि एसीटोन के मूल्य घरेलू उद्योगों के लिए संगत अवधि के दौरान सही मूल्य नहीं थे, उन्होंने एन्टी-डम्पिंग हेतु नामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत की जा रही प्रणाली पर न्यूनतम मूल्य के निर्धारण हेतु प्रार्थना की है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योगों ने यह स्वीकार किया है कि यदि आयात 22,000 रु० प्रति मी.टन पर प्राप्त हो तो उन्हें कोई क्षति नहीं है (विद्यमान सीमा शुल्क को ध्यान में रखते हुए) जिससे कि इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को आसान आपूर्ति सुनिश्चित होगी और घरेलू उद्योगों को संरक्षण भी उपलब्ध होगा।

(ख) एच ओ सी ने संकेत किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एसीटोन की कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए एच ओ सी ने 7 जुलाई, 1999 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि एसीटोन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी और 30 जून 99 से भारत सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए 22% रक्षोपाय शुल्क के आधार पर फिनाल का मूल्य भी 3000/- रु० प्रति मी.टन तक बढ़ा दिया और इस प्रकार 1998-1999 की अंतिम तिमाही में हुई क्षति को मूल्यों में वृद्धि करके पूरा किया। एच सी एल ने भी अपने पत्र दिनांक 1 जुलाई, 99 (रक्षोपाय शुल्क के लिए जांच आरंभ करने हेतु पत्र जारी होने के तुरंत बाद) एसीटोन की कीमत बढ़ा दी और इस प्रकार 1998-1999 की अंतिम तिमाही में हुए क्षति को मूल्य वृद्धि करके पूरा किया।

(ग) एच ओ सी के मूल्य संशोधन हमेशा तत्काल प्रभावी होते हैं और उन्होंने उन शेष सुपुर्दगी आदेशों, जो कि उनके द्वारा पुरानी दरों पर जारी किए गए थे, के विरुद्ध फिनाल और एसीटोन की आपूर्ति रोक दी। यह एकाधिपत्य प्रवृत्ति उपभोक्ताओं को एसीटोन और फिनाल की कीमतों का निर्णय नहीं करने देती और उन्हें क्षति होती है।

(घ) एच ओ सी फिनाल और एसीटोन का विनिर्माण अपने कोचीन इकाई में करते हैं और अन्य उत्पादों के विनिर्माण हेतु उनके पास रसायनी महाराष्ट्र में एक दूसरी इकाई है। एच ओ सी का कोचीन संयंत्र उच्च लाभदायक है और उनके रसायनी संयंत्र में हुई क्षति की पूर्ति कोचीन संयंत्र द्वारा की जाती है।

अरविन्दो फार्मा लि०, हैदराबाद

(ङ) एच ओ सी के खर्चें प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं जबकि एसीटोन की उत्पादन क्षमता में बड़ोत्तरी नहीं हुई है, इसलिए एच ओ सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी होने में समर्थ नहीं है। उन्हें अपने खर्चों को घटाने पर ध्यान लगाना चाहिए।

बेयर (इंडिया) लि०, मुम्बई

(च) अभाव के समय उन्होंने कर - अतिरिक्त आधार पर या अग्रिम लाइसेंस के विरुद्ध स्थानीय आयातकों से

आयातित एसीटोन की बहुत थोड़ी मात्रा का कय किया। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट का फायदा उठाने हेतु सीधे आयात का सहारा लेने के बजाए उन्होंने घरेलू उद्योगों की सम निर्यात प्रक्रिया के माध्यम से उच्च कीमत पर एसीटोन खरीदकर घरेलू उद्योगों की मदद की है। यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तो घरेलू उद्योग मूल्य वृद्धि का सहारा लेंगे जो कि मै० बेयर के लिए पूर्णतया अनुचित होगा और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करेगा। बड़े घरेलू उत्पादकों द्वारा एसीटोन की उपलब्धता की कोई संभावना नहीं है। यह बात ध्यान में रखते हुए कि आवेदकों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र इकाई है और उनकी वर्तमान आर्थिक दशा को भी ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास करना बहुत अधिक आशावादी होना होगा कि भारत सरकार द्वारा 650 करोड़ रुपये की वसुली कर ली जाएगी।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०

(ज) आयातित एसीटोन की उतराई के समय की कीमत की बराबरी करने के लिए वे देशी विनिर्माताओं से सम्पर्क करते हैं ताकि अपनी दीर्घकालीन उपलब्धता नीति के हितों की रक्षा के लिए वे बिना कोई अतिरिक्त लागत के देशी स्रोतों को जीवित रख सकें।

रेनबैयसी

(झ) जैसा उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया है, एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. की संयुक्त क्षमता 45950 मी टन थी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी क्षमता जुलाई-अगस्त 1999 में बढी है जिसकी उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उस हद तक एक प्रमाण पत्र देकर प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता है।

क्रीसेण्ट आर्गेनियस लिमिटेड

(जं) एच ओ सी और एच सी एल के विपरीत, एसीटोन का कोई भी घरेलू उत्पादक एसीटोन का अनिवार्य उत्पादक नहीं है। वे नोसिल और कोरडाइट को आवेदक के रूप में लेने पर आपत्ति करते हैं। अपने पूर्व के कार्य निष्पादन के आधार पर, वे वाल्टन और सरसिलक उत्पादकों को आवेदक के रूप में सम्मिलित करने पर आपत्ति करते हैं। 1994-95 से लगातार निष्क्रिय इकाइयाँ बनी रहने के कारण कृष्णा और वाल्वा को सम्मिलित करने पर भी आपत्ति करते हैं। घरेलू उत्पादकों को क्षति का सही कारण है कच्चे माल की मंहगी उपलब्धता, कीमतों को तेजी से बढ़ाने की उनकी असमर्थता और उत्पादन का अप्रतिस्पर्धी स्तर होना।

(ट) मित्सुई के सिंगापुर संयंत्र के साथ-साथ अमेरिका के बड़े संयंत्रों के पास एसीटोन को वापस प्रापीलीन में परिवर्तित करने की तकनीक है। इन नई क्षमताओं में से कोई भी एसीटोन का नहीं, बल्कि फिनाल का निर्यात करेंगे। इसलिए भारत को एसीटोन के निर्यात की लहर के बारे में कोई चिंता की बात नहीं है और इस आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध ठीक नहीं है।

(घ) घरेलू उत्पादकों के दृष्टिकोण

घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं :-

(क) कोरबाइट फैक्ट्री, अखनकाडु (नीलगिरि)

- (i) एसीटोन के विनिर्माण हेतु उनके कच्चे माल, इथाइल एल्कोहल के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखकर उन्होंने पिछले कुछ समय से एसीटोन का विनिर्माण बंद कर दिया है।
- (ii) वे एसीटोन के अधिक आयात से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं।
- (iii) एसीटोन के उपभोक्ता होने के नाते एसीटोन के मूल्यों में कमी के बारे में वे खुश हैं।

(ख) कृष्णा, सतारा

- (i) वे वर्ष 1984 से एसीटोन का विनिर्माण कर रहे हैं और उनकी क्षमता 4500 टन प्रति वर्ष है।
- (ii) लगभग 250 अमरीकी डालर प्रति टन की गिरावट कम कीमतों पर भारत में एसीटोन के वर्धित आयात (1998-99 में 28000 टन से अधिक) से घरेलू एसीटोन विनिर्माण उद्योगों को गम्भीर क्षति हुई है।
- (iii) गत सात वर्षों में भारत में एसीटोन का आयात 1992-93 में 2773 मी.टन से 1998-99 में 28,870 मी.टन, तक दस गुने से भी अधिक बढ़ा है।
- (iv) पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयात शुल्क में अधिक गिरावट भी भारतीय एसीटोन विनिर्माताओं को लुप्त होने की कगार पर ले गया।
- (v) एसीटोन के आयात के विरुद्ध रक्षोपाय जांच के लिए एच ओ सी और एच सी एल द्वारा प्रस्तुत आवेदन का वे समर्थन करते हैं जो कि घरेलू एसीटोन विनिर्माताओं की परेशानियों को कम करने के लिए किया गया है।

(ग) राजाराम बापू सहकारी शक्कर कारखाना, माव्हा

- (i) आयातों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि के साथ-साथ पिछले चार वर्षों में एसीटोन की आयात कीमतों में भारी गिरावट हुई है।
- (ii) 1995-96 में वे एसीटोन की विनिर्माण लागत की पूरी तरह भरपाई कर सके। 1996-97 में उताराई के समय आयात की कम लागत के कारण वे अपनी विनिर्माण लागत की भरपाई नहीं कर सके और उन्हें एसीटोन के उत्पादन को अस्थाई रूप में स्थगित करना पड़ा।
- (iii) एसीटोन के उत्पादन को पुनः आरंभ करने हेतु एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क वसूलने की प्रबल आवश्यकता उन्हें है।

(घ) नोसिल, मुम्बई

(i) वे एसीटोन के उत्पादक होने के साथ उपभोक्ता भी हैं ।

(ii) घरेलू उद्योगों द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति के साथ वे अत्यधिक सम्बन्धित हैं । पेट्रोकेमिकल एक चक्रीय उद्योग है और मूल्य व्यापार चक्र पर निर्भर होकर ऊपर नीचे होता रहता है । एसीटोन के मूल्य फिनॉल के मूल्यों पर निर्भर होते हैं ।

(iii) पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि लगभग 85-90% का संयंत्र उपयोग स्तर एक बहुत ही अच्छा संयंत्र उपयोग है । एच ओ सी और एच सी एल अपनी अधिकतम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं और उद्योगों द्वारा उत्पादन में और वृद्धि, नयी क्षमता जोड़ें बिना संभव नहीं हो सकती । देश में एसीटोन की कमी है, अतः शेष मांग आयात से ही पूरी की जाती है ।

(iv) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में नहीं है । रक्षोपाय शुल्क का प्रयोजन घरेलू उद्योग को मूल्य संरक्षण उपलब्ध कराना है (आवेदन, कोटा प्रतिबंध हेतु नहीं है) । यदि वर्तमान जांच पूरी होने के पश्चात यह पाया जाता है कि संगत अवधि के दौरान एसीटोन के मूल्य घरेलू उद्योगों के लिए उचित नहीं थे, उन्होंने एण्टी डम्पिंग शुल्क हेतु नामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत की गई प्रणाली पर, न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु प्रार्थना की है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योगों ने यह स्वीकार किया है कि यदि आयात 23,907 रु० प्रति मी.टन (सीमा शुल्क के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए एवं सीमा शुल्क और एस ए डी की अतिरिक्त छूटी को ध्यान में न रखते हुए) पर उपलब्ध हो तो उन्हें कोई क्षति नहीं है । यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं को सरल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और घरेलू उद्योगों को संरक्षण उपलब्ध कराएगी ।

(v) यह विवादित नहीं है कि भारत में आयात मूल्य 240 अमरीकी डालर प्रति टन तक गिरे हैं और यह भी संभव है कि इन मूल्यों पर आवेदकों को हानि हुई और जब मूल्य ऊंचे हो, उन्हें लाभ हुआ हो । चूंकि मूल्यों में गिरावट एक बाजार परिदृश्य है, उद्योग को रक्षोपाय शुल्क का कोई अतिरिक्त संरक्षण दिया जाना आवश्यक नहीं है विशेषतया तब जबकि बाजार में तेजी का फायदा घरेलू उद्योगों द्वारा भी उठाया गया हो ।

(vi) यह विचार करते हुए कि आवेदकों का क्षमता उपयोग पहले ही बहुत अच्छा है, यह उचित प्रतीत नहीं होता कि कम समय में घरेलू उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं । इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अन्य घरेलू कंपनियाँ जो एसीटोन उत्पादन के लिए क्षमता रखती हैं, वास्तव में गत 5 वर्षों से अधिक समय से एसीटोन का उत्पादन नहीं कर रही हैं और उनके संयंत्रों के बंद होने वाले कारण, आयात नहीं हो सकते ।

(vii) चूंकि आई पी ए रुट के माध्यम से एसीटोन का विनिर्माण किफायती नहीं है, नोसिल वाणिज्य बाजार के लिए एसीटोन की विशेष मात्रा का उत्पादन नहीं करता है । इसलिए नोसिल के पास उपलब्ध क्षमता घरेलू उद्योगों को प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(viii) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित करेगा और इसलिए यह सार्वजनिक हित में नहीं है, जिसे रक्षोपाय शुल्क नियमावली के अधीन विशेष आवश्यकताओं में से एक समझा जाता है ।

(ix) एसीटोन का उत्पादन होने के अलावा नोसिल, एसीटोन का कम निम्न कम के उत्पाद यथा मिथाइल आइसोबुटिल कीटोन (एम आई बी के) डाई एसीटोन एल्कोहल (डी ए ए) और मिथाइल आइसोबुटिल कार्बोनो (एम आई बी सी) जैसे उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी करता है । नोसिल एम आई बी के और एम आई बी सी का देश में अकेले विनिर्माता है । जबकि एम आई बी के मुख्यतः फार्मास्युटिकल, रबर केमिकल्स, सतह कोटिंग आदि में प्रयुक्त होता है, एम आई बी सी नाइट्रोसेलुलोज, रेसिनो आदि हेतु लेटेन्ट विलायक अथवा फ्लोटेशन में प्रयुक्त होता है ।

(x) एम आई बी के के लिए नोसिल अंतर्राष्ट्रीय रसायन कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है । अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा गंभीर है और एसीटोन पर अतिरिक्त छपूटी का कोई भी अधिरोपण एम आई बी के के विनिर्माण की व्यवहार्यता को गंभीर रूप में प्रभावित करेगा ।

(xi) घरेलू उद्योगों का पूरा मामला यह आरोप दिखाई देता है कि घरेलू उत्पादकों को अपने बिक्री मूल्य मार्च 1998 में 28 रु० प्रति किलो से मार्च 1999 में 18 रु० प्रति किलो तक घटाने के लिए बाध्य होना पड़ा । यदि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को मूल्य संरक्षण उपलब्ध कराना है तो रक्षोपाय शुल्क एन्टी डम्पिंग पर नामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत प्रणाली पर परिवर्तनशील आधार पर संस्तुत किया जाना चाहिए जो कि न केवल घरेलू उद्योगों को सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करेगा हालाँकि वे सोचते हैं कि रक्षोपाय शुल्क के रूप में कोई भी सहायता घरेलू उद्योगों को दी जानी आवश्यक नहीं है ।

(xii) 1998-99 में एसीटोन के लिए विद्यमान बाजार स्थिति पेट्रोकेमिकल की चक्रीय स्थिति के कारण थी । वास्तव में एसीटोन के मूल्य मार्च, 99 में 240 अमरीकी डालर प्रतिटन से जून, 99 में 360 अमरीकी डालर प्रति टन तक बढ़े । वे नहीं सोचते हैं कि उस अवधि में विद्यमान बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योगों द्वारा किसी समायोजन की आवश्यकता है ।

(ड.) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, मुम्बई एवं हर्षोलिया केमिकल्स लि० मुम्बई

(i) एच ओ सी की अपनी विनिर्माण इकाईयों (1) रासायनी 410027, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र (2) अम्बलमुगल 682302 जिला एर्नाकुलम, केरल में है और फिनाल संयंत्र केवल अम्बलमुगल में स्थित है । वे मूल आर्गेनिक केमिकल्स यथा एसीटोन, जिसे कि डाईमिथाइल कीटोन के नाम से भी जानते हैं, फिनोल जिसे कि कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं या हाइड्रोक्सी बेन्जिन, एनीलीन, नाइट्रोटोलुयन्स, नाइट्रोक्लोरो बेन्जिन, मोनोक्लोरो बेन्जिन, फार्मलडीहाइड, नाइट्रोबेन्जिन, सल्फुरिक एसिड साइक्लो हेक्सीलेमाइन, एसीटोनीलाइड कार्बिक सोडा, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, ब्यूटिन-1 और 4-डायल का विनिर्माण करते हैं ।

(ii) एच ओ सी एसीटोन का उत्पादन उच्च दबाव एवं तापमान पर वायु प्रयुक्त करते हुए क्यूमिन के आक्सीडेशन द्वारा करते हैं । यह कम सांद्रता पर क्यूमिन हाइड्रोपराक्साइड उत्पाद है जो कि तब अलकली में धोया जाता है और उच्च शक्ति पर सांद्रित किया जाता है । तब यह एच 2 एस ओ 4 के साथ मिश्रित किया जाता है जो कि फिनाल और एसीटोन देने हेतु एक क्लीवेज प्रतिक्रिया करता है । अम्लता हटाने के लिए इसे धोया जाता है और एसीटोन, फिनाल, अनरिएक्टेड क्यूमिन (जो कि एसीटोन और फिनाल के रूपांतरण के लिए रिसाइकिल किया जाता है) देने हेतु आसवन की श्रृंखला में आसवित किया जाता है । एसीटोन और फिनाल के विनिर्माण के लिए बेन्जिन और प्रोपिलीन मुख्य कच्चे माल हैं जबकि क्यूमिन एक मध्यवर्ती माल है । समय-समय

पर क्यूमिन खरीदा भी जाता है। उनके द्वारा विनिर्मित एसीटोन की भी वैसी ही गुणवत्ता एवं विशेषता है जैसी कि आयातित उत्पाद की।

(iii) एच सी एल मूल आर्गेनिक रसायनों और विशिष्ट उत्पादों जैसे फिनोल, एसीटोन, थैलिक एन्हाइड्राइड, डाईएसीटोन एल्कोहल, डोडीसिल फिनाल, नोनील फिनाल, डाई फिनाइल आक्साइड, आइसोबुटाइल बेन्जिन, आइसोफोरोन, हीट ट्रांसफर मीडिया, एसीटोफीरोन आदि का विनिर्माण करते हैं। आयातित एसीटोन और उनके द्वारा विनिर्मित एसीटोन सभी तरीके से एक जैसा है।

(iv) एच सी एल/एच ओ सी द्वारा विनिर्मित एसीटोन एक माध्यमिक या एक विलायक के रूप में विभिन्न आर्गेनिक सियोसिस में प्रयुक्त होता है चाहे एसीटोन से विनिर्मित रसायनों में आइसोफ्रोन, डाईएसीटोन एल्कोहल, मिथायल मिथाकाइलेट, बिस्फिनाल ए, रबर रसायन और सेलुलोस एसीटेट शामिल हैं। एसीटोन पेंट्स एवं कोटिंग्स के विनिर्माण में विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है।

(v) एसीटोन आयात उच्च वृद्धि दर पर निरन्तर बढ़े है, 1990 में औसतन 78% प्रतिवर्ष, 1993-94 और 1998-99 के बीच (1014 मी.टन से 21870 मी.टन तक) की वृद्धि हो रही है। आयात में यह तेजी विशेषतः 1998-99 के दौरान, विश्व में एसीटोन मूल्यों में अचानक कमी के कारण है। आयात में इस वृद्धि के साथ- साथ लाभ में गिरावट ने उद्योगों को इस हद तक प्रभावित किया है कि यदि यही स्थिति विद्यमान रहती है तो घरेलू एसीटोन उद्योग बंद हो सकते हैं।

(vi) आयातित एसीटोन की सी आई एफ दर 1995-98 के दौरान 490 से 880 अमरीकी डालर, 1998-97 में 380 से 490 अमरीकी डालर और 1997-98 में 440 से 530 अमरीकी डालर के बीच थे जो कि मार्च 1999 में 240 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक नीचे आ गए। आयात की लागत में इस कमी के साथ-2 सीमा शुल्क छूटी में 50% से लगभग 35% तक की कमी ने उन्हें प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया। घरेलू विनिर्माताओं की कुल प्राप्ति भी प्रभावित हुई है।

(vii) जबकि उत्पादन की लागत तकरीबन दिनोदिन बढ़ती जा रही है, घरेलू मूल्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों (सी आई एफ भारत) पर आधारित है, आयात शुल्क और विनियमन दर के बाजार शेयर की क्षति को कम करने की दृष्टि से तीव्र कमी करनी पड़ी। इससे लाभ पर दबाव पड़ा।

(viii) विगत 5 वर्षों में सबसे कम स्तर पर सी आई एफ भारतीय मूल्यों में तेज गिरावट होने के कारण विगत 5 वर्षों में आयात में औसतन दो गुने से भी अधिक 14454 टन प्रतिवर्ष की अचानक वृद्धि हुई। और आयात की उताराई के समय की लागत में कमी की तुलना में लाभ में कमी भी वर्तमान स्तरों पर हुई। वर्धित आयात के कारण बाजार की हानि से बिक्री कम हुई जिससे कि उच्च निर्धारित लागत प्रतिटन बढ़ा।

(ix) इन अत्यधिक कम मूल्यों वाले आयात के कारण, भारतीय विनिर्माताओं को जनवरी 1998 में अपनी कीमतें 31 रु० प्रति किलो से अक्टूबर 1998 में 21 रु० प्रति कि.ग्रा तक तथा मार्च 1999 में रु० 18 कि.ग्रा. (सभी मूल्य सूची मूल्य हैं) तक कम करनी पड़ी जिससे कि छूट के बाद नेट मूल्य सी बी डी सेटआफ के नेट 15 रु० प्रति कि.ग्रा. लगभग मेल खाते हैं। मार्च 1999 के आखिर तक जनवरी 1998 के 31 रु० प्रति कि. के मूल्य स्तर से मूल्य सूची में 13 रु०/- कि.ग्रा. की कमी हुई है। कच्चे माल के मूल्यों में कोई इस तरह की कमी नहीं हुई है। इस दृष्टि से, निर्माण की लागत अधिक है एवं लाभ दबाव में है।

(x) एच ओ सी ने 1998-99 के दौरान प्रथम तिमाही में 386 रु० प्रति मी.टन, दूसरी तिमाही में 6980 रु० प्रति मी. टन और तीसरी तिमाही में 447 रु० प्रति मी. टन का लाम दर्ज किया किन्तु चौथी तिमाही 1722 रु० प्रति मी. टन की हानि उठायी । इसी तरह हररीलिया ने 1998-99 की प्रथम और द्वितीय तिमाहियों में 3282 रु० प्रति मी. टन तथा 2264 रु० प्रति मी. टन का लाम उठाया किन्तु तीसरी और चौथी तिमाहियों में क्रमशः 1588 रु० प्रति मी. टन तथा 2096 रु० प्रति मी. टन की हानि उठायी ।

(xi) भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में एसीटोन आयात (पर्याप्त रूप में लागत एवं लम्बी क्रेडिट अवधियों पर) के कारण परिस्थितियाँ विनिर्माताओं को उपभोक्ताओं को अधिक क्रेडिट अवधि देने हेतु बाध्य कर रही हैं । दोनों कम्पनियों के मामले में कार्य पूजा चक्र के लम्बा होने से पिछले कुछ महीनों के दौरान कर्जदारों की पर्याप्त वृद्धि हुई है । जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः नकदी में कमी हुई। परिणामस्वरूप दोनों संगठनों को आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में कठिनाई हो रही है । एसीटोन के कर्जदार अगस्त 1998 में 32 दिनों से मार्च 1999 में 38 दिनों तक बढ़े । आयोजकों को विद्यमान बाजार दरों की तुलना में उच्च दरों पर राशि उधार लेनी पड़ी जिससे कि लाम में और अधिक कमी हुई ।

(xii) साख के लिए हररीलिया के साथ-साथ एच ओ सी की निष्पादन मानदण्ड भी एसीटोन के कम मूल्यों के कारण भी गिर गए जिससे कि उचित लागत पर धनराशि प्राप्त करने में कठिनाई हुई । इससे भविष्य में लाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लागत में ब्याज के घटक बढ़ेंगे । इसकी बहुत अधिक संभावना है ।

(xiii) धनराशि की कमी (और लाम की अनुवर्ती कमी) के कारण दोनों विनिर्माताओं को वित्तीय संस्थानों से फंड प्राप्त करने में वास्तव में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । परिणामतः ग्रीनफील्ड एसीटोन क्षमता के निर्माण हेतु दीर्घावधि योजनाओं को कार्यान्वित करने में देरी हो रही है

(xiv) कृत्रिम रूप से तरलीकृत गैसों हेतु पूर्णतः अपर्याप्त पतन संरचना के कारण वर्तमान में प्रोपिलीन आयात के योग्य नहीं है । प्रोपिलीन पर अत्यधिक माहा भी आयात को कठिन बनाता है । प्रोपिलीन की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय एच ओ सी मूल्यों से 65% अधिक हैं । और इन सबसे ऊपर प्रोपिलीन पर घरेलू माहा घरेलू प्रोपिलीन मूल्य से 15.20% अधिक है ।

(xv) भारत में बिजली, ईंधन, वित्त, यातायात आदि की लागत भी विश्व के अन्य भागों से अधिक है जहाँ एसीटोन का उत्पादन होता है । यह (भारत में) एसीटोन के विनिर्माण की उच्च लागत में सहायक है और एक ऐसा कारक है जो भारत में एसीटोन विनिर्माताओं के नियन्त्रण से बाहर है ।

(xvi) एसीटोन के सह उत्पाद (अर्थात् फिनॉल) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी पिछले एक वर्ष में तेजी से गिरे हैं जिसके कारण उसी अवधि के दौरान फिनॉल और एसीटोन की उतराई के समय की संयुक्त लागत भी तेजी से गिरी है। फिनॉल के घरेलू मूल्यों को भी और कम करना पड़ा । इसके कारण संयुक्त कुल प्राप्ति और फलस्वरूप फिनॉल और एसीटोन में लाम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । एसीटोन और सह उत्पाद फिनॉल के आयात की उतराई के समय की संयुक्त लागत गिरती हुई स्थिति को दर्शाते हुए बहुत नीचे गिर गयी ।

(xvii) प्रति इकाई घालन लागत को कम करने के उद्देश्य से एच ओ सी और एच सी एल अपनी तकनीक और अवरोधयुक्त संकीर्ण विनिर्माण सुविधाओं को उद्घीकृत कर रहे हैं और अधिकांश क्षेत्रों से बढ़ती घरेलू मांग को

पूरा करने हेतु अपनी प्रमाणी क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। बिजली लागत को कम करने हेतु उन्होंने को-जेनरेशन प्लंट द्वारा कैप्टिव बिजली उत्पादन सुविधा को लगाने हेतु कदम उठाए हैं और इससे लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। वे महाराष्ट्र में दाहेज या गुजरात राज्य में 100000 टन प्रति वर्ष या 150000 टन प्रतिवर्ष (80000 टन प्रतिवर्ष की एसीटोन क्षमता जो कि 90000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार योग्य है) विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड फिनान्स निर्माण सुविधा की स्थापना की योजना बना रहे हैं। एच ओ सी और एच सी एल के बीच सहयोगी प्रयास की भी संभावना है। तकनीकी आपूर्तिकर्ताओं और सलाहकारों की सहायता से वे अपनी क्षमता का विस्तार करके उच्चीकरण एवं आधुनिक तकनीक के जरिए वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं।

(घ) निष्कर्ष :

1. मैंने मामले के रिकार्ड एवं घरेलू उत्पादकों उपयोगकर्ताओं/आयातकों/निर्यातकों एवं निर्यातक सरकारों द्वारा प्रस्तुत जवाबों पर ध्यान दिया है। विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत निवेदनो एवं उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर नीचे दिए गए निष्कर्षों में उचित स्थानों पर विचार किया गया है।

2. जौंच के अधीन उत्पाद :

(i) जौंच के अधीन उत्पाद "एसीटोन" है (जिसे कि डाइमिथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है) जो केमिकल फार्मूला सी एच 3 सी ओ सी एच 3 के साथ एक मूल आर्गेनिक केमिकल है।

(ii) एसीटोन का विनिर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग करके किया जाता है, यथा क्यूमिन प्लंट, जो कि एच ओ सी और एच सी एल द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल (आई पी ए) पर आधारित प्लंट एवं एल्कोहल (इथनॉल) पर आधारित प्लंट। क्यूमिन प्लंट में एसीटोन उच्च तापमान और दबाव पर वायु प्रयोग करते हुए क्यूमिन के आक्सीडेशन द्वारा विनिर्मित होता है। कम सांद्रता पर क्यूमिन हाइड्रोपराक्साइड उत्पाद है जो कि तब अल्कली से धोया जाता है और उच्च शक्ति पर सकेन्द्रित किया जाता है। फिर यह एस 2 एस ओ 4 के साथ मिलाया जाता है जिसके कारण क्लीवेज रिएक्शन होता है जो फिनॉल एवं एसीटोन बनाता है। अम्लता हटाने के लिए यह धोया जाता है और फिनॉल, एसीटोन एवं अनरिएक्टेड क्यूमिन (जो कि फिनॉल और एसीटोन में परिवर्तन के लिए रिसाइकिल किया जाता है) देने के लिए आसवन कालम की श्रृंखला में आसदित किया जाता है। उसके बाद क्यूमिन उच्च दबाव एवं तापमान पर डोस फास्फोरिक एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में प्रोपिलीन एवं बेन्ज़िन के बीच प्रतिक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है।

(iii) आई पी ए आधारित प्लंट में एसीटोन, आई पी ए के डीहाइड्रो जेनरेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है। यह परिवर्तन कैटालिस्ट की उपस्थिति में उच्च तापमान पर किया जाता है जो कि साधारणतया एक धातु या एक अवस्थित धातु से समर्थित मेटालिक आक्साइड है।

(iv) एल्कोहल आधारित प्लंट में, एसीटोन, उच्च तापमान पर माप प्रयुक्त करते हुए एल्कोहल के कैटालिटिक किटोनाइजेशन द्वारा उत्पन्न किया जाता है।

(v) एसीटोन का विनिर्माण एकमात्र श्रेणी में रंगहीन द्रव्य के रूप में स्वीकार्य ईथर जैसी गंध के रूप में किया जाता है।

(vi) एसीटोन का प्रयोग अनेकों ऑर्गेनिक संश्लेषणों (बल्क औषधियों, कृषि रसायनों, डाइस्टफ, विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों और रसायनों) में माध्यम या विलायक के रूप में होता है । एसीटोन से विनिर्मित होने वाले रसायनों में आइसोफोरान, डाइएसीटोन एल्कोहल, मिथाइल मेथाक्राइलेट और बिसफिनोल-ए शामिल हैं । इसके अलावा एसीटोन का प्रयोग कुछ रबर रसायनों, आक्सी एसीटीलीन, सेलुलोस एसीटेट के विनिर्माण में एवं पेट्स/कोटिंग के विनिर्माण में विलायक के रूप में होता है ।

(vii) एसीटोन के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 2914.11 एवं हार्मोनाइज्ड कामोडिटी विवरण एवं कोडिंग प्रणाली (आई टी सी) पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के 29141100 के अधीन वर्गीकृत किया गया है । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 एवं भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अधीन एसीटोन का यह वर्गीकरण सुविधा के प्रयोजन से दर्शाया गया है एवं यह किसी तरह से जीव के अधीन उत्पाद को सम्मिलित करने के क्षेत्र को प्रतिबंधित नहीं करता ।

3. घरेलू उद्योग :

(i) कुल मिलाकर आठ घरेलू उत्पादक 74770 मी.टन प्रतिवर्ष की प्रभावी एसीटोन क्षमता के साथ एसीटोन उत्पादन की क्षमता रखते हैं । मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लि मुम्बई (एच ओ सी) और मै. हर्डीलिया केमिकल लि. मुम्बई (एच सी एल) एसीटोन का विनिर्माण क्यूमिन स्लट से करते हैं । नोसिल एसीटोन का विनिर्माण आई पी ए आधारित स्लट से करते हैं और अन्य पाँच घरेलू उत्पादक, यथा चाल्थन, सरसिल्क, कृष्णा, राजाराम (वाल्वा) और कोरडाइट इकाइयों एल्कोहल पर आधारित स्लट से एसीटोन उत्पादन क्षमता रखती हैं ।

(ii) नोसिल ने निवेदन किया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि आई पी ए स्लट के माध्यम से एसीटोन का विनिर्माण सस्ता नहीं है, इसलिए नोसिल विपणन बाजार के लिए एसीटोन की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं करता और इसीलिए नोसिल के पास उपलब्ध क्षमता घरेलू उद्योग के लिए प्रभावी रूप में उपलब्ध नहीं है । उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने आई पी ए के उत्पादन को अधिकतम करने का रास्ता चुना है जो कि निवेश पर बेहतर अतिरिक्त मूल्य/वापसी देता है । आई.पी.ए. के वर्धित उत्पादन से एसीटोन के उत्पादन को कम करने हेतु बढ़ावा मिलता है । इसी प्रकार कोरडाइट इकाई ने कहा है कि पिछले कुछ समय से उन्होंने एसीटोन का उत्पादन बंद कर रखा है और एसीटोन के उपयोगकर्ता के रूप में, एसीटोन मूल्यों में कमी होने से वे खुश हैं ।

(iii) हालाँकि मै० कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि० और मै० राजाराम बाबू पाटिल एस.एस.के. लि० यद्यपि इस आवेदन को प्रस्तुत करने में आवेदकों के साथ सम्मिलित नहीं हुए, परन्तु उन्होंने जीव में माग लिया है और एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए अपना समर्थन किया है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजी से गिरी कीमतों पर हुए वर्धित आयात के कारण उन्हें अपना उत्पादन निलंबित करना पड़ा जिससे कि एसीटोन का उत्पादन उनके लिए अव्यवहार्य हो गया और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उन्हें एसीटोन के उत्पादन को शुरू करने में सहायक होगा ।

(iv) 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान आठ घरेलू उत्पादकों का उत्पादन (मी. टन में) नीचे सारणी में दिया गया है ।

सारणी- 1
उत्पादन मी. टन में

वर्ष / कम्पनी	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
एच.ओ.सी.	23576	27024	21333	27555	25096
एच.सी.एल.	11579	12790	14151	14803	16126
नोसिल	7277	6731	3209	1523	1021
कोरडाइट	300	425	425	380	375
कृष्णा	0	1157	0	0	0
राजाराम	0	1429	166	0	0
सरसिलक	0	0	0	0	0
घात्यन	0	0	0	0	0
कुल	42732	49556	39284	44261	42618

(V) एसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि एसीटोन उत्पादन की 45950 मी. टन (1998-99) की संयुक्त क्षमता रखते हैं। 1998-99 के दौरान उन्होंने देश में उत्पादित कुल 42618 मी. टन एसीटोन में से 41222 मी. टन का उत्पादन किया। इसलिए एच.ओ.सी. और एच.सी.एल., दोनों घरेलू उत्पादन के अधिकतम अंश का उत्पादन करते हैं। इसलिए एच.ओ.सी. एवं एच.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत आवेदन को घरेलू उद्योग की ओर से किया गया माना गया है।

4. वर्धित आयात:

भारत में एसीटोन का आयात कनाडा, चीन, चीनी ताइपेइ, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, कोरिया डी.पी.आर., कोरिया आर.पी., नीदरलैंड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। वर्तमान में, भारत को एसीटोन के मुख्य निर्यातक जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अमेरिका हैं। एसीटोन पर आयात शुल्क जो कि 1993-94 में 85% था, 1994-95 में 65%, 1995-96 में 50%, 1996-97 में 40% और 1997-98 में 30%+2%+3% तक नीचे लाया गया। 1998-99 में एसीटोन पर आयात शुल्क 30%+5% यथामूल्य की दर पर था जिसमें सीमा शुल्क की अतिरिक्त छछूटी शामिल नहीं है।

(ii) 1994-95 में, भारत में मुख्यतः जर्मनी से (1001 मी. टन), नीदरलैंड से (826 मी. टन) फिलीपिंस से (1551 मी. टन) और यू.एस.ए. से (4839 मी. टन) कुल 9046 मी. टन एसीटोन का आयात हुआ। 1995-96 में बेल्जियम से (1037 मी. टन), चीनी ताइपेइ से (978 मी. टन), जर्मनी से (2549 मी. टन), कोरिया से (1452

मी.टन) नीदरलैंड से (2100 मी.टन), सिंगापुर से (820 मी.टन), दक्षिण अफ्रीका से (7498 मी.टन) और अमेरिका से (1098 मी.टन) एसीटोन का कुल आयात वस्तुकारिक रूप में 18519 मी.टन तक बढ़ा। 1998-97 में मुख्यतः जर्मनी से (1429 मी.टन), नीदरलैंड से (1415 मी.टन), दक्षिण अफ्रीका से (11124 मी.टन) यू. के से (1597 मी.टन) और अमेरिका से (7561 मी.टन) एसीटोन का आयात और अधिक बढ़कर कुल 26228 मी. टन हो गया। तथापि 1997-98 में कोरिया से (1401 मी.टन), नीदरलैंड से (637 मी.टन) सिंगापुर से (1770 मी. टन) दक्षिण अफ्रीका से (9030 मी. टन) और यू.एस.ए. से (3547 मी.टन) के साथ आयात घटकर 18574 मी. टन तक गिर गया। 1998-99 में आयात दक्षिण अफ्रीका से (16350 मी.टन), कोरिया से (2975 मी.टन) नीदरलैंड से (2571 मी.टन) रूस से (2040 मी.टन) अमेरिका से (1480 मी.टन) जर्मनी से (1365 मी.टन) और ताइवान से (1005 मी.टन) होने वाले मुख्य आयातों के साथ बढ़कर 29182 मी.टन तक के सर्वोच्च शिखर तक पहुँच गया।

(iii) आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में कुछ पक्षों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। विशेषतः 1998-99 की अवधि के दौरान के आयात आंकड़ों के बारे में। इस संबंध में घरेलू उत्पादकों ने प्रस्तुत किया है कि 1997-98 तक के वर्षों के लिए आँकड़े डी.जी.सी. आई.एस. कलकत्ता से लिए गए हैं। डीजीसीआईएस आँकड़ों के प्रकाशन में विलम्ब के कारण उन्होंने 1998-99 के लिए बाजार आसूचना स्रोतों पर आधारित आँकड़े लिए हैं। आयात आंकड़ों की प्रामाणिकता के संबंध में यह महसूस किया जाता है कि 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान के लिए आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े डी.जी.सी.आई.एस. आँकड़ों पर आधारित हैं और प्रामाणिक हैं। जहाँ तक 1998-99 के आँकड़ों का संबंध है, यह पाया गया है कि आवेदकों ने आवेदन में जहाजों का नाम, पहुँचने की तिथि, मात्रा, लदान का पतन और मूल्य आदि का विवरण देते हुए आयात के विवरण उपलब्ध कराए हैं। यह पाया गया है कि 1998-99 की अवधि के आयात आंकड़ों में किसी भी पक्ष द्वारा किसी विशिष्ट कमी की ओर इशारा नहीं किया गया है। तथापि, एसीटोन के आयात के आँकड़े सत्यापन के अधीन थे। काबुला सीमा शुल्क सदन ने 15610.442 मी.टन एसीटोन (15360.737 मी.टन का दावा आवेदकों द्वारा किया गया है) एवं मुम्बई सीमा शुल्क सदन ने 13472.549 मी.टन (आवेदकों द्वारा 13410.691 मी.टन का दावा किया गया है) एसीटोन के आयात की पुष्टि की है। आवेदकों ने 98.960 मी.टन एसीटोन का आयात चेन्नई पतन से होने का दावा किया है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पुष्ट किये गये आयात आँकड़ों एवं आवेदकों द्वारा दावा किए गए आयातों के आँकड़ों के बीच अन्तर महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए 1998-99 के दौरान एसीटोन का आयात 29182 मी.टन था। नीचे दी गई सारणी में 1994-95 से 1998-99 तक के आयात आँकड़े दर्शाए गए हैं।

सारणी 2 (आयात मी.टन में)

वर्ष	आयात	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (रु० मिलियन)
1994-95	9046	121.7
1995-96	18519	414.9
1996-97	26228	464.7
1997-98	18574	376.9
1998-99	29182	-

(iv) आयात 1994-95 में 9046 मी.टन से बढ़कर 1995-96 में 18519 मी.टन एवं 1996-97 में 26228 मी.टन हो गया। तथापि 1997-98 में आयात 16574 मी.टन तक नीचे गिर गया। 1994-95 को एक तरफ छोड़ते हुए, जबकि आयात निम्नस्तर पर था, 1995-96 से 1997-98 के दौरान भारत में एसीटोन के आयात की मात्रा औसतन 20440 मी.टन प्रतिवर्ष थी। 1998-99 में आयात 29182 मी.टन तक ऊँचा उठा अर्थात् 1995-98 की तुलना में लगभग 42.8% की वृद्धि हुई। तत्काल पूर्व वर्ष 1997-98 की तुलना में, 1998-99 में आयात में 76% की वृद्धि हुई। तुलनात्मक मर्दों में आयात 1994-95 में घरेलू उत्पादन का 21.17%, 1995-96 में 37.37%, 1996-97 में 66.77%, 1997-98 में 37.45% और 1998-99 में 68.47% था। घरेलू उत्पादन, आयात आंकड़ों तथा घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात को सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3
घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात

वर्ष	घरेलू उत्पादन (मी.टन)	आयात (मी. टन)	घरेलू उत्पादन के % के रूप में आयात
1994-95	42732	9046	21.17
1995-96	49556	18519	37.37
1996-97	39284	26228	66.77
1997-98	44261	16574	37.45
1998-99	42618	29182	68.47

(v) इस प्रकार आयात सम्पूर्ण रूप में, एवं घरेलू उत्पादन की तुलना में साथ साथ बढ़ा है।

5. गम्भीर क्षति की आशंका

(क) एसीटोन के आयात से प्रभावित घरेलू उत्पादक

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 बी की उपधारा B(सी) गम्भीर क्षति को पारिभाषित करती है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योगों की स्थिति में कुल मिलाकर महत्वपूर्ण क्षति पहुँचाना और उपधारा (घ) गम्भीर क्षति की आशंका को पारिभाषित करती है जिसका अर्थ है गम्भीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरा। आगे यह निर्धारण करने के लिए कि क्या वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है या होने की आशंका है, रक्षोपाय शुल्क नियमावली के परिशिष्ट की अपेक्षानुसार महानिदेशक को उस उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्यात्मक और परिमाणात्मक प्रकृति के समी संगत कारकों का मूल्यांकन करना चाहिए विशेष रूप में, सम्पूर्ण एवं सापेक्ष मर्दों में संबंधित उत्पाद के आयात में वृद्धि की दर और राशि, वर्धित आयात द्वारा कब्जा किए गए घरेलू बाजार का अंश, बिक्री उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग लाभ एवं हानि और रोजगार के स्तर में परिवर्तन को भी ध्यान में रखना होगा।

(ii) घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध एसीटोन की वास्तविक क्षमता के बारे में विभिन्न पक्षों द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। क्षति के विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने से पूर्व, इस मुद्दे पर पहले चर्चा करना आवश्यक समझा गया।

(iii) आवेदकों ने 1998-99 में आठ घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध 74770 मी.टन प्रतिवर्ष की प्रमावी एसीटोन क्षमता का दावा किया है जिन्होंने कुल मिलाकर 42818 मी.टन एसीटोन का उत्पादन किया जो कि प्रमावी एसीटोन क्षमता का केवल 57% उपयोग है। विभिन्न पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने उन कम्पनियों की क्षमता को भी शामिल कर लिया है जो कि 1994-95 से कोई भी उत्पादन नहीं कर रही हैं या बिल्कुल नगण्य मात्रा का ही उत्पादन कर रहे हैं। इनमें नोसिल की 14000 मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता भी शामिल है जिसने कि अपने संयंत्र में 1994-95 में 52%, 1995-96 में 48%, 1996-97 में 23%, 1997-98 में 11% और 1998-99 में 7% कार्य किया। एल्कोहल पर आधारित एसीटोन विनिर्माण इकाइयों, कमश: घाट्यन और सरसिल्क जो कि 3000 मी. टन प्रतिवर्ष एवं 1500 मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली इकाइयों हैं, ने 1994-95 से एसीटोन का उत्पादन नहीं किया। राजा राम (वाल्वा) और कृष्णा ने अपनी प्रत्येक की 4500 मी. टन प्रतिवर्ष की तुलना में 1995-96 में 2586 मी. टन एवं 1996-97 में 166 मी. टन का उत्पादन किया और उसके पश्चात एसीटोन का कोई उत्पादन नहीं किया। 1320 मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली कोरडाइट इकाई के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि यह इकाई केवल रक्षा मंत्रालय के लिए स्थापित की गई थी और इसलिए, यह इकाई अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं करती।

(iv) इस संबंध में पाया गया है कि नोसिल ने निवेदन किया है कि आई.पी.ए. रुट के माध्यम से एसीटोन विनिर्माण किफायती नहीं है, वे वाणिज्य बाजार के लिए एसीटोन की उल्लेखनीय मात्रा का विनिर्माण नहीं करते और इसलिए उनके पास उपलब्ध क्षमता प्रमावी रूप में घरेलू उद्योगों को उपलब्ध नहीं है। नोसिल के इस विशिष्ट आग्रह की दृष्टि में, उनकी क्षमता, घरेलू उत्पादकों को प्रमावी रूप में उपलब्ध है, को नहीं माना जा सकता है।

(v) जहाँ तक घाट्यन और सरसिल्क इकाइयों का संबंध है यह पाया गया है कि इन इकाइयों ने जॉच शुरू करने के नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही उन्होंने उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का जवाब प्रस्तुत किया है। इन इकाइयों ने 1994-95 से एसीटोन का विनिर्माण नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि घाट्यन और सरसिल्क दोनों अपने एसीटोन विनिर्माण को पुनः शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए उनकी विनिर्माण क्षमता घरेलू उद्योगों को प्रमावी रूप में उपलब्ध है, यह नहीं माना जा सकता है।

(vi) कोरडाइट इकाई ने निवेदन किया है कि एसीटोन के विनिर्माण हेतु उनके कच्चे माल, इथाईल एल्कोहल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उन्होंने पिछले कुछ समय से एसीटोन का विनिर्माण बंद कर रखा है। एसीटोन के अधिक आयात से वह साफ तौर से प्रभावित नहीं हैं और यह कि एसीटोन के उपभोक्ता के रूप में, एसीटोन की कीमतों में कमी के बारे में वे खुश हैं। उनके उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को देखते हुए, उनकी क्षमता भी घरेलू उद्योगों को प्रमावी रूप में उपलब्ध है, यह नहीं माना जा सकता है।

(vii) कृष्णा और राजाराम (वाल्वा) इकाइयों ने एसीटोन का उत्पादन करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है और उन्होंने एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने 1995-96 में 2686 मी. टन एवं 1996-97 में 166 मी. टन एसीटोन का उत्पादन किया है। उन दोनों में से प्रत्येक के पास 4500 मी. टन प्रतिवर्ष एसीटोन उत्पादन की क्षमता है। कुछ पक्षों का यह तर्क कि उन्होंने पिछले कुछ सालों से एसीटोन का उत्पादन नहीं किया है, इसलिए उनकी क्षमता को कुल उपलब्ध एसीटोन क्षमता में शामिल न किया जाए, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन एसीटोन क्षमताओं की केवल इसलिए अवहेलना नहीं की जा सकती कि ये इकाइयों पिछले दो सालों में एसीटोन उत्पादन में सफल नहीं हो सकी हैं। यह उनके द्वारा प्राप्त की गई गम्भीर

क्षति की एक अभिव्यक्ति है। क्योंकि उन्हें उत्पादन की लगभग पूर्ण हानि हुई है, यदि इस अकेले आधार पर उनको घरेलू एसीटोन उद्योग के हिस्से के रूप में विचार नहीं किया जाता है तो इससे क्षति में और वृद्धि होगी। उन्होंने एसीटोन उत्पादन को पुनः आरंभ करने की अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है। इस संबंध में यह पाया जाना भी महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में बहुत सी इकाइयाँ एल्कोहल आधारित रुट का प्रयोग करते हुए एसीटोन का उत्पादन करती हैं। इसलिए एल्कोहल को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करके भारत में एसीटोन का उत्पादन करना अपवाद नहीं है।

(viii) उपरोक्त चर्चा को देखते हुए विचार किया गया है कि केवल एच.ओ.सी., एच.सी.एल., कृष्णा और राजाराम (बाल्वा) इकाइयों (नोसिल, कोरडाइट, चाल्थन और सरसिलक इकाइयों को छोड़कर) के बारे में क्षति का विश्लेषण किया जाना है जिन्हें यहाँ "प्रभावित घरेलू उत्पादक" के रूप में संदर्भित किया गया है। 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान प्रभावित घरेलू उत्पादकों की एसीटोन क्षमता और उत्पादन नीचे सारणी 4 में दिया गया है:-

सारणी-4

प्रभावित घरेलू उत्पादकों की क्षमता और उत्पादन

उत्पादक	क्षमता					उत्पादन				
	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
एच.ओ.सी.	24640	24640	24640	27650	27650	23578	27024	21333	27555	25096
एच.सी.एल.	12000	14400	16170	16170	18300	11579	12790	14151	14803	16126
कृष्णा	4500	4500	4500	4500	4500	0	1157	0	0	0
राजाराम	4500	4500	4500	4500	4500	0	1429	166	0	0
कुल	45640	48040	49810	52820	54950	35155	42400	35650	42358	41222

(ख) घरेलू उत्पादन :

(i) प्रभावित घरेलू उत्पादकों की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1994-95 में घरेलू उत्पादन 35155 मी. टन था। 1995-96 में घरेलू उत्पादन 42400 मी. टन तक बढ़ा लेकिन 1996-97 में 35650 मी. टन तक तेजी से गिरा। फिर 1997-98 में घरेलू उत्पादन 42358 मी. टन तक बढ़ा और 1998-99 में 41222 मी. टन तक गिरा। घरेलू उत्पादन, जिसने 1996-97 की तुलना में 1997-98 में लगभग 18.8% की वृद्धि दर्ज की, वहीं 1997-98 की तुलना में 1998-99 में 2.68% की गिरावट हुई।

(ii) यह पहले कहा जा चुका है कि देश में आठ घरेलू उत्पादकों के पास विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते हुए विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से एसीटोन उत्पादन की क्षमता थी। इन उत्पादकों को तीन विभिन्न श्रेणियों, यथा अल्कोहल आधारित उत्पादक, आई पी ए आधारित उत्पादक एवं क्यूमिन आधारित उत्पादक में रखा गया है। विभिन्न पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विभिन्न श्रेणियों में आने वाले ये उत्पादक उत्पादन का विभिन्न स्तर रखते हैं और यह कि कुछ उत्पादक पिछले कुछ सालों से एसीटोन उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नोसिल एसीटोन का उत्पादक होने के बजाए एक आयातक बन गया है। आवेदकों ने एसीटोन उद्योग की इस विशिष्ट स्थिति को यह कह कर स्पष्ट किया है कि घरेलू एसीटोन उद्योग की क्षति कई घरणों में हुई है। आवेदकों ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त रूप में कम कीमतों पर अधिक आयात के कारण भारतीय एसीटोन विनिर्माण उद्योग 1996-97 से प्रभावित होना आरंभ हुआ। इस संबंध में यह पाया गया है कि 22407 रु० प्रति मी. टन के औसत सी आई एक मूल्य पर 1995-96 में 18519 मी. टन की तुलना में 17718 रु० प्रति मी. टन के औसत सी आई एक मूल्य पर 1996-97 में आयात 26228 मी. टन की ऊंचाई तक पहुँच गया। इसका परिणाम घरेलू उत्पादन पर पड़ा (सभी इकाइयों शामिल हैं) जो 1994-95 में 42732 मी. टन से 1995-96 में 49556 मी. टन की चरम सीमा पर पहुँचा और 1996-97 में 39284 मी. टन तक नीचे गिर गया। उद्योग का जो पहला क्षेत्र प्रभावित हुआ वह अल्कोहल आधारित उत्पादक थे जिनका उत्पादन 1996-97 में 591 मी. टन तक कम हो गया जो कि गत वर्ष 1995-96 में 3011 मी. टन (425 मी. टन कोरहाइट द्वारा, 1429 मी. टन राजाराम (वाल्वा) द्वारा तथा 1157 मी. टन कृष्णा द्वारा) था। 1996-97 के पश्चात् कोरहाइट के अलावा इन इकाइयों को अपना उत्पादन बन्द करना पड़ा। इस तथ्य की नुमिका यह है कि 1980-81 से 1996-97 के बीच भारत में गन्ने के उत्पादन में बढोतरी हुई जिसके फलस्वरूप अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार हुआ जिसके कारण अल्कोहल आधारित एसीटोन के उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। इसके विपरीत इन इकाइयों को 1996-97 के पश्चात् अपना एसीटोन का उत्पादन बन्द करना पड़ा।

(iii) घरेलू उद्योग का जो दूसरा क्षेत्र प्रभावित हुआ वह आई.पी.ए. आधारित एसीटोन उत्पादक नोसिल था जिसने 96-97 में अपने एसीटोन उत्पादन में 50% से भी अधिक की हानि उठाई जो कि 1995-96 में 6731 मी. टन की तुलना में 3209 मी. टन तथा 1994-95 में 7277 मी. टन था। 1997-98 में 1523 मी. टन तक की उनके उत्पादन में और गिरावट हुई जो कि 1998-99 में 1021 मी. टन रह गया। इस कारण से भी नोसिल को एसीटोन के उत्पादक की अपेक्षा एसीटोन के बड़े आयातक के रूप में परिवर्तित होना पड़ा।

(iv) आवेदक कम्पनियों, जिनको कुछ दलों ने एसीटोन के अनिवार्य उत्पादकों के रूप में घोषित किया हुआ है, को भी एसीटोन के आयातों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा लेकिन फिनल/एसीटोन संयंत्रों में समर्पित अपने निवेश को बचाने के लिए उन्हें अपना उत्पादन कम अथवा बन्द करने से वंचित किया गया तथा उनको अपनी क्षति कम करने के लिए अपने संयंत्र आशा के आधार पर नुकसान उठा कर भी चलाने पड़े। तथापि उन्होंने उत्पादन में भी नुकसान उठाया। एच.ओ.सी. जिसने 1997-98 में 27555 मी. टन का उत्पादन किया था, 1998-99 में केवल 25096 मी. टन का उत्पादन किया। एच.सी.एल. ने 1997-98 में 14803 मी. टन के मुकाबले में 1998-99 में 16126 मी. टन का कुछ अच्छा उत्पादन किया। कुल मिलाकर, क्यूमिन आधारित दोनों आवेदक कम्पनियों ने 1997-98 में 42358 मी. टन उत्पादन की तुलना में 1998-99 में 41222 मी. टन का उत्पादन किया।

(v) इस प्रकार एसीटोन के घरेलू उत्पादकों को 1997-98 की तुलना में 1998-99 में एसीटोन के उत्पादन में हानि हुई।

(ग) क्षमता उपयोग

(i) जैसा कि ऊपर 'क' पर चर्चा की गई है, घरेलू उद्योग के पास एसीटोन क्षमता की उपलब्धता चार उत्पादकों की है यथा एच.ओ.सी., एच.सी.एल., कृष्णा तथा राजाराम (वाल्वा) इकाईयों। 1994-95 में उनकी कुल एसीटोन क्षमता 45840 मी. टन प्रति वर्ष थी जो बढ़कर 1995-96 में 48040 मी. टन प्रति वर्ष, 1996-97 में 49810 मी. टन प्रतिवर्ष, 1997-98 में 52820 मी. टन प्रति वर्ष तथा 1998-99 में 54950 मी. टन प्रति वर्ष हो गई। इस अवधि के दौरान उन्होंने सामूहिक रूप से क्रमशः 35155 मी. टन, 42400 मी. टन, 35650 मी. टन, 42358 मी. टन तथा 41222 मी. टन एसीटोन का उत्पादन किया। उनका क्षमता उपयोग, जो 1994-95 में 77% से 1995-96 में 88.3% की चरम सीमा तक ऊँचा उठा, को 1996-97 में जबरदस्त धक्का लगा जब वह 71.6% तक गिर गया। 1997-98 में क्षमता उपयोग ने एक बार फिर 80.2% की बहुतेतरी दर्ज किया परन्तु उसके पश्चात 1998-99 में 75% तक गिर गया। अतः इस प्रकार एसीटोन के घरेलू उत्पादकों ने क्षमता उपयोग में सुकसान उठाया है।

(ii) कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों द्वारा 87% से 102% तक का क्षमता उपयोग का उच्च स्तर प्राप्त किया गया जो कि रसायन उत्पादों के लिए अत्यधिक उच्च दर है और जिसे विश्व के अधिकांश बड़े रसायन विनिर्माता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में यह पाया गया है कि 1995-96 में एच.ओ.सी. ने 103% तक का उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त किया तथा 1994-95 में एच.सी.एल. ने 96.5% क्षमता उपयोग प्राप्त किया। वर्ष 1998-99 में एच.ओ.सी. तथा एच.सी.एल. ने फिर भी क्रमशः 91% तथा 88% का क्षमता उपयोग प्राप्त किया। जहाँ यह भी संभव है कि ये क्षमता उपयोग विश्व के बड़े रसायन विनिर्माताओं के संदर्भ में उच्च दर समझा जा रहा हो, उनके अपने पिछले निष्पादन के संदर्भ में, दोनों एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. ने क्षमता उपयोग में गिरावट दर्ज की। कुल मिलाकर "प्रभावित घरेलू उत्पादकों" ने भी 1998-99 में क्षमता उपयोग में हानि उठाई है जो कि 1995-96 में 88.3% की तुलना में 75% था जो 13.3% प्वाइंट की हानि थी।

(घ) विक्रय

(i) नीचे दी गई सारणी 1994-95 से 1998-99 की अवधि के "प्रभावित घरेलू उत्पादकों" के घरेलू बिक्री (निर्यात तुल्य आधार पर घरेलू बाजार में बिक्री तथा कैप्टिव खपत सहित) के आंकड़े दर्शाती है :-

सारणी - 6
घरेलू बिक्री मी. टन में

वर्ष	एच.ओ.सी.	एच.सी.एल.	कृष्णा	राजाराम (वाल्वा)	योग
1994-95	21411	11567	0	0	32978
1995-96	26694	12380	1157	1429	41660
1996-97	19817	14089	0	166	34072
1997-98	26568	14797	0	0	41365
1998-99	25839	16068	0	0	41907

(ii) सारणी यह दर्शाती है कि प्रभावित घरेलू उत्पादकों ने 1994-95 में 32978 मी.टन की घरेलू बिक्री प्राप्त की (समतुल्य निर्यात के आधार पर बिक्री तथा कैप्टिव खपत सहित) जो कि 1995-96 में 41680 मी.टन तक बढ़ गई और 1996-97 में गिर कर 34872 मी. टन हो गई । उसके पश्चात 1997-98 में घरेलू बिक्री 41365 मी. टन पहुँच गई और फिर लगभग 1.3% बढ़कर 1998-99 में 41907 मी.टन हो गई । घरेलू बाजार की (सारणी 6) कुल स्पष्ट खपत (घरेलू बिक्री + आयात) में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 1998-99 में घरेलू बिक्री में इस सीमान्त वृद्धि को देखने की आवश्यकता है जिसने 1997-98 (59842 मी.टन) की तुलना में 1998-99 (72483 मी.टन) की लगभग 21.1% की वृद्धि दर्ज की । घरेलू उत्पादक स्पष्ट उपभोग में 21.1% की वृद्धि की तुलना में बिक्री में अल्प वृद्धि को केवल अपने औसत विक्रय मूल्य में तीव्र कमी करके ही प्राप्त कर सके जो कि मार्च 1998 में 28/-रु० प्रति किलो की तुलना में मार्च, 1999 में 18/-रु० प्रति किलो कम कर दी गई थी ।

सारणी - 6
आमासी खपत मी. टन में

वर्ष/कम्पनी एच ओ सी एच सी एल नोसिल कोरडाइट कृष्णा राजाराम चाल्टन सरसिल्क आयात कुल योग										
1994-95	21411	11567	7277	300	-	-	-	-	9046	49601
1995-96	26694	12380	6731	425	1157	1429	-	-	18519	67335
1996-97	19769	14089	3209	425	-	166	-	-	26228	63886
1997-98	26568	14797	1523	380	-	-	-	-	16574	59842
1998-99	25839	16068	1021	375	-	-	-	-	29182	72483

(iii) एच ओ सी और एच सी एल ने 1997-98 की तुलना में 1998-99 में कुल बिक्री पर हानि उठाई । एच ओ सी ने 1997-98 में औसत 21713/रु० प्रति मी. टन (थोक) की बिक्री की जो कि 1998-99 में गिर कर 18919 रु० प्रति मी. टन (थोक) रह गई । एच सी एल के मामले में, 1997-98 में 24682/रु० प्रति मी. टन की औसत बिक्री प्राप्ति 1998-99 में गिरकर 20982/रु० प्रति मी. टन (थोक) रह गई । (एच ओ सी और एच सी एल की 1998-99 की एसीटोन की थोक औसत बिक्री प्राप्ति की गणना उनके द्वारा दिए गए मात्रा संबंधी आँकड़ों के आधार पर की गई है)

(ड) भंडार

1997-98 के अन्त में प्रभावित घरेलू उत्पादकों का अन्त स्टाक 1148 मी. टन था जो 1998-99 के अन्त में घटकर 437 मी. टन रह गया । इस विषय में यह पाया गया है कि एच ओ सी और एच सी एल ने दावा किया है कि एसीटोन एक खतरनाक रसायन है जिसकी भंडारण क्षमता को विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित करवाने की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए उन्होंने अपने उत्पाद की बिक्री करके अथवा उत्पादन कम करके न्यूनतम भंडार रखा । इस स्पष्टीकरण को देखते हुए एसीटोन के भंडारण की स्थिति को उनकी गंभीर क्षति की सच्ची तस्वीर नहीं माना जा सकता ।

(घ) रोजगार

घरेलू उत्पादकों ने कहा है प्रतिमाशाली, अनुमती और योगदान देने वाले कर्मचारियों ने कम्पनियों की सेवाओं से त्यागपत्र देने शुरू कर दिए हैं जिससे घरेलू उद्योग के ज्ञान और कौशल की अपूरणीय क्षति हुई। नयी प्रतिमाओं को आकर्षित करने में भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको शिथिल एसीटोन उद्योग में प्रगति के लक्षण नहीं दिखायी पड़ रहे हैं। इस विषय में यह पाया गया है कि एच ओ सी के एसीटोन संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1995-96 में 474 से घटकर 1998-99 में 447 रह गई तथा एच सी एल में उनके एसीटोन संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1995-96 में 82 से घटकर 1998-99 में 61 रह गई।

(छ) उत्पादकता

प्रभावित घरेलू उत्पादकों का उत्पादन 1997-98 में 42358 मी. टन से घटकर 1998-99 में 41222 मी. टन हो गया तथा उनकी उत्पादकता में भी कमी आई जैसे कि उनके द्वारा रखे गए प्रति कर्मचारी द्वारा उत्पादन की मात्रा जो कि 1997-98 में 82.89 मी. टन प्रति कर्मचारी से घटकर 1998-99 में 81.15 मी. टन प्रति कर्मचारी रह गई।

(ज) लामांश

एच ओ सी और एच सी एल ने कहा है कि उन्होंने एसीटोन की घरेलू कीमत निश्चित करने के लिए एसीटोन की उतराई के समय की अनुमानित लागत के आधार पर ही निश्चित करने की नीति को अपनाया है। वर्धित आयातों के परिणामस्वरूप और आयात कीमतों में गिरावट के कारण उन्हें अपने ग्राहकों को पूरी तरह आयातों पर जाने से रोकने के लिए अपने एसीटोन की कीमतों में विभिन्न समायोजन करने पड़े। औसत रूप में, उन्होंने अपना मार्च 1998 में बिक्री मूल्य 28/-रु० प्रति किलो से घटाकर मार्च, 1999 में 18/-रु० प्रति किलो कर दिया जो कि सूची मूल्य में लगभग 36% की गिरावट है। एच सी एल की एसीटोन की (थोक में) कुल वसूली जो कि 1998-99 की पहली तिमाही में 25883/-रु० प्रति मी. टन थी वह 1998-99 की आखिरी तिमाही में 17787/-रु० प्रति मी. टन तक गिर गई जो 8000/-रु० प्रति मी. टन से भी अधिक की गिरावट है। एच ओ सी के मामले में 1998-99 की पहली तिमाही में उनकी शुद्ध वसूली 22626/-रु० प्रति मी. टन से घटकर 1998-99 की आखिरी तिमाही में 15230/-रु० प्रति मी. टन हो गई जो कि 7000/-रु० प्रति मी. टन से भी अधिक की गिरावट है। एच ओ सी और एच सी एल की शुद्ध वसूली में कमी से उनका लामांश गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और दोनों को हानि होनी आरम्भ हो गई क्योंकि एसीटोन की कीमतों में कमी, कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के बराबर नहीं थी।

(ii) कुछ पक्षों ने दावा किया है कि रक्षोपाय की कार्यवाहियाँ उत्पाद विशेष कार्यवाहियाँ हैं और इसलिए एच ओ सी और एच सी एल के लामांश केवल वहीं तक माना जाना चाहिए जहाँ तक उसका संबंध एसीटोन उत्पादन से हो। यह एक वैध तर्क है। एच ओ सी और एच सी एल दोनों ने अपने एसीटोन विशेष के उत्पादन लागत तथा वसूली इत्यादि के विवरण प्रस्तुत किए हैं जिनका भी सत्यापन किया जाना है यह पाया गया कि एच ओ सी और एच सी एल दोनों ने 1998-99 में गंभीर हानि उठाई तथा 1998-99 के बाद की अवधि में हानि उठाई।

(iii) एच ओ सी और एच सी एल को अपने एसीटोन के ग्राहकों को अधिक ऋण अवधि देने के लिए भी बाध्य होना पड़ा । 1998-99 के बाद दोनों ही कम्पनियों के कर्जदारों में काफी वृद्धि हुई जिससे कार्यरत पूंजी चक्र में बाधोत्तरी हुई जिसने नकदीकरण की स्थिति को प्रभावित किया । उनको बाजार दरों से भी काफी उच्च दरों पर इण्टर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में पैसा उधार लेना पड़ा जिससे उनके लामांश में और नुकसान हुआ । एसीटोन की नीची कीमतों के साथ-साथ उनकी साख दर के लिए उनके कार्य निष्पादन मानदंड भी गिर गए जिसने उचित लागत पर धन प्राप्त करना और अधिक मुश्किल कर दिया जिससे भविष्य में उनके लामांश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ब्याज के लागत संघटक उच्च हो जाएंगे । लामांश में हानि का प्रभाव दोनों कम्पनियों की शेयर की कीमतों पर भी पड़ा जो 1998-99 में बी एस ई सेन्सेक्स से भी तीव्र गति से कम हुआ । नकदीकरण की कमी तथा लामांश में कमी के कारण दोनों कम्पनियों को वित्तीय संस्थानों से धन लेने में कठिनाई हो रही है । इस प्रकार इससे ग्रीनफील्ड एसीटोन क्षमताओं के विनिर्माण हेतु उन्हें लम्बी अवधि की योजनाएँ लागू करने में विलम्ब हो रहा है ।

(iv) एच ओ सी और एच सी एल के लामांश के संदर्भ में कुछ पक्षों ने कुछ प्रेस रिपोर्टों का हवाला दिया है । अप्रैल, 1999 के बिजनेस लाइन ने कहा है कि हाल ही में पूरे हुई क्लोरालकली तथा हाइड्रोजन पराक्साइड योजनाओं के कारण अवमूल्यन एवं उच्च ब्याज दर के कारण, एच ओ सी का लामांश दबाव में रहा है । 8 जुलाई, 1999 को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने एच ओ सी के उत्पादन में 70% की, बिक्री में 16% की तथा क्षमता उपयोग में 4% की वृद्धि के बारे में रिपोर्ट छपी है । एच सी एल के संदर्भ में 20 जून, 1999 के बिजनेस लाइन्स ने रिपोर्ट छपी है कि कम्पनी, विश्वव्यापी वस्तुओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा माग और आपूर्ति के असन्तुलन के कारण निरन्तर झूबती जाएगी तथा विश्वव्यापी वस्तुओं की कीमतों का उतार चढ़ाव पर घरेलू संरचना संबंधी कठिनाइयों के कारण और भी बुरा प्रभाव पड़ा है । अन्य श्रेणी की कम्पनियों अथवा सहायक कम्पनियों का एच सी एल पर प्रभाव के विषय में भी रिपोर्ट में कहा गया है । उन्होंने तर्क दिया है कि एच ओ सी तथा एच सी एल दोनों कम्पनियों के लामांश में हानि प्रेस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के कारण है तथा इस हानि को दोनों कम्पनियों के एसीटोन संचालन का कारण नहीं समझा जाना चाहिए । इस विषय में यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इन दोनों कम्पनियों के एसीटोन संचालन से संबंधित लामांश को ही वर्तमान जौंच के लिए संगत माना जाना चाहिए न कि उनके समस्त लामांशों पर विचार किया जाना चाहिए । प्रेस रिपोर्ट में एच ओ सी तथा एच सी एल के समस्त संचालनों का हवाला दिया गया है न कि केवल एसीटोन के लिए । तथापि वर्तमान जौंच में पाये गए निष्कर्ष केवल एसीटोन विशेष के तथ्यों पर आधारित है ।

(v) कुछ पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदकों ने अतीत में बहुत अधिक लाभ कमाया है और इसलिए अब यदि उनको क्षति हो रही है तो उनको क्षति के विरुद्ध शिकायत नहीं करनी चाहिए । पिछले लाभों को देखते हुए वर्तमान क्षति के संदर्भ में यह पाया गया है कि क्षति के निर्धारण हेतु विभिन्न कारणों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ आधार पर किया जाना चाहिए । यदि यह प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को अगर अपूरणीय महत्वपूर्ण हानि हो रही है तो गंभीर क्षति के अस्तित्व का निर्धारण कर दिया जाना चाहिए । यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वर्तमान जौंच गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण से संबंधित है, अर्थात् एक स्थिति जहाँ गंभीर क्षति स्पष्टतः आसन्न हो । इसलिए लाभों का हानि में परिवर्तित होने को उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जांचा जाना चाहिए तथा गंभीर क्षति की आशंका के अस्तित्व के निर्धारण के रास्ते में, अतीत के लाभ को नहीं आने चाहिए ।

(इ) गंभीर क्षति की आशंका

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी की उप धारा 6 (डी) की परिभाषा के अनुसार गंभीर क्षति की आशंका का अर्थ है एक स्पष्ट तथा आसन्न गंभीर क्षति का खतरा तथा इस धारा की उप धारा 6 (सी) की परिभाषा के अनुसार गंभीर क्षति का अर्थ है वह क्षति जो एक घरेलू उद्योग की स्थिति में कुल मिलाकर महत्वपूर्ण अपूरणीय क्षति उत्पन्न करे। जैसा ऊपर विचार किया जा चुका है, विभिन्न मानदंडों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि 1998-99 में "प्रभावित घरेलू उत्पादकों" को गंभीर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। 1997-98 की तुलना में उन्होंने उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री प्राप्ति, उत्पादकता तथा लाभों में नुकसान उठाया है। उन्होंने बिक्री में कुछ वृद्धि प्राप्त की लेकिन वह आभासी उपयोग में वृद्धि से बहुत कम थी और वह भी विक्रय मूल्य में तेजी से कमी करने के आधार पर थी। इस प्रकार घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति स्पष्ट रूप से आसन्न है। इसलिए यह पाया गया कि घरेलू उद्योग को एक गंभीर क्षति की आशंका है।

6. क्षति का कारण

(क) मांग और पूर्ति में अन्तर

(i) विभिन्न पक्षों द्वारा बढ़ते हुए आयात को न्यायसंगत ठहराते हुए अथवा घरेलू उद्योग को वर्धित आयात से नहीं बल्कि अन्य कारकों से क्षति हुई है, आदि अपने को मुद्दे उठाए गए हैं। इन मुद्दों में से अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है आपूर्ति-मांग में अन्तर। कुछ पक्षों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण वर्धित आयात नहीं था क्योंकि घरेलू आपूर्ति तथा घरेलू मांग में अन्तर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक था। यह कहना उचित होगा कि एच सी.एल. जो भारत में एसीटोन उत्पादन करने वाली पहली इकाई थी, आरम्भ में 8000 मी.टन एसीटोन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ 1968 में स्थापित की गई थी। 1979 में इसने 12000 मी.टन प्रतिवर्ष की क्षमता के विस्तारीकरण के लिए अनुरोध किया था लेकिन उनका अनुरोध सरकार द्वारा 28-7-1980 को उस समय प्रचलित कानून के अनुसार यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि एच सी.एल. का ई.आई.डी.पैरी के साथ अन्तःसम्बन्ध होने के कारण एक बड़ा उपक्रम था, तथा भारतीय बाजार में उनका प्रभुत्व था। अतः एच सी.एल. जब तक एम.आर.टी.पी. के बन्धन से मुक्त नहीं होता है उसके बड़े विस्तारीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता था। एच सी.एल. ने एम.आर.टी.पी. से पंजीकरण समाप्त करवाने के लिए कई वर्षों तक प्रयास किया लेकिन बड़ा विस्तारीकरण अथवा नई परियोजनाओं से संबंधित एम.आर.टी.पी. अधिनियम (1991 में) की संगत धाराओं के समाप्त होने से पहले सफल नहीं हो पाया, फिर भी, एच सी.एल. ने पूर्णतः आन्तरिक जमा के माध्यम से प्राप्त धन द्वारा अवरोधों को दूर करने हेतु पूंजी का निवेश करके 1994-95 में 12000 मी.टन प्रति वर्ष की अपनी एसीटोन की प्रभावी क्षमता में धीरे-धीरे वृद्धि की। क्षमता को फिर से 1995-96 में 14400 मी.टन प्रति वर्ष तथा 1996-97 में 16170 मी.टन प्रति वर्ष तथा 1998-99 में 18300 मी.टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया है। एच.ओ.सी. के मामले में 1994-95 में एसीटोन की प्रभावी क्षमता 24640 मी.टन प्रति वर्ष से बढ़कर 1997-98 में 27650 मी.टन प्रति वर्ष हो गई। अन्य दो इकाइयों कृष्णा तथा राजाराम (वाल्वा) में प्रत्येक की एसीटोन की 4500 मी.टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता है। इस प्रकार, 1998-99 में "प्रभावित घरेलू उत्पादकों" की 54950 मी.टन प्रतिवर्ष की प्रभावी एसीटोन क्षमता थी जो कि घरेलू उद्योग को उपलब्ध थी। उन्होंने 1998-99 में सामूहिक रूप से 41222 मी.टन एसीटोन का उत्पादन किया जो कि 1998-99 में 75% क्षमता उपयोग माना गया। 1998-99 के दौरान एसीटोन की 72483 मी.टन की स्पष्ट खपत थी। गत वर्षों में, हालांकि, 1994-95 में 49801 मी.टन, 1995-96 में 87335 मी.टन, 1996-97 में 83888 मी.टन तथा 1997-98 में 59842 मी.टन एसीटोन की स्पष्ट खपत थी।

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 1994-95 की तुलना में 1995-96 में एसीटोन की स्पष्ट खपत की पर्याप्त वृद्धि हुई लेकिन उसके पश्चात 1996-97 तथा 1997-98 में उसमें गिरावट आई। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से एक वर्ष विशेष में वास्तविक मांग को नहीं दर्शाते क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों से अधिकतम फायदा उठाने के लिए अधिक आयात तथा स्टॉक को आगे लाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह उचित समझा गया कि इस अवधि में आभासी खपत का औसत लिया जाए जो 60188 मी. टन प्रति वर्ष निकलता है। इसकी तुलना में 1998-99 में आभासी खपत 72483 मी. टन थी जो कि 1994-98 के दौरान औसत आभासी खपत से 20.5% अधिक निकलती है। 1997-98 की तुलना में 1998-99 की आभासी खपत 21.1% अधिक निकलती है। घरेलू एसीटोन की खपत में इतनी बढ़ोत्तरी पर न ही किसी ने ध्यान दिया है और न दावा किया है मैसर्स कीसेंट आर्गेनिक्स लिमिटेड ने यह दावा किया है कि भारत में वास्तविक एसीटोन के उपभोग का प्रतिरूप डा. अजीत जोशी तथा पंकज दत्ता द्वारा एक लेख "एसीटोन - ए टेक्नो कामर्शियल प्रोफाइल" जो केमिकल वीकली के 17 दिसम्बर, 1998 के अंक में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल एसीटोन की वास्तविक खपत 1985-86 में 29000 मी. टन का उल्लेख है, जो बढ़कर 1990-91 में 48000 मी. टन, 1994-95 में 54000 मी. टन तथा 1999-2000 में अनुमानित मांग 64750 मी. टन है। प्रस्तुत आँकड़ों से यह पाया गया है कि 1985-86 से 1990-91 के दौरान एसीटोन की खपत में औसतन 10.6% प्रति वर्ष (निश्चित) वृद्धि हुई। वृद्धि हालांकि 1990-91 से 1994-95 के दौरान लगभग औसतन 3% प्रति वर्ष (निश्चित) घटी। रिपोर्ट के अनुसार 1994-95 से 1999-2000 के बीच बढ़ोत्तरी लगभग 3.7% प्रति वर्ष (निश्चित) होती है। रिपोर्ट के अनुसार 1998-99 में एसीटोन की खपत 62440 मी. टन होनी चाहिए थी। तथापि मैसर्स कीसेंट ने उल्लेख किया है कि उपलब्ध प्रकाशित आँकड़े रूढ़िवादी आकलन पर आधारित हैं। 1998-99 में 62440 मी. टन की इस गणना की तुलना में आवेदकों ने 1998-99 में 68749 मी. टन एसीटोन की वास्तविक खपत का दावा किया है। फिर भी उन्होंने इस आँकड़े की गणना गत रुझान के आधार पर केवल वाग्विस्तार द्वारा (तथा माल शेष प्रणाली का प्रयोग किया)। उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि 68749 मी. टन का आँकड़ा 1998-99 के दौरान एसीटोन उपभोग का एक अधिक ग्यार्थ आकलन है।

(ii) 1998-99 में 68749 मी. टन के उपभोग के वास्तविक आँकड़े में नोसिल की 12000 मी. टन एसीटोन की अनुमानित आवश्यकता भी सम्मिलित है। नोसिल के पास स्वयं 14000 मी. टन प्रति वर्ष की प्रभावी एसीटोन क्षमता है। "प्रभावित घरेलू उत्पादकों की 1998-99 में कुल 54950 मी. टन प्रति वर्ष की प्रभावी एसीटोन क्षमता थी। नोसिल की क्षमता को भी सम्मिलित करके "प्रभावी एसीटोन क्षमता" 68950 मी. टन रही होगी। कुछ समय पहले नोसिल स्वयं एसीटोन के एक बड़े उत्पादक थे। यद्यपि उन्होंने अपना उत्पादन बहुत अधिक कम कर दिया और आयातित एसीटोन के एक बड़े उपयोगकर्ता में परिवर्तित हो गए। इसलिए प्रभावित घरेलू उत्पादकों द्वारा नोसिल की आवश्यकताओं का शामिल करने की आशा करना उचित नहीं होगा। नोसिल की आवश्यकता को निकाल कर, प्रभावित घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध 54950 मी. टन की प्रभावी एसीटोन क्षमता की तुलना में 1998-99 में घरेलू माँग 56750 मी. टन निकलती है जो कि घरेलू माँग के लगभग बराबर ही है।

(iii) किसेंट आर्गेनिक्स लिमिटेड ने अल्कोहल आधारित एसीटोन उत्पादकों की अकुशलता के विषय में विस्तारपूर्वक निरूपण किया है। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का निष्कर्ष भी प्रस्तुत किया है तथा अल्कोहल रूट आदि के माध्यम से एसीटोन के उत्पादन की लागत के विषय में आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस विषय में यह पाया गया है कि अल्कोहल रूट द्वारा किए गए एसीटोन के उत्पादन की लागत की गणना बाजार में अल्कोहल की कीमत को

आधार बना कर की गई है। यह कृष्णा और राजाराम (वाल्वा) के विषय में संगत प्रतीत नहीं होती जिनमें से दोनों चीनी की मिलें हैं और अल्कोहल/एसीटोन उत्पादन की उनके पास आन्तरिक सामर्थ्य है। इन इकाइयों के लिए अनेकों कारक जैसे माछा, बिक्री कर इत्यादि संगत नहीं होंगे और उनकी उत्पादन लागत बहुत कम होगी। इसके अलावा इन इकाइयों के पास पहले से ही एसीटोन संयंत्र विद्यमान हैं और एसीटोन के उत्पादन के लिए इन संयंत्रों को चलाने के लिए उनकी अपनी अनिवार्यता तथा वचन बढ़ताएँ हो सकती हैं। संयंत्रों को चलाने अथवा न चलाने का विकल्प उनके अपने पास है। जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के पश्चात् यदि उन्होंने अपनी इच्छानुसार उत्पादन करने का निश्चय कर लिया है तो यह उनका अपना निर्णय है जिसका सम्मान करने और जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतीत में उन्होंने अपने एसीटोन संयंत्र संचालित किए और पर्याप्त मात्रा में एसीटोन का उत्पादन किया। अतः अब यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यदि एक बार रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर दिया गया तो वे दुबारा ऐसा नहीं करेंगे।

(iv) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि आवेदकों ने धीरे-धीरे अपनी उत्पादन क्षमता 1994-95 में 36640 मी. टन प्रतिवर्ष से 1998-99 में 45950 मी. टन प्रतिवर्ष उच्चिकृत कर ली थी अर्थात् 1994-95 को देखते हुए 1998-99 में लगभग 25% का सुधार है। फिर भी, वे अपनी उत्पादन क्षमता का प्रयोग पूरी तरह नहीं कर पाए तथा 1998-99 में केवल 41222 मी. टन उत्पादन करने के लिए बाध्य थे। आवेदकों ने विगत में 100% से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त किया था। 1995-96 में आवेदकों ने 102% क्षमता उपयोग प्राप्त किया था। 1998-99 में भी उनके पास उपलब्ध प्रमाणी क्षमता का वे इस्तेमाल कर सकते थे। एच.सी.एल. तथा एच.ओ.सी. ने, तिमाही आधार पर, 1998-99 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तिमाही में क्रमशः 7811, 12169, 10177 और 11071 मी. टन का उत्पादन किया। अपनी उत्पादन सुविधाओं आदि को सुधारने के लिए आवेदकों द्वारा कुछ समय के लिए अपने संयंत्र बन्द करने के कारण पहली तिमाही में उनका उत्पादन कम हुआ होगा। दूसरी तिमाही में फिर भी उन्होंने 12169 मी. टन का उत्पादन किया। अनुपात के आधार पर, वे 44318 मी. टन $(7811 + 12169 \times 3)$ का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल 41222 मी. टन का उत्पादन किया। अतः आवेदकों ने 3000 मी. टन के उत्पादन को खो दिया तथा अन्य दो इकाइयों, कृष्णा और राजाराम (वाल्वा) ने एसीटोन का कुछ भी उत्पादन नहीं किया। अतः यह कहना सही नहीं है कि घरेलू उत्पादक घरेलू माँग पूरी करने के लिए अधिक एसीटोन के उत्पादन के लिए सक्षम नहीं थे, और यह कि जो भी आयात हुआ वह घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू माँग पूरी न करने के कारण हुआ था। इसके विपरीत सस्ते आयात ने घरेलू उत्पादकों को सम्पूर्ण क्षमता उपयोग प्राप्त करने से रोका तथा घरेलू बाजार में एसीटोन की कीमत में मन्दी भी उत्पन्न की।

(ख) निर्यात की हानि

यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग की विपत्ति का कारण इसके निर्यात बाजार का खोना है जो 1996-97 में 2263 मी. टन तथा 1997-98 में 333 मी. टन की तुलना में 1998-99 में 26 मी. टन तक गिर गया, न कि एसीटोन का आयात। इस विषय में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि एसीटोन उत्पादन के उत्पादन का तरीका घरेलू खपत तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए समान है। एक उद्योग जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की तो उससे उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, विशेषकर उस समय जब घरेलू उद्योग के लिए घरेलू आपूर्ति मुख्य बाजार था तथा निर्यात इसके बाजार का केवल एक अंश मात्र ही था। इसलिए वर्धित आयात के कारण घरेलू उत्पादकों को हुई हानि का प्रभाव घरेलू

उत्पादकों के निर्यात कार्य पर भी पड़ा। फिर भी घरेलू उत्पादकों ने 1997-98 में 2250 मी. टन तथा 1998-99 में 2272 मी. टन की डीम्ड निर्यात योजना के अन्तर्गत एसीटोन की आपूर्ति की, जिसे भारतीय तटों से वास्तव में बिना माल गए, निर्यात माना गया है। इसलिए यह तर्क उचित नहीं है।

(ग) आयात द्वारा अधिग्रहीत बाजार शेयर

(i) "प्रभावित घरेलू उत्पादकों" का 32978 मी. टन का बाजार शेयर था अर्थात् 1994-95 में 49601 मी. टन की कुल आमासी खपत में 66.5%। उनका बाजार शेयर 1997-98 में 69.1% बढ़ने से पहले 1995-96 में 61.4% तथा 1996-97 में 53.1% नीचे आ गया और 1998-99 में फिर से 57.8% तक नीचे गिर गया। इस अवधि में आमासी खपत में आयात का शेयर 1997-98 में 33.5% से 1995-96 में 38.1% तथा 1996-97 में 46.7% बढ़ गया था जो कि 1997-98 में 30.9% गिर गया लेकिन 1998-99 में फिर से 42.2% की ऊँचाई तक वृद्धि हुई। तुलनात्मक आधार पर, 1997-98 की तुलना में 1998-99 में आयातों के शेयर में लगभग 36.6% की वृद्धि हुई जब कि घरेलू बिक्री का शेयर लगभग 19.6% तक गिर गया। निम्नलिखित सारणी 1994-95 के पश्चात घरेलू उत्पादकों का बाजार शेयर दर्शाती है -

सारणी - 7

आमासी खपत में आयात का शेयर

वर्ष	घरेलू बिक्री मी. टन	कुल आमासी खपत मी. टन	आमासी खपत में घरेलू बिक्री का शेयर (%)	आमासी खपत में आयातों का शेयर (%)
1994-95	32978	49601	66.5	33.5
1995-96	41660	67335	61.9	38.1
1996-97	34022	63886	53.3	46.7
1997-98	41365	59842	69.1	30.9
1998-99	41907	72483	57.8	42.2

कुल आयात आँकड़ों में नोसिल द्वारा आयात के आँकड़ों भी सम्मिलित हैं जिन्होंने इस जॉब में एसीटोन के उत्पादकों के बदले एक आयातकों के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। एसीटोन की माँग और आपूर्ति की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अनुप्रवाही पदार्थों के विनिर्माण में एसीटोन के प्रयोग की उनकी माँग तथा उनकी एसीटोन की क्षमता के बारे में विचार नहीं किया गया है। इसलिए नोसिल द्वारा किये गये आयात को छोड़कर आयातित एसीटोन द्वारा बाजार शेयर पर आधिपत्य का विश्लेषण करना लाभदायक होता। इसीलिए उनसे उनके द्वारा आयातित एसीटोन के आँकड़ों प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए। इसलिए इन आँकड़ों की अनुपस्थिति में यह विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

(ii) 1997-98 में कुल आमासी खपत 59842 मी.टन थी जो 1998-99 में 21.1% बढ़कर 72483 मी.टन हो गई। तथापि घरेलू बिक्री में उसी गति पर वृद्धि नहीं हुई। इस अवधि के दौरान "प्रभावित घरेलू

उत्पादक जिन्हे घरेलू बाजार में इस अवधि के दौरान 50093 मी. टन की (41365x121.1%) बिक्री करना चाहिए था (इसमें एच ओ सी द्वारा डीम्ड निर्यात के आधार पर किया गया 2272 मी.टन शामिल है) केवल 41907 मी टन एसीटोन की ही बिक्री कर सके । इस प्रकार घरेलू उत्पादकों को 8186 मी.टन की बिक्री की हानि हुई जिसे वर्धित आयात ने हथिया लिया जिसने कि कुल आमासी खपत में 21.1% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 9111 मी टन (29182-16574x121.1%) के अतिरिक्त बाजार पर कब्जा कर लिया ।

(घ) आयात के मूल्य

(i) कुछ पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने सस्ते आयात की शिकायत की और यदि उनको हुई क्षति, आयात के मूल्यों के कारण हुई है तो इसका उपचार कुछ और है, रक्षोपाय कार्रवाई नहीं । तथापि यह तर्क उचित दिखता नहीं पड़ता । सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 बी, जो कि केन्द्रीय सरकार को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, में अनुबद्ध है कि, "यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी जाव, जिसे वह उचित समझे, के पूरी होने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि भारत में इसकी बिक्री हुई मात्रा में आयातित कोई माल और ऐसी परिस्थितियों के अधीन आयातित हुआ है जो कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण या क्षति की आशंका का कारण है, तो वह भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर सकती है " । इस धारा के सामान्य अध्ययन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उन परिस्थितियों, जिनके अधीन वर्धित आयात हुआ, की रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए जाँच किया जाना आवश्यक है और इसलिए भारत ने जिस मूल्य पर आयात हुआ, उन मूल्यों पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि मूल्य एक ऐसा मुख्य महत्वपूर्ण कारक होता है जिस पर स्वतंत्र माल हेतु निर्णय लेने से पूर्व विचार करना आवश्यक है । इसके अलावा रक्षोपाय शुल्क के अनुलग्नक में अर्पित है कि "जब उसी समय वर्धित आयात के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं तो इस प्रकार की क्षति वर्धित आयात से नहीं मानी जाएगी । इस प्रकार के मामले में, महानिदेशक इस शिकायत को, एण्टी-डम्पिंग प्राधिकारी या काउण्टरवेलिंग शुल्क जाँच के लिए जैसा वे उचित समझे, भेज सकते हैं । इस प्रावधान के अनुसरण में भी जिन मूल्यों पर भारत में आयात हुआ, उन मूल्यों पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है, यह पता लगाने हेतु कि क्या डम्पिंग या आर्थिक अनुदान जैसे कारक विद्यमान हैं या नहीं । इसलिए वे मूल्य जिन पर भारत में आयात हुआ, और क्या उन मूल्यों के कारण घरेलू उद्योगों को क्षति हुई, और क्या वर्धित आयात के अलावा उस समय अन्य कारक भी विद्यमान थे, का परीक्षण करना आवश्यक समझा गया है ।

(ii) भारत में आयातित एसीटोन डम्प किया गया या सम्सीटाइज किया गया, ऐसे किसी साक्ष्य की बात तो दूर, आवेदकों या किसी पक्ष द्वारा ऐसा दृढतापूर्वक कहा भी नहीं गया है । सारणी 2 में दिए गए आयात आंकड़ों से यह पाया गया है कि 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान औसतन आधार पर आयातित एसीटोन की उततराई के समय की लागत (सी आई एफ+ आयात शुल्क) 1994-95 में 22200 रु० प्रति मी. टन (13454x1.65), 1995-96 में 33610 रु० प्रति मी. टन (22407x1.5), 1996-97 में 24805 रु० प्रति मी टन (17718x1.4) 1997-98 में 30698 रु० प्रति मी टन (22739x1.35) और 1998-99 में 18698 रु० प्रति मी. टन (13850x1.35) थी । इस अवधि के दौरान भारत में एसीटोन का आयात और उततराई के समय की लागत भी घटे सारणीबद्ध है ।

सारणी 8
आयात की उतराई के समय की लागत

वर्ष	आयात मी. टन	औसतन सी आई एफ (रु)	उतराई के समय की लागत (औसतन)रु./मी.टन
1994-95	9046	13454	22200
1995-96	18519	22407	33610
1996-97	26228	17718	24805
1997-98	18574	22739	30698
1998-99	29182	13850 x	18698

(x 1998-99 के आयात आंकड़ों से गणना की गयी)

आलेखक और कुछ प्रतिवादी दोनों ने आई सी आई एस एल ओ आर के आंकड़ों को विश्वसनीय माना है जिनके अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए आयातित एसीटोन का औसत मूल्य 1994 में 488 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन, 1995 में 820 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन, 1996 में 427 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन, 1997 में 433 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन 1998 में 360 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन और 1999 की प्रथम तिमाही में 265 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन था । इस प्रकार कीमतें 1995 में 820 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन तक बढ़ने के पश्चात वर्ष दर वर्ष कम हो रही हैं । तथापि आयातित एसीटोन की उतराई के समय लागत उसी प्रकार की प्रवृत्ति का ठीक प्रकार से अनुसरण विभिन्न कारकों जैसे विनियम दर और आयात शुल्क की दर आदि में परिवर्तन होने के कारण नहीं कर सकी । आयातित एसीटोन की उतराई के समय की लागत 1995-96 में 33610 रु० प्रति मी. टन तक बढ़ी और 1996-97 में 24805 रु० प्रति मी. टन तक कम हो गयी । उतराई के समय की लागत में कमी के साथ, आयात 1995-96 में 18519 मी.टन से 1996-97 में 26228 मी. टन तक बढ़ा । अगले वर्ष अर्थात् 1997-98 में आयात की उतराई के समय की लागत 30698 रु० प्रति मी. टन तक बढ़ी और आयात 18574 मी. टन तक कम हुआ । 1998-99 में उतराई के समय की लागत 18698 रु० प्रति मी. टन तक कम हुई और आयात 29182 मी. टन तक ऊपर पहुँच गया । इसलिए यह पाया गया है कि भारत में एसीटोन के आयात की मात्रा उतराई के समय की लागत पर निर्भर थी और सस्ते आयात ने घरेलू उत्पादकों को अपने मूल्य कम करने के लिए बाध्य कर दिया । घरेलू उत्पादकों ने प्रस्तुत किया है कि एसीटोन की अनुमानित उतराई के समय की लागत के साथ घरेलू मूल्यों की बराबरी के लिए उन्हें मूल्यों में कई प्रकार के समायोजन करने पड़े थे । एसीटोन की सूची मूल्य कम करने के अलावा, घरेलू उत्पादकों को अपने उपभोक्ताओं को आयात की ओर पूर्णतया स्थानांतरित होने से बचाने के लिए विभिन्न अतिरिक्त छूट देना पड़ा ।

(iii) एक अन्य तर्क जो कि आयातित एसीटोन के मूल्यों के संदर्भ में कुछ पक्षों द्वारा दिया गया है वह एसीटोन मूल्यों की चक्रीय प्रकृति है । उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विश्व स्तर पर रसायन उद्योग एक चक्रीय उद्योग है जो एक नियतकालिक उतार-चढ़ाव से युक्त है और यह चक्रीय प्रवृत्ति विभिन्न कारकों पर निर्भर है जो कि विश्वव्यापी बाजार के संदर्भ में सम्पूर्ण मांग और आपूर्ति की स्थिति को प्रभावित करती है । इस संबंध में नीचे दी गई सारणी में जुलाई 1994 से मार्च 1999 की अवधि के दौरान एसीटोन के सी आई एफ मूल्यों का अमेरिकी डालर में विवरण दर्शाया गया है ।

सारणी ७
एसीटोन के सी आई एक मूल्य

मास	अमेरिकी स्रोत से सी आई एक	यूरोपीय स्रोत से सी आई एक	सुदूर पूर्व एशिया	सी आई एक भारत
जुलाई, 1994	437	392		490
नवम्बर, 1994	767	798		800
मई, 1995	909	840		880
जुलाई, 1995	926	856		850
अक्तूबर, 1995	909	701		725
मार्च, 1996	554	470		490
मई, 1996	442	420		490
अगस्त, 1996	365	360		380
नवम्बर, 1996	348	360		380
मार्च, 1997	403	403		400
मई, 1997	415	437		440
जून, 1997	435	465		440
सितम्बर, 1997	552	522		470
नवम्बर, 1997	588	559	570	530
जनवरी, 1998	595	625	560	480
फरवरी, 1998	540	608	540	470
मार्च, 1998	461	550	480	450
अप्रैल, 1998	410	480	465	450
मई, 1998	360	465	390	360
जून, 1998	340	445	385	340
जुलाई, 1998	300	440	350	305
अगस्त, 1998	283	420	340	275
सितम्बर, 1998	273	270	335	260
अक्तूबर, 1998	270	260	300	260
नवम्बर, 1998	270	255	295	260
दिसम्बर, 1998	270	275	290	260
जनवरी, 1999	266	275	292	260
फरवरी, 1999	270	280	295	250
मार्च, 1999	270	285	297	240

(स्रोत - आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए)

उपरोक्त सारणी में आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अमरीकी डालर प्रति मी. टन में एसीटोन के सी आई एफ मूल्यों में 1994 के अंत में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हुई और जो 1995 में अपनी चरम सीमा पर थे । उसके पश्चात मूल्य कम होने शुरू हो गए और मार्च 1999 में 240 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के स्तर तक पहुँच गए । इस बीच में 1997 की दूसरी छमाही और 1998 के आरंभ के दौरान कुछ हद तक मूल्य बढ़े । तथापि यह वृद्धि मध्य 1995 में प्रचलित चरम मूल्यों से बहुत कम थी । जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, एसीटोन के सी आई एफ मूल्यों में परिवर्तन यह समर्थन नहीं करता कि आयातित एसीटोन में कोई चकीय विभिन्नता थी । इसके अलावा, गत प्रवृत्तियों मविष्य के व्यवहार हेतु कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विश्वव्यापी परिदृश्य लगातार परिवर्तित होता रहा है । क्षति का सामना करने वाले घरेलू उद्योगों को भी चकीय परिवर्तन की प्रतीक्षा करके स्वयं की रक्षा करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता । यदि घरेलू उद्योगों को हुई गंभीर क्षति को समय पर सुधारा नहीं जाता और बढ़ते हुए आयात मूल्यों की दया पर छोड़ दिया जाता है, तो घरेलू उद्योगों का पुनरुद्धार कठिन या असंभव हो सकता है ।

(iv) कुछ पक्षों ने एसीटोन के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों में अभी हाल ही के सुधार के परिप्रेक्ष्य में रक्षोपाय शुल्क की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया है । उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि मध्य 1999 में आयातित एसीटोन के मूल्य लगभग 450 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के स्तर तक बढ़े । 450 अमरीकी डालर का यह दावा अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाई पड़ता है क्योंकि आवेदकों ने सितम्बर 1999 के दौरान भारत में 310 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के सी आई एफ मूल्य पर वास्तविक आयात के बारे में उल्लेख किया है । उन्होंने 284.74 अमरीकी डालर प्रति मी. टन पर 950 मी. टन का एक परेषण एवं 834.27 अमरीकी डालर प्रति मी. टन पर 12.64 मी. टन के अन्य परेषण के अलावा 245 अमरीकी डालर प्रति मी. टन से 252 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के बीच सी.आई.एफ. मूल्यों पर अप्रैल 1999 से अगस्त 1999 के दौरान मुम्बई पत्तन के माध्यम से 3448 मी. टन एसीटोन के आयात के विवरण भी उपलब्ध कराए हैं । आवेदकों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि भारत में आयात आन स्पॉट आधार पर होते हैं और इसलिए आनासी वृद्धि वाले बाजार में एसीटोन के मूल्यांकन हेतु भारत में केवल आने के समय के मूल्य ही महत्वपूर्ण एवं सगत हैं । दूसरी ओर, गिरते हुए मूल्यों की स्थिति में, बुक होने वाले आयात की बड़ी मात्रा को रोकने के लिए घरेलू मूल्यों के निर्धारण के लिए बुकिंग मूल्य समानता के साथ चलना होता है । इसलिए घरेलू उद्योग बढ़ते एवं गिरते बाजार दोनों में हानि की ओर अग्रसर हैं । इसके अलावा, इस तर्क में विभिन्न कमियाँ हैं । घरेलू उद्योगों को हुई क्षति के बारे में जॉच के नोटिस में दी गई अवधि जो कि 1994-95 से 1998-99 है, के दौरान विद्यमान तथ्यों पर आधारित है । घरेलू उद्योगों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी मानदण्डों जिनमें कि घरेलू उद्योगों द्वारा एसीटोन के उत्पादन की लागत आदि शामिल हैं, पर भी इस अवधि के लिए विचार किया गया है । आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि प्रोपिलीन और बेन्जिन के क्रय मूल्य एच.सी.एल. के मामले में जून 99 के अंत तक 15% बढ़ गए हैं । एच.ओ.सी. के मामले में कैक एल पी.जी. (प्रोपिलीन) मूल्य अप्रैल 99 और सितम्बर 1999 के शुरुआत तक 80% तक बढ़ गए हैं । इसी अवधि के दौरान बेन्जिन के मूल्य 24% एच.एल.एस.एस.एस. के मूल्य 40% तक बढ़ गए हैं । कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि का उत्पादन की लागत पर प्रभाव होगा जिसमें पर्याप्त वृद्धि होगी । यदि अनुवर्ती अवधि के एसीटोन के आयात मूल्यों पर विचार किया जाता है, तो अनुवर्ती अवधि के उत्पादन आदि की लागत पर भी विचार करना पड़ेगा । यह एक अव्यावहारिक स्थिति है और इस पर निर्भर करता है कि परिवर्तन किसका समर्थन करते हैं । विभिन्न पक्ष अधिक नवीनतम आंकड़ों को संदर्भित करने के लिए कह सकते हैं । विभिन्न पक्षों ने जॉच अवधि के दौरान विद्यमान तथ्यों पर आधारित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है एक निर्धारित अवधि को संदर्भित करना आवश्यक है, अन्यथा कोई भी सामान्य सहमति के आधार नहीं हो सकते । जॉच के शुरू होने

के तथ्यों द्वारा प्रभावित अनुवर्ती आयात की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि एसीटोन के आयात मूल्यों में वृद्धि, आवेदकों द्वारा रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग के प्रयास को निष्फल करने की प्रतिवादियों की कोशिश है। अभी हाल ही में फिनाल के लिए हुई रक्षोपाय की कार्यवाही के अपने अनुभवों को उन्होंने उद्धृत किया है जहाँ जैसे ही जॉघ शुरू की गई थी, फिनाल के मूल्य बढ़ने शुरू हो गए थे जो कि लगभग 395 अमरीकी डालर प्रति मी.टन से 415 अमरीकी डालर प्रति मी.टन तक बढ़ गए थे और जैसे ही शुल्क उद्ग्रहीत किया गया, तभी से मूल्य कम होने शुरू हो गए जो कि 415 अमरीकी डालर प्रति मी. टन से 385 अमरीकी डालर प्रति मी.टन तक और उससे भी कम हो गए। उन्होंने उल्लेख किया है कि जब वे फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क के लिए सरकार के पास गए, इच्छुक पक्षों को यह आभास हो गया होगा कि आवेदक इसी प्रकार एसीटोन के लिए भी सरकार के पास जाएंगे। किसी भी मामले में, मूल्य वृद्धि थोड़े समय तक रहने वाली है, क्योंकि फिनालकेमी - 240000 मी. टन प्रतिवर्ष, शेल - 138000 मी. टन प्रतिवर्ष और मित्सुई, सिंगापुर - 120,000 मी.टन प्रतिवर्ष आदि की नई क्षमताएँ आ रही हैं। उपरोक्त की दृष्टि में, वर्तमान कार्यवाही हेतु आयातित एसीटोन के मूल्यों में अनुवर्ती परिवर्तनों पर विचार करना संगत नहीं माना गया है।

(v) यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 240 अमरीकी डालर प्रति मी. टन का आयात मूल्य, आयातित एसीटोन का प्रतिनिधि मूल्य नहीं है। इस संबंध में, यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ये निष्कर्ष किसी एक संघालन पर आधारित नहीं है बल्कि लम्बे समय से विद्यमान आयात मूल्यों पर, रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की वांछनीयता के निर्धारण हेतु मारित औसत आधार पर, विचार किया गया है। दूसरा प्रस्तुतीकरण, जो इस संबंध में किया गया है वह यह है कि आयातित एसीटोन के मूल्यों में कमी भारत के लिए आश्चर्यजनक नहीं है और यह विश्व के अन्य हिस्सों में मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति के अनुसार थी। तथापि, यह तर्क वर्तमान जॉघ के लिए असंगत समझा गया है क्योंकि रक्षोपाय उपाय अनुचित आयात के विरुद्ध नहीं लगाए जाते बल्कि इसका उद्देश्य, यदि आयात वर्धित मात्रा और ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिससे कि घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई हो या होने की आशका हो तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है।

(vi) घरेलू उद्योगों को क्षति के संदर्भ में, नोसिल के रुख पर विचार करना भी उपयोगी है, हालांकि नोसिल ने स्वयं को भारत में एसीटोन के आयात से प्रभावित घरेलू उत्पादकों के हिस्से के रूप में विचार न किए जाने के लिए कहा है और उनके अधिकार की अवहेलना नहीं की जा सकती, फिर भी यह प्रशंसनीय है कि उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना। क्या यह क्षति की एक अभिव्यक्ति है जिसने कि उन्हें एसीटोन उत्पादन के बजाए एसीटोन आयात के लिए बाध्य किया या यह आयातित एसीटोन के मूल्यों से स्वतंत्र एक स्वैक्षिक निर्णय है। नोसिल ने 1994-95 में 7277 मी.टन, 1995-96 में 6731 मी. टन 1996-97 में 3209 मी. टन, 1997-98 में 1523 मी. टन एवं 1998-99 में 1021 मी. टन एसीटोन का उत्पादन किया। उपरोक्त तथ्यों से यह पाया गया है कि नोसिल का एसीटोन उत्पादन 1996-97 और उसके पश्चात तेजी से गिरा। पृष्ठभूमि में यह देखा जाना है कि एक ओर आयात मूल्य 1996 और 1997 में औसतन लगभग 425-430 अमरीकी डालर प्रति मी. टन से 1998 में 360 अमरीकी डालर प्रति मी. टन और 1999 की प्रथम तिमाही में 265 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक कम होना शुरू हुआ, दूसरी ओर आयात शुल्क में कमी हुई। आवेदकों ने स्पष्ट किया है कि वर्धित आयात से प्रतिस्पर्धा को मुख्यतः एल्कोहल आधारित एसीटोन विनिर्माताओं और उसके बाद आई पी ए आधारित एसीटोन उत्पादकों द्वारा बहुत गंभीरता से महसूस किया गया। नोसिल, जो कि बेन्जिन और प्रोपिलीन दोनों के उत्पादक हैं, ने एसीटोन के उत्पादन के लिए क्यूमिन कूट के बजाए आई पी ए कूट को चुना। यह शायद अपने स्त्रोतों को अन्य अधिक लाभकारी कार्यों में उपयोग करने और कैप्टिव उपयोग हेतु एसीटोन के उत्पादन के बजाए,

अनुप्रवाह उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए एसीटोन का आयात करने के नोसिल के निर्णय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। इस तथ्य से इस बात को भी समर्थन मिलता है कि नोसिल ने सुझाव दिया है कि एसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए आधार मूल्य उस स्तर पर निर्धारित किया जाए जो एसीटोन का उत्पादन करने के लिए शायद उन्हें प्रेरित करे।

(vii) कुछ पक्षों ने दावा किया है कि सारे रासायनिक उद्योगों में विश्वव्यापी मंदी आई हुई है और भारतीय रासायनिक उद्योग पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। अतः व्यापार में तथा मूल्यों में कमी केवल भारत में ही विशिष्ट नहीं है, यह दलील तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि जबकि एक ओर आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है दूसरी ओर 1998-99 घरेलू बाजार की आमासी खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू एसीटोन उद्योग की निराशाजनक स्थिति घरेलू मांग में कमी अथवा रासायनिक उद्योग में सामान्य मंदी के कारण नहीं, किन्तु सस्ती कीमतों पर एसीटोन के बड़े हुए आयात के कारण है।

(7) अन्य मुद्दे :-

(क) संयुक्त उत्पाद मूल्यांकन

यह तर्क दिया गया है कि फिनाल एवं एसीटोन संयुक्त उत्पाद हैं और इसलिए केवल एसीटोन अकेले को लेकर घरेलू उद्योगों की क्षति का आकलन, फिनाल के संबंध में स्थिति का आकलन किए बिना, उचित नहीं होगा। इस बारे में यह पाया गया है कि दोनों ही घरेलू उत्पादक अपना रेकार्ड सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी.ए.ए.पी.) के अनुसार ही रखते हैं तथा एसीटोन के संबंध में हुई क्षति जी.ए.ए.पी. के अनुसार संयुक्त उत्पाद के लिए मूल्यांकित की गई है। इसलिए फिनाल के बारे में घरेलू उद्योगों की स्थिति का मूल्यांकन वर्तमान जॉच के उद्देश्य से संगत नहीं है।

(ख) घरेलू उत्पादकों का एकाधिकार/द्वाधिकार :

(i) कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि एसीटोन के घरेलू उत्पादकों ने एकाधिकार स्थिति का लाभ उठाया है क्योंकि वे एसीटोन के घरेलू उत्पादन के 97% तक पर नियन्त्रण रखते हैं और यह कि वर्तमान शिकायत, शिकायतकर्ताओं की भारतीय बाजार में द्वाधिकार प्रभुत्व सुरक्षित एवं कायम रखने की दृष्टि से है जिससे कि वे घरेलू बाजार का शोषण जारी रख सकें। इस संबंध में यह पाया गया है कि एकाधिकार को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता बल्कि एकाधिकार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया के कारण हुई क्षति और उससे होने वाले लाभ के संदर्भ में औचित्य के बीच संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता है। एसीटोन के चार प्रभावित घरेलू उत्पादकों में से एक सी.एल. निजी क्षेत्र में है, कृष्णा और राजाराम (वालवा) सहकारी इकाइयाँ हैं और एक ओ.सी. सार्वजनिक क्षेत्र में है। एसीटोन के उत्पादन क्षमता के 50% से अधिक का अश.एच.ओ.सी. का है। इसके अलावा एसीटोन का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। कुल आमासी खपत का लगभग 40% भाग आयात द्वारा पूरा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने एसीटोन के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए अनुरोध नहीं किया है बल्कि उन्होंने विधि के अनुसार एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए प्रार्थना की है जिससे कि वे वर्धित आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति के साथ समायोजन करने योग्य बन सकें। एसीटोन की सुनिश्चित घरेलू उपलब्धता के साथ घरेलू एसीटोन उद्योगों ने अनुप्रवाह उद्योगों जैसे दवाएं, कीटनाशक,

विस्फोटक, पेंट, रबर, रसायन और अन्य अनुप्रवाह रसायन जैसे मिथाइल मेथाक्राइलेट, बिसफेनाल-ए आदि अनेक उत्पादों के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। उद्योग के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और निर्माण आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना अनावश्यक नहीं होगा कि यह स्थिति अकेले भारत के लिए विशिष्ट नहीं है। एसीटोन के भारत में वर्तमान बड़े आपूर्तिकर्ता यथा दक्षिण अफ्रीका में भी केवल एक विनिर्माता है जो एसीटोन क्षमता का 100% स्वामित्व रखता है।

(ii) यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदकों ने घरेलू एसीटोन की कीमतें एक साथ मिलकर बदल दीं। इस संबंध में आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि वे आयातित एसीटोन की उतराई के समय के मूल्य की समानता रखने का प्रयास करते हैं और रखते हैं जो कि ओ जी एल के अधीन है जो आवेदकों को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं और यदि आवेदकों में से कोई एक भी मूल्य कम करता है, तो दूसरे को भी बिक्री और बाजार शेयर की हानि को रोकन हेतु उसका तत्काल अनुसरण करना होता है। दोनों कम्पनियों का उत्पादन एक जैसा है और इसलिए उन दोनों को विभिन्न छूट आदि देकर द्वार पर सुपुर्दगी मूल्यों को उसके समान करना होता है क्योंकि दोनों कम्पनियाँ विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और एसीटोन के परिवहन पर बाधा लागत का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए इस आरोप में कोई दम नहीं है।

(ग) भारत में आयात शुल्क संरचना

कुछ पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि उदारीकरण की बढ़ती नीति के मद्देनजर, एसीटोन पर आयात शुल्क कई वर्षों में कम किया जा चुका है। मगर अभी भी इस क्षेत्र में यह सर्वाधिक है और इसलिए यह भारत के एसीटोन के विनिर्माताओं को अन्तःनिर्मित संरक्षण और प्रतिस्पर्धा की समानता उपलब्ध कराता है। तथापि, रक्षोपाय शुल्क के संदर्भ में यह तर्क असंगत माना गया है क्योंकि किसी विशेष उत्पाद पर आयात शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें कुछ हैं, तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धी उत्पादों एवं इन्पुट पर आयात शुल्क का स्तर, राजस्व उगाही की ज़रूरत और अंतराष्ट्रीय उत्पादकों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को होने वाली असुविधाएँ हैं। इस लिए प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आयात शुल्क के स्तर का निर्णय लेता है जिसे अन्य के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में नहीं देखा जा सकता। यहाँ यह उल्लेख करना भी संगत है कि एसीटोन और इसके कच्चे माल यथा बेन्जिन और प्रोपिलीन के बीच आयात शुल्क का अन्तर 1993-94 में 70% से घटकर 1994-95 में 50% तक और 1998-99 में 20% तक कम हुआ है। एसीटोन और क्यूमीन के बीच आयात शुल्क अन्तर 1993-94 में 45% से घटकर 1998-99 में 20% हो गया। इसलिए भारत में एसीटोन के आयात शुल्क, बेन्जिन और प्रोपिलीन के आयात शुल्क में कमी की तुलना में अधिक तेजी से कम हुआ जो कि 1993-94 और 1994-95 में 15% से 1995-96 में 10% तक नीचे आ गया लेकिन मार्च 1999 में 15% के स्तर पर पुनः पहुँच गया। क्यूमीन के मामले में, आयात शुल्क 1994-95 में 30% से 1998-99 में 10% तक नीचे आ गया और मार्च 1999 में 15% तक ऊपर उठ गया।

(घ) कच्चे माल का अप्रतिस्पर्धी स्रोत

कुछ पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उत्पादकों ने अपने कच्चे माल को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्राप्त नहीं किया है जो कि उनकी क्षति का एक मुख्य कारण है। उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय एसीटोन उत्पादकों को प्रोपिलीन के अप्रतिस्पर्धी मूल्य, जो कि अंतराष्ट्रीय मूल्य से 85% अधिक थे और अधिक परिवहन

लागत और 180 दिनों की ऋण सुविधा आदि के उपयोग द्वारा कम लागत पर आयात करने के बजाए क्यूमिन के अप्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन के कारण क्षति हुई। इस संबंध में, यह पाया गया है कि भारत में क्यूमिन, एल्कोहल या आई पी ए स्लट के माध्यम से एसीटोन का उत्पादन किया जाता है। आवेदक एसीटोन का उत्पादन क्यूमिन स्लट का प्रयोग करते हुए करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उनके लिए घरेलू उत्पादन पर आधारित न्याय सम्मत क्यूमिन की आवश्यकता है जिसे आयात द्वारा पूरक बनाया गया हो। क्यूमिन की परिवर्तनीय लागत आयातित क्यूमिन की उताराई के समय की लागत के साथ लगातार तुलनात्मक रूप से अनुकूल है। यह कुछ अंश तक इसलिए है क्योंकि आयातित क्यूमिन के मूल्यों पर ऊँचा लाभ मिलता है जो कि क्यूमिन के खरीददारों से वसूला जाता है और यह कि क्यूमिन के प्रत्येक आयात हेतु, मूल्य और शर्तें उपलब्ध स्रोतों से लिए जाते हैं और खरीदने का निर्णय लेने से पूर्व सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी मूल्यों को प्राप्त किया जाता है। क्यूमिन के उत्पादन की लागत से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि घरेलू उत्पादित क्यूमिन की परिवर्तनीय लागत क्यूमिन की उताराई के समय की लागत के साथ अनुकूल रूप में तुलनात्मक है। इसलिए घरेलू एसीटोन उत्पादकों द्वारा क्यूमिन की माँग का शतप्रतिशत आयात करना विवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता। प्रोपिलीन के आयात के संबंध में आवेदकों द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रोपिलीन, जो कि सामान्य तापमान एवं दबाव पर गैस अवस्था में होती है, को कृत्रिम रूप में द्रवित करना होता है जिससे कि भाड़ा बहुत अधिक हो जाता है जो कि आयात विकल्प को विशेषकर छोटे आकार के पार्सल हेतु अत्यवहार्य बनाता है। कैसे भी, प्रोपिलीन को क्यूमिन के विनिर्माण में प्रयोग किया ही जाना है और जब तक आवेदक आयातित क्यूमिन की तुलना में अनुकूल दरों पर क्यूमिन का उत्पादन करते रहे, यह नहीं माना जा सकता कि वे अपना कच्चा माल अप्रतिस्पर्धात्मक रूप में प्राप्त करते हैं।

(ज) स्वयं प्रदत्त क्षति :

यह दावा किया गया है कि आवेदकों को क्षति स्वयं प्रदत्त है क्योंकि एच.सी.एल. ने एसीटोन का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है और एच.ओ.सी. ने एक टेंडर जारी किया एवं आयात मूल्य कम कराने हेतु मोलभाव किया। इस संबंध में, यह पाया गया है कि 1998-99 के दौरान एच.सी.एल. ने लगभग 2700 मी. टन एसीटोन का आयात किया जिसमें से अधिकतर आयात, शुल्क मुक्त पात्रता के अंतर्गत निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए किया गया। 1998-99 के दौरान भारत में कुल 29182 मी. टन एसीटोन आयात किया गया और 1998-99 में एच.सी.एल. का आयात कुल आयात का 10% से कम है। पिछले वर्ष के दौरान एच.सी.एल. का आयात लगभग 4900 मी. टन था। इसलिए 1998-99 में एच.सी.एल. के आयात में पर्याप्त कमी हुई। एच.ओ.सी. द्वारा टेंडर जारी करने के संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एसीटोन के खाली होते हुए स्टाक को सहारा देने और आगामी दिनों में मानसून के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद होने की संभावना के कारण उत्पादन में अस्थायी अनिश्चितता के कारण टेंडर जारी किया गया था। उन्होंने टेंडर 500 मी. टन के लिए दिया था लेकिन 275 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की दर पर केवल 250 मी. टन ही खरीदा। ये मात्राएँ सामान्य पार्सल आकार से कम थी। सामान्यतः आयात पार्सल, आकार में अधिक बड़े होते हैं। इसलिए यह प्रतीत नहीं होता है कि एच.ओ.सी. का टेंडर या आरोपित मोलभाव का भारत में एसीटोन के आयात मूल्यों पर कोई प्रभाव था या क्षति स्वयं प्रदत्त है।

(i) अन्य क्षमताएँ जो निष्क्रिय रहीं

यह आरोप लगाया गया है कि एच.ओ.सी. तथा एच.सी.एल. ने वर्षों पहले अल्कोहल आधारित इकाइयों

को अत्यावहारिक बना दिया था। इस विषय में यह पाया गया है कि अल्कोहल आधारित एसीटोन का उत्पादन केवल भारत के लिए ही विशिष्ट नहीं है। विश्व भर में एसीटोन उत्पादन के लिए प्रयोग किये जाने वाला यह एक जाना माना तरीका है तथा इस प्रणाली द्वारा निर्मित एसीटोन दूसरे तरीकों से निर्मित एसीटोन से अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब घरेलू उत्पादक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे तो वह प्रतिस्पर्धा उनके स्वयं के बीच होगी, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को बाहरी प्रतिस्पर्धा, जो बड़े हुए आयात द्वारा उत्पन्न हुई है, से बचाना है। रक्षोपाय शुल्क को इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि घरेलू उत्पादक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से पीड़ित रहें हैं। वर्तमान जीव में यह पाया गया है कि 1998-99 में 68000 मी. टन से अधिक की घरेलू मांग थी तथा एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. दोनों ने मिलकर 41222 मी. टन का उत्पादन किया जिसमें लगभग 27000 मी. टन का अन्तर है। अल्कोहल आधारित इकाइयों की क्षमता इस माँग से बहुत कम थी। इसलिए क्यूमिन आधारित उत्पादकों ने अपने बाजार को जाने नहीं दिया लेकिन उस अन्तर को आयात में पूरा किया। दो अल्कोहल आधारित उत्पादक कृष्णा और राजाराम (वाल्वा) ने बड़े हुए आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए विशेष रूप से आवेदकों का समर्थन किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि यही उनके द्वारा उठाई गई हानि का कारण है। अल्कोहल आधारित उत्पादक अपनी एसीटोन क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर सकें इसका कारण एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. नहीं है।

(घ) क्षमता का सृजन क्षति का कारण नहीं हो सकता

(i) मित्सुई केमिकल्स इक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि क्षमता की सृजनता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आयात और क्षति में कोई नैमित्तिक संबंध है। उन्होंने इसके समर्थन में 'ग्लास केस की विशेष श्रेणी' - ओ.जे. 1986 सी 128/7 को उद्धृत किया है। प्रारम्भ में ही यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह जीव रिपोर्ट यूरোपियन कमीशन की है जिसकी भारत पर कोई बाध्यता नहीं है। यह जीव विनियम (ई.ई.सी.) सं० 288/82 की शर्तों के अनुसार की गयी थी, न कि रक्षोपाय पर अनुबंध के प्रावधानों को प्रतिबिम्बित करने वाले विनियम के अधीन, जिसे डब्ल्यू टी ओ रिजीम के अधीन केवल 1-1-1995 को समाविष्ट किया गया था। उस मामले के तथ्य बिल्कुल उसी तरह से अलग हैं जिस तरह उस मामले में जीव पड़ताल किये गए मित्र मामले में ग्रीस में आयात किए गए। प्राधिकारियों ने ग्रीस में ग्लास के उपयोग में मांग के स्तर ढोंचे में बदलाव जो ग्रीक उद्योग द्वारा तकनीकी रूपान्तर के साथ जुड़ा था, और ग्रीक उद्योग के लाभों पर ग्रीक प्राधिकारियों द्वारा स्थापित मूल्य नियन्त्रण प्रणाली के प्रभाव पर भी विचार किया था। उस मामले में तथ्य यह थे कि ग्रीक उद्योग ने एक फ्लोट ग्लास के लिए नहीं, बल्कि एक ड्रॉन ग्लास उत्पादन लाइन बनाने के लिए 1980 में बहुत बड़े निवेश किए थे। ड्रॉन ग्लास की खपत मुख्यतः निर्माण क्षेत्र में धीमी गति के कारण कम हुई तथा माँग के ढोंचे में एक बदलाव आ गया था। 1981 तथा 1984 के बीच ड्रॉन ग्लास की खपत 17000 टन से अधिक गिर गई जबकि फ्लोट ग्लास जिसके लिए ग्रीक उद्योग के पास आवश्यक तकनीक नहीं थी, उसमें 12000 टन की वृद्धि हो गई। इस प्रकार ड्रॉन ग्लास का स्थान स्पष्ट रूप से फ्लोट ग्लास ने लिया। वर्तमान मामले में तथ्य स्पष्टतया दृष्टि गोचर हैं क्योंकि घरेलू उत्पादकों ने एसीटोन के उत्पादन के लिए क्षमता को विस्तारित किया है जिसकी मांग बढ़ गई है लेकिन घरेलू उत्पादक अपने बाजार शेयर में वृद्धि करने में असमर्थ रहे।

(ii) मित्सुई केमिकल्स इक ने भी इस मामले में समर्थन देने से यह कहने के लिए हाथ खींच लिया है कि यदि गिरती हुई प्रवृत्ति पहले ही दृष्टिगोचर थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों और हानि दोनों में नैमित्तिक संबंध है। यह भी उनको सहायता नहीं करता क्योंकि वर्तमान मामले में पहले से ज्ञात गिरावट की

प्रवृत्ति नहीं है। वर्तमान जॉच में यह परीक्षण किया जा रहा है कि क्या घरेलू उत्पादकों ने गंभीर क्षति की आशंका का सामना किया है जो कि प्रारम्भिक अवधि से 1998-99 की उनके कार्य निष्पादन की तुलना से प्रमाणित है। घरेलू उत्पादकों का मामला यह है कि प्रारम्भिक वर्षों की तुलना में उन्होंने 1998-99 के कार्य निष्पादन में एक गंभीर बाधा का सामना किया है। यहाँ यह भी देखना आवश्यक है कि वर्तमान जॉच के प्रयोजन के लिए जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है वह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी के अधीन पारिभाषित घरेलू उद्योग है, न कि व्यक्तिगत इकाइयाँ। इसलिए कुल मिलाकर प्रभावित घरेलू उत्पादकों के कार्य निष्पादन पर विचार करने की आवश्यकता है जो पहले से ज्ञात किसी गिरावट की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाती है।

(iii) यूरोपियन आयोग की घोषणा का आश्रय लेते हुए, मित्सुई केमिकल्स इंक ने भी तर्क दिया है कि यदि उत्पादन और बिक्री स्थिर रहे अथवा ऊपर उठे तो आयातों के साथ नैमित्तिक संबंध का दावा नहीं किया जा सकता। यह कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है जिसे केवल उत्पादन और बिक्री के आधार पर ही नहीं बल्कि विभिन्न कारकों के वास्तविक मूल्यांकन पर क्षति आँकने की आवश्यकता है। वास्तव में, आयातों और क्षति के बीच नैमित्तिक संबंध को आँकने के लिए रक्षोपाय शुल्क नियम के अनुलग्नक की अपेक्षा है कि विशेषकर उस उद्योग की स्थिति से संबंधित यथार्थ और परिभाषित प्रकृति के सभी संगत कारकों, यथार्थ और सापेक्ष रूप में उसे संबंधित वस्तु के आयात में वृद्धि की राशि और दर, वर्धित आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार का अंश, बिक्री और उत्पादन के स्तर में परिवर्तन आदि सभी संगत कारकों का महानिदेशक द्वारा मूल्यांकन किया जाए। इस लिए यदि बड़ा हुआ आयात इस दशा में पहुँच जाए कि घरेलू उत्पादन तथा बिक्री अधिक होने की स्थिति में भी यदि आयातों ने अधिक बाजार शेयर पर अधिकार कर लिया है और इस प्रकार घरेलू उत्पादन को विस्थापित कर देता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार जो क्षति हुई है वह बड़े हुए आयात के कारण है। हालाँकि वर्तमान मामले में 1997-98 की तुलना में 1998-99 में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है यद्यपि बिक्री 1997-98 की तुलना में 1998-99 में 1.3% बढ़ गयी थी, परन्तु वह आमासी खपत में दर्ज की गयी 21.1% की वृद्धि से बहुत कम थी।

(iv) मित्सुई केमिकल्स इंक ने भी इसी प्रकार तर्क दिया है कि यदि निर्यात का नुकसान हुआ है तो आयात को क्षति का कारण नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में भी ई सी द्वारा जॉच किए गए मामलों के तथ्य काफी स्पष्ट थे क्योंकि उस मामले में 1981 से 1984 के बीच तारों वाले या फीगर्स ग्लास की खपत लगभग 4400 टन गिरी तथा ग्रीक उद्योग द्वारा निर्यात ग्रीक उद्योग के लिए एक अपरिहार्य मार्ग था जो निर्यात के क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सका। वर्तमान मामले में घरेलू बाजार में खपत में कोई गिरावट नहीं आई है बल्कि खपत में वृद्धि हुई है और आवेदकों को हालाँकि वास्तविक निर्यात में हानि हुई लेकिन डीम्ब एक्सपोर्ट आधार पर घरेलू बाजार में तुलनीय मात्रा की आपूर्ति की। लिहाजा मित्सुई किसी भी प्रकार से 'ग्लास के मामले' से समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है।

(ज) विदेशों में स्थापित की जाने वाली महत्वपूर्ण क्षमताएं

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एसीटोन की माँग में विश्वव्यापी वृद्धि जो पिछले कुछ वर्षों में 4.2% प्रतिवर्ष थी, वह विलायक आधारित प्रणाली आदि से जल आधारित पेन्ट की ओर परिवर्तित हो जाने जैसे कारकों के कारण आने वाले वर्षों में घटकर 3.1% प्रति वर्ष रह जाएगी। लगभग 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की वर्तमान क्षमता, अनुमानित 3.85 मिलियन टन प्रति वर्ष की माँग से अधिक है। इस प्रकार 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष

अतिरिक्त है और अगले 3 - 4 वर्षों में लगभग 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष की नयी क्षमताओं के स्थापित होने की आशा है। अमिनव एवं निकट भविष्य में होने वाले विस्तार में फिनलैंड - 43000 मी. टन प्रतिवर्ष, डी.एस.एम. - 12000 मी. टन प्रतिवर्ष, एस्टिसा, स्पेन - 90000 मी. टन प्रतिवर्ष, फिनलैंड - मोबिल-244000 मी. टन प्रतिवर्ष, चीन - 80000 मी. टन प्रतिवर्ष और मित्सुई, सिंगापुर - 120000 मी. टन प्रतिवर्ष सम्मिलित हैं। जिसका मतलब अगले 3-4 वर्षों में 1.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक अतिरिक्त क्षमता होने की आशा है जिसका अर्थ है माँग से 40% की अधिक क्षमता का होना। इस अतिरिक्त क्षमता का प्रभाव भारत में एसीटोन के उत्पादकों पर भी पड़ने जा रहा है। यह दावा किया गया है कि मित्सुई के पास एसीटोन को प्रापिलीन में वापस परिवर्तित करने की तकनीक है। इस संबंध में यह पाया गया है कि यह मित्सुई के पास उपलब्ध तकनीकी विकल्पों में से एक है, लेकिन क्या वे इस विकल्प का सहारा लेंगे और क्या यह उनके लिए मितव्ययी होगा, यह भविष्य में देखा जाना है। फिर भी, मित्सुई द्वारा स्थापित एसीटोन संयंत्र के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है।

8. समायोजन योजना:

(i) आवेदकों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने के लिए एक सकारात्मक समायोजन करने हेतु हाथ में ली जाने वाली योजनाओं तथा किये जाने वाले प्रयासों के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक पुनः संरचना योजना को प्रस्तुत किया है। दोनों घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वे यह समझते हैं कि रक्षोपाय शुल्क के रूप में प्रदान की गयी राहत एक अल्पकालिक उपाय है। विद्यमान सुविधाओं का निर्माण उदारीकरण से पूर्व, एम.आर.टी.पी. के समय में किया गया था और उच्च निर्धारित लागत की ओर ले जाने वाले कारकों में मितव्ययिता की कमी थी। तथापि, भारतीय उद्योग अपने तकनीक को लगातार उच्चीकृत करता रहा है और अपने विनिर्माण सुविधाओं के मार्गावरोधों को दूर करता रहा है ताकि प्रति इकाई परिवालन लागत में कमी आये और अधिकांश क्षेत्रों से बढ़ती हुई घरेलू माँग को पूरा करने की प्रभावी क्षमता बढ सके। क्षमता वृद्धि के क्षेत्र में (विनिर्माण की निश्चित लागत में अनुवर्ती कमी के साथ), एच.सी.एल. जिसने अभी हाल में ही अपनी क्षमता 1994-95 में 12000 मी. टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1998-99 में 18300 मी. टन प्रतिवर्ष कर ली है, उसके पास इसे बढ़ाकर 24000 मी. टन प्रतिवर्ष करने की सक्रिय योजना है। विद्युत लागत को कम करने के लिए, एच.सी.एल. द्वारा, को-जेनरेशन रुट द्वारा कैप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। यह सुविधा पहले ही स्थापित की जा चुकी है और जल्द ही आरम्भ हो जाएगी। इसके अलावा, लागत में कमी करने के विभिन्न उपायों को सुझाने हेतु बाहरी कंसल्टेंटों को नियुक्त किया गया था। इस तरह के कुछ सुझाव जैसे कि एसीटोन के विनिर्माण की लागत में कमी करने की दृष्टि से फीड स्टॉक (क्यूमिन) की गुणवत्ता में सुधार करना अत्यधिक उपयोगी है। यह सब चलते रहने वाले किया कलाप हैं, जो जारी रहेंगे। मध्यम अवधि में उद्योग द्वारा प्रापिलीन का आयात पत्तनों पर जुटायी गयी नयी सुविधाओं के माध्यम से किया जाएगा जैसा कि दाहेंज ने जी.सी.पी.टी.एल. और मुम्बई के निकट जे.एन.पी.टी. (जिसके लिए एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. दोनों प्रमोटर रहे हैं और जिसे भूतल परिवहन मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है)। पानीपत में आई.ओ.सी. परिशोधक की क्षमता बढ़ाई जा रही है और यह प्रक्रिया 1999 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। जाम नगर की रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि. की सार्वभौमिक आकार की परिशोधक के भी 1999 से कार्य आरम्भ करने की आशा है। कैकर काम्प्लेक्सों के साथ गेल और हल्लिद्या द्वारा भी निकट भविष्य में स्थापित होने की आशा है और वर्तमान सुविधाओं के मार्गावरोधों को दूर करके, घरेलू प्रापिलीन की उपलब्धता को आसान किया जा सकेगा और कीमतों को कम किया जा सकेगा और नये स्त्रोतों से उपलब्धता संचय हो सकेगी। एच. सी. एल.

भी विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड फिनाल विनिर्माण सुविधाओं (60000 मी. टन प्रतिवर्ष अथवा 90000 मी. टन प्रतिवर्ष) को स्थापित करने की योजना बना रहा है। एच.सी.एल. सुविधा की योजना गुजरात राज्य में दाहेज में बनायी जा रही है। तकनीकी अनुबंध भी कर लिए गये हैं। क्यूमिन के लिए स्टेट आफ दि आर्ट जियोलाइट तकनीक का अनुबंध अमरीका की यू.ओ.पी. से कर लिया गया है। इसी तरह एसीटोन के विनिर्माण के लिए अद्यतन पीछी तकनीक का अनुबंध अमरीका की ए.बी.बी. ल्यूमस ग्लोबल से कर लिया गया है। दोनों तकनीकें पर्यावरण अनुकूल हैं और एच.सी.एल. को परिचालनात्मक एवं लागत संबंधी लाभ अवश्य देंगी। कच्चा मात्रा या तो आयात किया जाएगा या ऊपर वर्णित नयी सुविधाओं से प्राप्त किया जाएगा। एच.सी.एल. परियोजना के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन पूरा कर लिया गया है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। एच.सी.एल. की जल आवश्यकता को दाहेज में जी.आई.डी.सी. की सामान्य जल आपूर्ति योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और उन्होंने इसके लिए आरंभिक सुगतान भी कर दिया है। विद्युत की योजना को-जेनरेशन रुट द्वारा कैप्टिव रूप से उत्पादन करने की है। जहाँ तक धनराशि का संबंध है, एच.सी.एल. पहले ही वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कर चुका है। एच.सी.एल. परियोजना के कच्चे माल और तैयार उत्पाद के ट्रेफिक आंकड़े दाहेज में स्थापित होने वाले गुजरात रसायन पत्तन टर्मिनल काम्प्लेक्स के कुल ट्रेफिक आंकड़ों में सम्मिलित हैं। इस पत्तन द्वारा 1999 के अन्त तक कार्य आरंभ कर देने की आशा है। दो विनिर्माताओं, एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. के बीच इस क्षेत्र में सहकारी प्रयास की और भी संभावना है।

(ii) इस संबंध में एच.ओ.सी. ने उल्लेख किया है कि क्षमता में वृद्धि के क्षेत्र में (विनिर्माण की निश्चित लागत में अनुवर्ती कमी से) आधुनिक जियोलाइट कैटलिस्ट प्रणाली का प्रयोग करके क्यूमिन के विनिर्माण हेतु तकनीक को उच्चीकृत करने के साथ-साथ एच.ओ.सी. अपनी क्षमता 39000 मी. टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, उनके द्वारा लगभग 65 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश द्वारा विभिन्न प्रकार की ऊर्जा संरक्षण योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। यह सब चलते रहने वाले क्रिया कलाप हैं, जो जारी रहेंगे। दीर्घकालीन उपाय के रूप में, एच.ओ.सी. की योजना 60000 मी. टन प्रतिवर्ष अथवा 90000 मी. टन प्रतिवर्ष के विश्व स्तरीय ग्रीन फील्ड फिनाल विनिर्माण सुविधा के स्थापना की है। इस क्षेत्र में निवेश 650 करोड़ रुपये या उससे अधिक होगा जो सुविधा के आकार पर निर्भर करेगा। उत्पादित मात्रा के एक भाग का निर्यात किया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. के बीच एक सहकारी प्रयास की संभावना है।

(iii) अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने के लिए, एच.ओ.सी. द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के आधार पर उन्हें आशा है कि वे 2001-2002 में 3939 रुपये प्रति मी. टन की कुल लागत बचत को प्राप्त कर लेंगे। वे यह भी आशा करते हैं कि वे एसीटोन विशेष सुधार उपायों को अपनाकर 655 रुपये प्रति मी. टन की और भी लागत में बचत कर लेंगे जिसकी संपूर्ण क्षमता 2002-2003 में प्राप्त कर ली जाएगी इसी तरह, एच.सी.एल. को आशा है कि वे 2001-2002 में 5956 रुपये प्रति मी. टन की लागत बचत को प्राप्त करेंगे और उसके बाद एसीटोन विशेष सुधारों को अपनाकर 1511 रुपये प्रति मी. टन की लागत बचत को प्राप्त करेंगे, जिसकी पूरी क्षमता 2002-2003 में प्राप्त कर ली जाएगी।

(iv) इस तरह आवेदकों ने उन कारणों की पहचान कर ली है, जिसने उन्हें बड़े हुए आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थ बना रखा है। उनके द्वारा पहचान किये गये कारणों में से एक आर्थिक

परिमाण का अभाव है। घरेलू उत्पादक अपनी उत्पादन सुविधाओं को लगातार उच्चिकृत करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, उन्होंने अपनी क्षमता को धीरे-धीरे 1994-95 में 38840 मी.टन प्रतिवर्ष से 1998-99 में 45950 मी.टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया है, जिससे उनकी क्षमता में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादकों ने प्रश्नावली के उत्तर में उनके द्वारा अपनायी गयी लागत बचत योजनाओं और उससे प्राप्त किये जाने वाले लागत में संभावित कमी का आवश्यक ब्यौरा उपलब्ध कराया है। यह एक व्यावहारिक समायोजन योजना प्रतीत होती है जिसका कार्यान्वयन और परिणाम 2001-2002 अर्थात् काई वर्षों में सामने आने वाला है। इसलिए, यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने की प्रक्रिया में हैं, और यह कि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनने के लिए काई वर्षों की आवश्यकता है।

9. जनहित

(i) कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से जनता का कोई हित नहीं होगा। इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनता के हितों पर गंभीर रूप से विपरीत प्रभाव डालेगा क्योंकि बड़ी संख्या में अन्त उपयोगकर्ता उद्योग बन्द हो सकते हैं। इस संबंध में, यह पाया गया है कि अभिव्यक्ति "जनहित" में केवल उपभोक्ता हित ही नहीं आता है। यह अधिक विस्तृत शब्द है जिसके अन्तर्गत गृहस्थ सामुदायिक हित के साथ-साथ सामान्य सामाजिक कल्याण आता है। चूंकि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के परिणामस्वरूप खरीददारों को आयातित एसीटोन की लागत में वृद्धि होगी, इसलिए इससे विनिर्मित अन्त उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के उद्देश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का उद्देश्य बड़े हुए आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने हेतु घरेलू उद्योग को समय प्रदान करना है। इसलिए मात्र पर्याप्त अवधि और सीमा तक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण ग्राहकों के लिए न केवल विपरीत प्रभाव, यदि कोई हो, को न्यूनतम करेगा, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक बड़ा विकल्प भी प्रदान करेगा। घरेलू उत्पादक जिन्होंने भारी सार्वजनिक निवेशों से संयंत्रों की स्थापना की है, वे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए रक्षोपाय शुल्क, जो बड़े हुए आयातों से उत्पन्न प्रतियोगिता के सामने घरेलू उत्पादकों को अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ बनायेगा, वह एसीटोन से विनिर्मित उत्पादों के खरीददारों के साथ-साथ एसीटोन के खरीददारों के दीर्घकालीन हित में भी होगा। इसलिए यह माना गया है कि एसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनता के हित में होगा।

10. अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क

इस तथ्य को देखते हुए कि जांच को पूरा करने तक यदि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण में विलम्ब किया गया तो घरेलू उद्योग को अपूर्ण क्षति होने वाली है, इस तथ्य को इंगित करने वाली गंभीर परिस्थितियाँ अस्तित्व में नहीं थीं, इस लिए अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

11. भारत में निर्यात करने वाले देशों का अंश

भारत को निर्यात करने वाले देशों / क्षेत्रों के अलग-अलग अंश 1998-99 में निम्नानुसार थे :-

सारणी - 10

देश/क्षेत्र	आयात मी.टन	% अंश
जर्मनी	1603	5.49
जापान	583	2.00
नीदरलैंड	2572	8.81
रूस	2040	6.99
दक्षिण अफ्रीका	16384	56.15
दक्षिण कोरिया	2975	10.19
ताइवान	1005	3.44
यू.एस.ए.	1480	5.07
अन्य	540	1.86
योग	29182	100

(छ) निष्कर्ष एवं संस्तुति

1 उपरोक्त जांच परिणामों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में एसीटोन के बढ़े हुए आयात ने एसीटोन के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न कर दी है और भारत में एसीटोन के आयात पर ढाई वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जन हित में होगा।

2 घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति से बचाने के लिए रक्षोपाय शुल्क की कितनी मात्रा पर्याप्त होगी, यह जानने के लिए और सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने हेतु एच सी एल और एच ओ सी के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत को सम्पूर्ण 1998-99 के लिए ध्यान में रखा गया है, जो सम्पूर्ण वर्ष के लिए सही लागत को अधिक प्रतिबिम्बित करता है। निवेशित पूंजी आदि पर अनुमानित वापसी के आधार पर घरेलू उत्पादकों ने लाम की एक निश्चित धनराशि का दावा किया है जिसे अधिक माना गया है, और इसलिए उत्पादन के भारित औसत लागत के आधार पर लाम की एक कम राशि (गोपनीय) को समुचित माना गया है और स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार पिछले छ. महीने अर्थात् अक्टूबर 1998- मार्च 1999 के लिए भारित औसत आधार पर एसीटोन के सी आई एफ आयात मूल्यो पर भी विचार किया गया है। ऋण अवधि एवं संचालन खर्च के लिए औसत के आधार पर सी.आई.एफ. आयात मूल्य में समायोजन किये गये हैं। आयातित एसीटोन के उतराई के समय के मूल्य की गणना करने में सीमा शुल्क की लागू होने वाली दर में परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है।

3. रक्षोपाय शुल्क के उत्तरोत्तर उदारीकरण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह संस्तुति की जाती है कि एसीटोन के बढ़े हुए आयात द्वारा उत्पन्न गंभीर क्षति की आशंका से घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यकता होने के कारण निम्नानुसार ढाई वर्षों की अवधि के लिए यथामूल्य आधार पर नीचे दिये गये दर पर भारत में एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया जाए।

अवधि	संस्तुत कुल संरक्षण का स्तर % में	विद्यमान संरक्षण % में	संस्तुत रक्षोपाय शुल्क % में (3) - (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम वर्ष	38.5 + 28	38.5	28
द्वितीय वर्ष	38.5 + 21		21
शेष छः महीने	38.5 + 9		9

[फा. सं. एस जी/आई.एन.वी./1/99]

आर.के. गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 1999

Subject: Safeguard investigation concerning imports of Acetone into India - Final Findings.

G.S.R. 749(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

A. PROCEDURE

1. The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of Acetone into India was issued on 16.06.1999 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 19.06.1999. A copy of the Notice was sent to all known interested parties, namely :-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOC), Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd. (HCL), Mumbai
- (iii) Rajaram Bapu Patil SSK Ltd., Walva, Distt. Sangli
(hereinafter referred to as Walva)
- (iv) Chaltan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandali Udyog Ltd. Surat
(hereinafter referred to as Chaltan)
- (v) Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Maharashtra
(hereinafter referred to as Krishna)
- (vi) National Organic Chemical Industries Ltd., Mumbai (NOCIL)
- (vii) Cordite Factory, Aruvankadu, Nilgiris.
- (viii) Sirsilk Ltd., Andhra Pradesh

The Notice sent by Regd. Post to Sirsilk Ltd was returned undelivered by the postal authorities with the remarks "Factory closed".

Importers

- (i) C.J.Shah & Company, Mumbai
- (ii) Haresh Kumar & Company, Mumbai
- (iii) Crescent Organics Ltd., Mumbai
- (iv) Aroma Agencies Mumbai
- (v) Vinmar International India Pvt. Ltd., Mumbai

User Industries

- (i) Kesar Petro Products Ltd., Mumbai
- (ii) Glaxo India Ltd., Mumbai
- (iii) Kopran Ltd., Mumbai
- (iv) Gharda Chemicals Ltd., Mumbai
- (v) Asian Paints Ltd., Mumbai
- (vi) Bayer (India) Ltd., Mumbai
- (vii) Bombay Oxygen Corporation, Mumbai
- (viii) Hitkari Multifilters Ltd., Mumbai
- (ix) Gujarat State Fertilisers and Chemicals Ltd., Vadodara
- (x) ICI Ltd. West Bengal

Exporters

- (i) Georgia Gulf Corporation, U.S.A.
- (ii) Mitsui Chemicals, Tokyo
- (iii) Kumho Chemical Company, Seoul, Korea
- (iv) Merisol/Merichem Sasol, South Africa
- (v) Kolmar Petrochemicals AG, Switzerland.
- (vi) ICC Chemical Corporation, New York,

Overseas Associations

- (i) Chemical Safety Management Centre, Japan Chemical Industry Association-JCIA, Tokyo 100, Japan.
- (ii) Chemical and Allied Industries Association -(CAIA) Auckland Park 2006, South Africa. (Notice sent was returned undelivered)
- (iii) Korean Petrochemical Industry Association -(KPIA) Chongno-ku, Seoul, Korea.
- (iv) Chemical Manufacturers Association (CMA) Virginia-22209, USA

Indian Associations

- (i) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai

2. A copy of the notice alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Canada, China, Chinese Taipei, Finland, France, Germany, Japan, Korea DPR, Korea RP, the Netherlands, New Zealand, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, U.K. and USA.
3. Questionnaires were also sent on the same day to all known domestic producers, exporters and importers who were asked to submit their response by 26.07.1999.
4. Request for extension of time to submit their reply was made by the following parties :-

- (i) Bayer (India) Ltd., Mumbai
- (ii) Gujarat State Fertilisers and Chemicals Ltd., Vadodara

Keeping their request in mind and the need to complete the investigation within the statutory period, M/s. Bayer (India) Ltd. was granted extension upto 30.07.99 and M/s. GSFC was informed that they may make their views known at the time of public hearing.

5. Replies to the Notice dated 16.06.1999 and to the questionnaire were received from the following parties :-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) NOCIL Mumbai
- (iv) Cordite Factory Aruvankadu
- (v) Krishna, Maharashtra

Importers

- (i) Haresh Kumar & Co., Mumbai
- (ii) Crescent International Ltd., Mumbai

User Industries

- (i) Kesar Petro Products Ltd., Mumbai
- (ii) Bayer (India) Ltd., Mumbai
- (iii) Gujarat State Fertilisers & Chemicals Ltd., Vadodara

Exporters

- (i) Mitsui Chemicals Inc., Japan
- (ii) Merisol, South Africa
- (iii) Kumho P&B Chemicals Inc., Seoul, Korea (through M/s. Samsung Corporation).
- (iv) Sasol Solvents, South Africa (through M/s. Crescent Organics, Mumbai).

6. Response to the notice has also been filed by the following :-

- (i) Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad

7. Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers visited the premises of M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Cochin; M/s. Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai; NOCIL, Mumbai; M/s. Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai and Crescent Organics Ltd., Mumbai. The outcome of investigations was conveyed to the concerned parties and a copy of the investigation report was also placed in the Public File.

8. A Public Hearing was given to all interested parties on 10.09.99, notice for which was sent on 10.08.99. During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by

them by 16.09.99; collect copies of replies filed by others on 17.09.99 and to file rebuttals if any, by 24.09.99. The following parties attended the public hearing:

- (i) Hindustan Organic Chemicals, Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) Rajaram, Walva
- (iv) Krishna
- (v) Bayer India Ltd., Mumbai
- (vi) Crescent Organics Ltd., Mumbai
- (vii) Kesar Petro Products Ltd., Mumbai (Through Counsel)
- (viii) Mitsui Chemicals Inc., Japan (Through Counsel)
- (ix) Mitsui & Co. Ltd., Japan
- (x) Samsung Corporation,
- (xi) Gujarat State Fertilisers & Chemicals
- (xii) Ranbaxy New Delhi
- (xiii) Embassy of Taiwan, New Delhi
- (xiv) South African High Commission, New Delhi
- (xv) NOCIL, Mumbai

B. VIEWS OF EXPORTERS

The following main points have been made by the exporters :-

(a) Mitsui Chemicals Inc., Japan

- (i) The Applicant Indian manufacturers of Acetone are in a monopolistic position in India (as per their own claim they control upto 97% of the domestic production) and it appears that the present application is being used as an instrument to secure and perpetuate that monopolistic position. Several of the issues currently complained of, have also existed in earlier years, in which years the Applicants achieved a capacity utilization of 102%, clearly indicating that these factors did not affect them significantly. It is apparent that the sharp decrease in exports which indicate that the Applicants have become internationally uncompetitive is the reason for the current application with a view to secure and sustain the Applicants monopolistic dominance of the Indian market.
- (ii) The quantum of the levy claimed effectively also indicates that the Applicants are trying to secure for themselves a level of profitability wholly unconnected with the current trend in the international market. This would clearly be at the cost of the Indian Domestic User Industry. The action indicated appears to be detrimental to the Indian Industry as a whole and with a very narrow perspective to secure market dominance and unrealistic price/profit realization for the two Applicants.
- (iii) The application fails to indicate 'serious injury' and in particular fails to establish any causal link between the claimed injury and the imports.

- (iv) The application fails to establish 'critical circumstances' and more particularly, 'irreparable damage' consequently the request for imposition of provisional duty does not appear sustainable.
- (v) The application sets out information on certain critical issues in a selective and improper manner. One such instance is regarding the information as to the low & reducing capacity utilization. The Applicants have alleged that the low and reducing capacity utilisation is a result of increasing imports, without clarifying the fact that the effective Acetone capacities of those companies has also been taken into consideration who have not been producing any or producing negligible quantities of Acetone since 1994-95 the non-production of Acetone by such companies is not on account of the increasing imports, as even in 1994-95 when the imports were as low as 9046 TPA no production was undertaken by them. A consideration of this issue is vital to a determination of the injury claimed and the sort of selective information offered must be construed as a conscious act of the Applicants with a view to not disclosing the information required which presumably is adverse to them.
- (vi) The source of information in support of various submissions of the Applicants have not been indicated or indicated as Market Information Sources. Such Market Information Sources are clearly nebulous and are not capable of sustainable verification and this vitiates the Application.
- (vii) Various figures such as the domestic demand figures are not absolute figures and have been derived by using mathematical formulae and therefore such figures are not reflective of the true position.
- (viii) Certain figures set out regarding a drop in the percentage of profitability do not seem to accurately reflect the position as set out in certain published audited accounts of the Applicant Company. It is submitted that this is a matter of some serious concern as to the credibility of the Application.
- (ix) The import price of shipment of Acetone at US\$ 240/MT indicated by HOC and Herdillia, in their opinion is an exceptional case and should not be used for general consideration.
- (x) In the present phase of globalization, local prices are also reflective of international prices. The expectation of the Applicants as indicated from the Application is that they should be able to sustain within India, (at the cost of the Indian Domestic User Industry), profit as they were making in the past, which wholly fails to recognize the impact of international prices. The Applicants appeared to be using these proceedings as an instrument to try and secure an unrealistic level of profitability, which they can exploit in view of their monopolistic dominance of the Indian market.
- (xi) An examination of the sales figures of both the Applicants indicates that the sales figures of Herdillia have consistently shown an increase, which pattern of increase is sustained even on the basis of the figures set out for year 1998-99. As regards HOC, the figures set out clearly indicate a fluctuating trend of sale from 1991-92 and thereafter. The projective sales for 1998-99 are also reflective of this fluctuating trend of sale which has earlier existed for HOC. The imports in question therefore, appear not to have caused any serious injury to the Applicants in respect of their sales.

- (xii) As to the issue of the stocks built up, an examination of HOC's stock position clearly indicates that this has also shown a fluctuating pattern, which pattern is likely to sustain in 1998-99 and thereafter. As regards Herdillia, their figures as to closing stock when examined in the context of factors like export as compared to their earlier exports, they have had no exports in the years 1997-98 and 1998-99 clearly indicate any stock built up is directly attributable to their failure to sustain their competitiveness in the international market. The imports in question therefore, have had no adverse impact on the stock position of the Applicants.
- (xiii) HOC and Herdillia's calculation of requested safeguard duty rate of 86% is based on their asserted minimum fair price using 12% as reasonable return on employed capital. This rate of 12% is unfairly high for manufactures of commodity chemicals today and even higher than the profitability rates realized by HOC or Herdillia in the past. In 1995-96, HOC realized profitability of 14.20%, but during that period, prices of chemical products were exceptionally high and those prices went down in 1997.
- (xiv) Demand of Acetone in India is constantly increasing. Acetone is one of the most important basic chemical to produce many kinds of Acetone derivatives. These Acetone derivatives are used in various industries which are in a severe international competition. The demand for acetone which is used in Pharmaceutical industry has been increasing by 8% to 10 per annum and pharmaceutical products using acetone were one of the major exports of India. Imposition of Safeguard Duty on Acetone would benefit 2 domestic Acetone producers at the expense of many manufacturers demanding Acetone. Delay of growth of such manufacturers would cause irreparable adverse effect on general economy of India.
- (xv) They admit that the domestic Acetone producers are experiencing difficulty due to decreased import duty rate on Acetone. However, import duty rate on Acetone in India is still considerably higher than other countries.
- (xvi) As production capacity of domestic Acetone producers cannot satisfy the total demand of Acetone in India, Acetone users will have to purchase imported Acetone even after imposition of safeguard duty. Procurement of Acetone at higher than international market price would severely deteriorate competitiveness of those users. They did not export their Acetone to India from 1.04.94 to 31.3.99 but hope to cooperate with the users of Acetone by supplying their product in the near future.
- (xvii) The initiation of the safeguard proceedings is wrongful and in breach of due process as the ultimate culmination of these proceedings would result in a situation which is clearly in breach of the laws of India as secured by other statutes, particularly statutes such as the MRTP Act which have defined socio-economic objectives.
- (xviii) The factors based on which injury is claimed are factors inherent to and typical of Indian industry as a whole, and the Chemicals and Pharmaceutical industry in particular i.e. the Customs Tariff structure, the pricing mechanism operative in India, infrastructure problems etc. This position is clearly recognized in various government studies and published papers. The injury claimed is, therefore, not a consequence of imports.

- (xix) The Application refers to certain figures in the context of entities who are themselves importers of Acetone. Further the Application also refers to figures relevant to entities who themselves have not supported this Application indicating clearly that they are neither injured nor perceive a threat of injury. Reference to such entities presents a skewed picture which clouds the issues under consideration.
- (xx) A study of the Indian market indicates that there is a demand supply gap both in quantum and quality terms which per-force requires imports by the user local industry. Any levy which tends to restrict or renders the imports costlier will have a significant adverse impact on the domestic and international competitiveness of the local user industry.
- (xxi) The Applicants have applied for the imposition of safeguard duty on behalf of eight Acetone manufacturers in India. These eight manufacturers could be divided into three categories based on their manufacturing processes as follows:
 - (a) Cumene Process Manufacturers : HOC and Herdillia;
 - (b) Isopropyl Alcohol Process Manufacturers : NOCIL
 - (c) Fermentation Process Manufacturers : Cordite, Chaltan, Walva, Sirsilk and Krishna

As the Financial/economic situations of Acetone manufacturers in the categories mentioned above are essentially different, treating eight manufacturers as one group would lead to incorrect conclusions being drawn as to the state of the domestic Acetone Industry. The Cumene Process is the most common and competitive process used by the major Acetone manufacturers in the world. Isopropyl Alcohol Process is a cost inefficient process for production of Acetone requiring large unit of Propylene as raw material of Isopropyl Alcohol. As the price of Propylene has increased, NOCIL has suspended its Acetone production and is now importing Acetone for its production of Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) and Diacetone Alcohol (DAA). As NOCIL is an importer of Acetone, they should not be included in consideration of injury. The Fermentation Process Manufacturers first produce Ethanol and subsequently Ethanol is used as a raw material for the manufacture of Acetone. During the relevant period, as the sale of Ethanol was more profitable than that of Acetone, the Fermentation Process Manufacturers sold Ethanol rather than Acetone. Even though the Acetone production by Fermentation Process Manufacturers has been extremely low as compared with their production capacity, they have not suffered any injury from such low production.

- (xxii) Domestic demand of Acetone has been constantly increasing owing to the open-door economic policy of the Indian Government. As the Applicants' production capacity is unable to satisfy such increasing demand, users need to import Acetone from foreign manufacturers. The reason why the Applicants have failed to satisfy the domestic market is lack of international competitiveness, which is clearly indicated by decrease in their exports. The Applicants could have achieved their targeted production level by increasing export of their product if they were internationally competitive.

- (xxiii) The capacity utilization of the Applicants has decreased from 96.7% in 1997-98 to 89.7% in 1998-99 which should be attributed to the expansion of production capacity by Herdillia in 1998-99 through debottlenecking, and should not be attributed to the increased imports of Acetone into India. If it were not for such expansion, the capacity utilization of the Applicants in 1998-99 would have been 94.1%.
- (xxiv) The Applicants have enjoyed capacity utilization rates between 87% to 102% during 1994-99 which are extremely high rates for chemical products and which most of global major chemical manufacturers are unable to attain.
- (xxv) Acetone is a commodity product sold worldwide and its price is established internationally. The price of Acetone imported into India has dropped due to overall decline of the international market price of Acetone. The rate of decline of the price in India is at the same level as other areas. The Applicants had to decrease their Acetone price in India in order to meet with this global economic situation. Increased imports should not be regarded as the cause of drop of Acetone price in India. The profitability of the Applicants has fallen in this competitive market because their production cost is much higher than foreign producers of Acetone. The Applicants could not attract their customers in this situation nor increase their production because of already high capacity utilization. Thus they fail to fulfil the increasing demand of Acetone in India and the market share of domestic Acetone producers has declined during the relevant period.
- (xxvi) The chemicals industry at large has been passing through a global recession and the Indian Chemical Industry has also felt its impact. The downtrend in business and prices is not peculiar to India and the Applicants cannot be an island and claim to be unaffected. The injury claimed is, therefore, not a consequence of imports.
- (xxvii) The chemical industry worldwide is a cyclical industry, characterised by periodical ebbs and flows.
- (xxviii) Imposition of safeguard duty may probably save two industries, but render several thousand units totally non-competitive.
- (xxix) In reports published by Business Line – April 11, 1999 and Press Trust of India, July 8, 1999, HOC have spoken in a different language that they are doing well. They can not turn up in another fora and plead they are injured.
- (xxx) In Business Line of June 20, 1999 HCL recognised adverse impact of global commodity price swings aggravated by domestic infrastructure – related problems and import from other group companies or subsidiaries. Factors other than import need to be excluded for evaluating injury caused by imports.
- (xxxi) As per the ratio of judgement in the case popularly referred to as the Certain Categories of Glass Cases, OJ 1986 C 128/7, several factors of injury are not attributable to increased imports.

(b) **Merisol/Merichem Sasol, South Africa**

They acknowledged receipt of the notice of initiation but stated that Acetone was not part of the Merisol product portfolio.

(c) **Kumho P & B Chemical Inc., Seoul, Korea**

- (i) The company has submitted certain details relating to their capacity, production, cost of production, selling price in domestic market, and export price per unit in India during the year 1998-99 which is as under :-

Years	1998	1999
Capacity (MT)	75000	75000
Production (MT)	76859	77000
Cost of Production (US \$)	306	299
Selling price in domestic market Korea (US \$)	406	426
Export price (US \$)	330 FOB Korea	

- (ii) The company has also stated that they exported Acetone to India as under during the last 3 years.

Year	Exports (MT)
1996	1040
1997	-
1998	4370
1999	-

(d) **Sasol Solvents, South Africa**

- (i) While Acetone marketed by Sasol is manufactured in a unique process in which coal is gasified and converted into petroleum products and chemicals one of which is Acetone; the other producers of Acetone use a different feedstock such as Naptha, Gas Propylene, Benzene, Cumene and Iso Propyl Alcohol.
- (ii) Their annual Acetone manufacturing capacity is 1,70,000 Tonnes. They manufacture Acetone of purity 99.85% (minimum).
- (iii) They have authorised their indenting agents for Acetone supplies to Indian market, M/s. Crescent Organics Ltd., Mumbai to represent them in the matter of investigations for the levy of Safeguard duty on Acetone.

The view expressed by M/s. Crescent Organics Ltd., Mumbai being more in the nature of submissions akin to importers, have been incorporated under 'views of Importers/user industry'.

C. **VIEWS OF THE EXPORTING GOVERNMENTS**(a) **Chinese Taipei (Taiwan)**

They furnished details of export of Acetone to India from Taiwan and have requested stopping the safeguard investigation since the quantity of Acetone

imported from Taiwan was minimal and desired prior consultation as per Article 12 of the WTO Agreement on Safeguards.

(b) **Department of Trade and Industry, London**

They expressed gratitude for having been advised of the notice of initiation and desired being kept informed of the progress of investigations.

(c) **South African High Commission, New Delhi**

They are of the view that the imposition of safeguard duty on Acetone is not justified by the circumstances prevailing in the Indian Industry. India's effective and operating capacities have not been able to meet the country's demand for Acetone and it is for this reason Acetone is being exported by Republic of South Africa to India.

Acetone prices in line with other petrochemical feedstock, such as Propylene, Benzene and Cumene – came down during 1998-99 and therefore Acetone exported by South Africa had necessarily to fall in line with this trend. Acetone from South Africa is being exported to meet the supply – demand gap in India and that the prices of Acetone have been moving up significantly since April 1999.

(d) **Embassy of Saudi Arabia, New Delhi**

The Royal Embassy of Saudi Arabia, New Delhi in their response stated that to their knowledge Acetone is not manufactured in the Kingdom of Saudi Arabia and they see no possibility of Acetone being dumped into India.

D. VIEWS OF IMPORTERS/USER INDUSTRIES

I. The importers in general have made the following main points:

- (i) It is a matter of common knowledge for those in the industry that Acetone is a cyclic industry and the prices fluctuate depending upon the business cycle. The prices of Acetone are further dependent upon the prices of Phenol.
- (ii) A plant utilisation level of about 85-90% is extremely good plant utilisation. The Applicants are operating at their optimum capacity and further addition to the production by the industry is ruled out unless some capacities are added. There could be various factors internal/external to HCL and HOC which could have influenced production of Acetone and that these factors are not necessarily reducible to one factor namely, imports of Acetone. The production of Phenol and viability to market the same during the period of reference which has been documented could have had a major impact on lower production levels of Acetone. Perhaps HOC and HCL have not been able to produce Acetone to full capacity since they themselves have imported Acetone.

- (iii) HOC and HCL have not apprised the correct status of effective capacity of Acetone manufacturers in the country. While historically there may have been eight manufacturers of Acetone in India, it is a well known fact that apart from M/s. Herdillia Chemicals Ltd (HCL), M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOC) and M/s. National Organic Chemical Industries Ltd (NOCIL), there are no other manufacturers of Acetone in India who can be depended upon for continuity of supply of Acetone through out the year, year after year. 'Cordite' is under the Ministry of Defence Production and exclusively caters only to its own in-house requirement - which was set up linked to manufacture of explosives for the Armed Forces. It is not a supplier to non-defence units. Chaltan (3000 TPA), Walva (4500 TPA), Sirsilk (1500 TPA) and Krishna (4500 TPA) are all basically Molasses based alcohol units - who like Cordite (1320 TPA) have set up highly uneconomical and unviable Acetone manufacturing capacities. These alcohol based manufacturers of Acetone reopen their units only when Acetone can be sold at rather exorbitant prices which could happen when either imports are inadequate and / or there is a major shutdown at HCL / HOC / NOCIL. These units have been rendered uncompetitive by HCL and HOC long before imports of Acetone came into the country. It is surprising that HCL and HOC should now blame importers for the present predicament of these units. In view of this, the unviable Acetone manufacturing capacities of Cordite / Alcohol units viz., 14,820 TPA should be deleted from the "Effective Manufacturing Capacity". Similarly NOCIL do not find it economical to produce Acetone from Crude IPA, they are progressively phasing themselves out of manufactured Acetone to bought in Acetone from HCL / Imports. Even their purchases of Acetone from HCL are intended to encourage HCL to use their Propylene - which is 65% costlier than imports. In view of this, NOCIL's production capacity of 14000 TPA Acetone should be deleted. The effective Acetone capacity of manufactured Acetone in India be considered commensurate and coterminous with the combined Acetone manufacturing capacities of HOC and HCL viz., 45,950 TPA.
- (iv) It is not proper for the Applicants to file the petition for imposition of safeguard duty in respect of an item which they themselves have been importing either for in house consumption or for stock and sale. Further, imports of large parcels by HCL / HOC / NOCIL have enabled other interested Indian importers to piggy-back on such imports at prices negotiated by these manufacturers.
- (v) The increased imports are not the prime cause of injury to the domestic producers of Acetone. Until 1994-95, the Applicants were operating in a monopolistic situation as imports until then were restricted under the high import duty regime (65% basic duty). The Government had introduced the policy of globalisation of economy and liberalised imports in 1992-93 with a phased programme of reduction in custom duties over a period of 7 to 8 years.
- (vi) While Reliance Petroleum Ltd., have set up the largest refinery in the world in less than 5 years, after nearly 7 years there is no adequate evidence of efforts showing HCL/HOC/NOCIL making themselves competitive in the manufacture of Acetone. During this 7 year period, they have not shed their obsolete technologies and gone in for state of art global scale of production which could produce Acetone for sale at an internationally competitive price. If after 7 years, they are content with mere

- debottlenecking and no major cost reduction has taken place either in their manufacturing process or by sourcing imports of feedstocks at a cheaper prices, then their customers should not be penalised by having to pay the price for inefficient purchasing / manufacturing process.
- (vii) The Applicant's high cost of production could possibly be one of the major reasons for a drop in the annual production tonnage. The non competitive purchasing of major inputs is a major cause of the Applicants inability to produce, cost competitive Acetone vis-a-vis imports. It requires to be investigated whether raw materials, namely Benzene and Propylene or the alternative feedstock, namely, Cumene have been sourced at internationally competitive prices. For reasons best known to them they remained silent on such critical issues as to whether they were in a position to procure Benzene and Cumene at competitive international prices - which has a serious bearing on their competitiveness and the injury as alleged. Had both Applicants procured larger quantities of Cumene in the international market on extended credits from 120 days to 180 days during the reference period, they should have been able to bring down the cost of Acetone substantially.
- (viii) US-Gulf producers are the largest exporters of Cumene in the world. Most of the major buyers of Cumene - including HCL and HOC - source their Cumene from the US-Gulf region. From the ICIS-LOR data it is observed that CIF Indian import price of Cumene imports are often at par with FOB US-Gulf prices at which major American producers of Acetone are purchasing Cumene. As Cumene could be imported at a competitive price comparable with global producers of Acetone in USA, the non import of Cumene in larger quantities can have a direct bearing on the profitability of HCL / HOC.
- (ix) It is not imports that have caused injury but rather the smug attitude of the Applicants and perhaps their expectation that either the problem would resolve by itself or the Government would come to their rescue by way of imposing safeguard duty as was done in the case of Phenol.
- (x) The HOC and HCL imported Acetone despite alleged capacity non utilisation which is not understood. HOC's imports were exclusively for stock and sale. HCL is reported to have taken Acetone to their plant and sold the same thereafter to customers of Acetone. If, as alleged by HCL and HOC, increased imports have caused injury to the domestic producers of Acetone, then it would also be necessary to assess the extent to which imports of Acetone by HCL and HOC have contributed to such injury. NOCIL so far has apparently not claimed injury due to imports. However, their imports - by the same logic - would have caused them injury also. Under the circumstances, it requires to be established how HCL and HOC can enjoy the benefits of being importers of Acetone and concurrently seek imposition of safeguard duty. The bids for imports made by the Applicants also influenced the price at which subsequently imports took place.
- (xi) The Applicants have not presented a correct picture of demand for Acetone and have concealed the fact that Effective Manufacturing Capacity is grossly inadequate to meet the country's demand for Acetone. The domestic production is not enough to meet the domestic annual consumption of about 70,000 MT. Even at 100% capacity utilisation by the Applicants, they fail to meet and are far short of the domestic consumption. Therefore, import is the only way to meet out the

- balance demand. Most of the domestic consumers are procuring their requirement from the Applicants but both put together do not have enough capacity to meet their entire demand.
- (xii) The stock position of HOC and HCL clearly reveals that their entire production is consumed by the domestic market and imports do not have any adverse impact on them.
 - (xiii) The installed capacity of both the Applicants is much lower vis-à-vis standard international Plant capacity. Besides, the Plant set up by the Applicants are inefficient with inferior technologies. They create shortage of Acetone in domestic market, invariably adjusting shut down of their Plants and resort to price rise even when there is drop in international price.
 - (xiv) There does not appear to be any further erosion in prices of Acetone - which are reported to have come down to USD 240 PMT CIF in March, 1999 and has already risen to USD 370 PMT in July, 1999. Consequent to the increase in the prices of Acetone in the international market the manufacturers HOC and HCL have increased their selling prices during May/June/July 1999 from Rs.18,000 PMT to Rs.23,500 which is more than the loss incurred reportedly by them in the last quarter of 1999. The prices are reported to be rising even higher.
 - (xv) Imports of Acetone are being projected by the Applicants as the cause of lower net sales price realisation of indigenously produced Acetone. However, this is not the case. The true cause of lower sales price realisations is the uncompetitive price at which they persist in purchasing their raw materials e.g., Propylene. Imports should not be unfairly blamed for lack of profitability by the Applicants who have consciously chosen to remain uncompetitive in their buying patterns.
 - (xvi) As imports of Acetone at 180 days credit are alleged to be creating liquidity problems for the Applicants, they need to explain why they themselves are not obtaining 100% of their requirements of Propylene and Benzene or Cumene at 180 days credit by resorting to imports.
 - (xvii) The Applicants have already increased their selling prices for Acetone from Rs.21,500 to Rs.23,500 per MT during June / July'99 and there was scope of increasing their price to Rs.26,000 per MT or even Rs.28,000 per MT ex-plant during July, 1999. As against HCL prices, traders such as M/s. Crescent International have sold 50 Tons Acetone to M/s. Kopran Ltd., M/s. Indosol Drugs and M/s. Glaxo India Ltd., at a basic price of Rs.28,000 per MT + excise + taxes. Thus HCL / HOC are not making a serious attempt to improve sales realisation.
 - (xviii) The Applicants expectation of a 12% return on Capital Employed is unreasonable. The market forces of demand and supply determine price and it would be arbitrary and unrealistic to have an accounting norm of 12% return on capital employed - when there is no such norm worldwide for Acetone. The Applicants are trying to secure for themselves a level of profitability wholly unconnected with the current trend in the international market.
 - (xix) The average net realisation of each of the Applicants requires to be worked out afresh using imported Propylene and Benzene as a starting point. Additionally, if the average net realisation improves substantially by resorting to 100% import of Cumene as the starting point for manufacture of Acetone, this should have been resorted to. HCL is importing Cumene at USD 275 PMT CIF in March, 1999. A

- proper scrutiny of the costing of production based on imported inputs purchased more competitively would have improved profitability.
- (xx) Considering the increase in CIF prices of Acetone (USD 390 PMT CIF) by more than USD 150 PMT since April, 1999 and the possibility of importing Propylene and Benzene or Cumene at much cheaper prices than if these are produced by certain indigenous producers, there is no material case for imposition of safeguard duty on imports of Acetone.
 - (xxi) The safeguard duty rate of 86% is based on a wrong price assumption (USD 240) and an unfairly high return of 12% - which is not realistic for commodity chemicals worldwide specially for a by-product such as Acetone whose principal product Phenol is already protected by 22% Safeguard Duty.
- II. In addition to the above points some of the importers have also made the following submissions :-

M/s. Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai

- (a) The purpose of safeguard duty is to provide a price protection to domestic industry (the petition is not for quota restriction). In case it is found after conducting the investigations that the prices of Acetone in the relevant period were not the fair prices for the domestic industry, a floor price may be fixed, on the lines being recommended by the Designated Authority on Anti-dumping, considering the fact that domestic industry has accepted that there is no injury to them in case the imports are available at Rs.22,000 PMT (considering the prevailing level of customs duties) which mechanism would ensure smooth supplies to the consumers and would provide a protection to the domestic industry.
- (b) HOC indicated that the price of Acetone has increased in the international market and, therefore, HOC vide their letter dated 7th July, 1999 indicated increase in Acetone prices in the light of tremendous increase in the international price of Acetone and increased price of Phenol also by Rs.3,000/- MT on account of 22% safeguard duty imposed by the GOI w.e.f. 30th June'99 and thus they have covered their losses incurred in the last quarter of 1999 (to be read as 1998-99) by way of increase in prices. HCL also vide their letter dated 1st July'99 (immediately after issue of letter for initiation for safeguard duty) increased the price of Acetone and thus they have covered their losses incurred in the last quarter of 1999 (to be read as 1998-99) by way of increase in prices.
- (c) Price revision by HOC are always effective immediately and they stop deliveries of Phenol and Acetone against the pending delivery orders which has already been issued by them at old rates. This dictatorial nature does not allow consumers of Acetone and Phenol to decide their prices and are invariably at a loss.
- (d) HOC manufactures Phenol and Acetone at their Cochin Unit and they have another unit at Rasayani, Maharashtra to manufacture other products. HOC's Cochin plant is highly profitable and the losses incurred at their Rasayani plant are compensated by Cochin plant.
- (e) The real grievance of the Petitioner is the price at which the imports are coming in and not the volume of imports. If this is so, then the remedy lies elsewhere.

Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad

- (f) The overheads of HOC are increasing year after year whereas the production capacities of Acetone did not increase thereby HOC are not able to compete with the international market. They should concentrate on reducing overheads.

Bayer (India) Ltd., Mumbai

- (g) They have purchased very small quantities of imported acetone from local importers on a tax plus basis or against Advance License in times of shortages. They have supported the domestic industry through the deemed export procedure by purchasing Acetone at higher prices instead of resorting to direct imports to capitalise on the fall in international prices. If safeguard duty is imposed, the domestic industry will resort to a price increase which will be totally unfair to M/s. Bayer and will affect their competitiveness. There is no possibility of availability of Acetone ex-major domestic producers. Considering that one of the Applicants is a Public Sector Unit and their present financial position, it would be optimistic to believe that Rs.650 Crores will be released by the Govt. of India.

Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.

- (h) They contact indigenous manufacturers to match the landed price of imported Acetone so that at no extra cost they are able to keep the indigenous sources alive in the interest of their long term procurement policy.

Ranbaxy

- (i) The combined capacity of HOC and HCL as stated by them in their application was 45950 MT. They have claimed that their capacity has increased in July-August, 1999, which needs to be substantiated by a certificate from their Statutory Auditors to that effect.

Crescent Organics Ltd.

- (j) Unlike HOC and HCL none of the other domestic producers of Acetone are compulsive producers of Acetone. They object to NOCIL and Cordite to be implicated as applicants. Based on their past performance, they object to Chalthan and Sirsilk producers to be included as applicants. They also object to inclusion of Krishna and Walva being consistent non-performing units since 1994-95. The true cause of injury to domestic producers is uneconomical procurement of raw material, their inability to quickly raise prices and uncompetitive scale of production.
- (k) The major US plants as well as Mitsui's Singapore plant have a Mitsui Special Technology to convert Acetone back into Propylene. None of these new capacities will export Acetone but Phenol. There is, therefore, no cause for alarm about a

wave of Acetone exports to India and request for Safeguard Duty for a period of 3 years on this ground is not warranted.

E. **VIEWS OF DOMESTIC PRODUCERS**

The domestic producers have made the following main points:

(a) **Cordite Factory, Aruvankadu (The Nilgiris)**

- (i) In view of the increase in price of Ethyl Alcohol, their raw material for manufacture of Acetone, they have stopped manufacture of Acetone since quite sometime.
- (ii) They are not affected directly by the excessive imports of Acetone.
- (iii) As a consumer of Acetone they are happy about the reduction in Acetone prices.

(b) **Krishna, Satara**

- (i) They have been manufacturing Acetone since the year 1984 and their capacity is 4500 TPA.
- (ii) The increased imports of Acetone in India (more than 28,000 tons in 1998-99) at extremely low prices in the region of US\$ 250/Ton have caused serious injury to the domestic Acetone manufacturing industry.
- (iii) Imports of Acetone into India have increased by more than ten times in the past seven years from 2773 MT in 1992-93 to 28,870 MT in 1998-99.
- (iv) The sharp fall in import duties in the past few years has also led to near extinction of a substantial number of Indian Acetone manufacturers.
- (v) They support the application made by HOC and HCL for Safeguard investigation against imports of Acetone which has been made to assuage the suffering of the domestic Acetone manufacturers.

(c) **Rajaram Bapu Sahakari Sakhar Karkhana, Walwa**

- (i) Import prices of Acetone have been drastically falling in the past four years alongwith dramatic increase in imports.
- (ii) In 1995-96 they could recover fully their manufacturing cost of Acetone. Due to lower landed cost of imports in 1996-97 they could not recover their manufacturing cost and they had to temporarily suspend production of Acetone.
- (iii) They are in dire need of safeguard duty to be levied on imports of Acetone to recommence Acetone production.

(d) **NQCIL, Mumbai**

- (i) They are a producer as well as consumer of Acetone.
- (ii) They are greatly concerned with the nature of claims made by the domestic industry. Petrochemical is a cyclic industry and the prices fluctuate depending

upon the business cycle. The prices of Acetone are further dependent upon the prices of Phenol.

- (iii) It is a matter of common knowledge for those in Petrochemical industry that a plant utilization level of about 85-90% is an extremely good plant utilization. HOC and HCL are operating at their optimum capacity and further addition to the production by the industry may not be possible unless fresh capacities are added. The country being deficient in Acetone, the remaining demand has to be met out of imports.
- (iv) Imposition of safeguard duty is not in public interest. The purpose of safeguard duty is to provide a price protection to domestic industry (the petition is not for quota restriction). In case it is found after conducting the present investigation, that the prices of Acetone in the relevant period were not the fair prices for the domestic industry, floor price may be fixed on the lines being recommended by the Designated Authority on Anti Dumping, considering the fact that domestic industry has accepted that there is no injury to them in case the imports are available at Rs.23,907/- pmt (considering the prevailing level of customs duties and without considering the additional duty of customs and SAD) which mechanism would ensure smooth supplies to the consumers and would provide protection to the domestic industry.
- (v) It is not disputed that the import price in India had declined to as low as USD 240/t and it is also possible that the Applicants might have made losses at these prices and might have made profits when the prices were higher. Since the decline in the price is a market phenomenon, no extra protection of safeguard duty is required to be given to the industry particularly when the benefit of rising market has also been reaped by the domestic industry.
- (vi) Considering that the capacity utilization of the Applicants is already very good, it does not appear feasible that the domestic industry can increase production in the short run. It also needs to be noted that other domestic companies who hold capacity for Acetone production are in fact not producing Acetone for more than last five years, and reasons for closure of their plants cannot be attributed to imports.
- (vii) Since manufacture of Acetone through the IPA route is not economical, NOCIL does not produce significant volumes of Acetone for the merchant market. The capacity available with NOCIL is, therefore, effectively not available to the domestic industry.
- (viii) Imposition of safeguard duty would affect the availability of the product to the consumers and is thus not in the public interest, which is understood to be one of the vital requirements under the Safeguard Duty Rules.
- (ix) NOCIL in addition to being a producer of Acetone, also purchases Acetone to manufacture downstream products like Methyl Isobutyl Ketone (MIBK), Diacetone Alcohol (DAA) and Methyl Isobutyl Carbinol (MIBC). NOCIL is the only manufacturer of MIBK and MIBC in the country. While MIBK is used mainly in pharmaceuticals, rubber chemicals, surface coatings etc., MIBC is used in ore floatation, latent solvent for nitrocellulose, resins etc.
- (x) NOCIL competes with international chemical companies for MIBK. The competition from international companies is very severe and any imposition of

additional duty on Acetone will seriously affect the viability of manufacture of MIBK.

- (xi) The whole case of domestic industry seems to be the allegation that the domestic producers have been forced to reduce their selling prices from Rs.28/kg in March 1998 to Rs.18/kg in March 1999. If the intent of the imposition of safeguard duty is to provide a price protection to the domestic industry, the safeguard duty should be recommended on a variable basis, on the lines being recommended by the Designated Authority on Anti-dumping which would not only ensure protection to the domestic industry, but also protect the interest of the consumers though they feel no relief by way of safeguard duty is required to be given to the domestic industry.
 - (xii) The market conditions prevailing for Acetone in 1998-99 were due to the cyclical nature of the petrochemical industry. The Acetone prices have in fact increased to USD 360/t in June 99 from USD 240/t in March 99. They do not think that any adjustment is required to be undertaken by the Indian industry in view of the prevailing market conditions in that period.
- (e) **Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai & Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai**
- (i) HOC have their manufacturing units at (1) Rasayani-410027, Distt. Raigad Maharashtra (2) Ambalamugal-682302, Distt. Ernakulam, Kerala and Phenol plant is located at Ambalamugal only. They manufacture Basic Organic Chemicals namely Acetone also known as Dimethyl Ketone, Phenol also known as Carboic Acid or Hydroxy Benzene, Aniline, Nitrotoluenes, Nitrochlorobenzene, Monochlorobenzene, Formaldehyde, Nitrobenzene, Sulphuric Acid, Cyclohexylamine, Acetanilide, Caustic Soda, Hydrogen Peroxide, Butene-1, 4-Diol.
 - (ii) HOC produce Acetone by the Oxidation of Cumene using air at elevated temperatures and pressures. The product is Cumene Hydroperoxide at lower concentration, which is then alkali washed and concentrated to a higher strength. This is then mixed with H_2SO_4 which causes a cleavage reaction to give Phenol and Acetone. This is washed to remove acidity and distilled in a series of distillation columns to give Acetone, Phenol and unreacted Cumene (which is recycled for conversion to Acetone and Phenol. Benzene and Propylene are the major raw materials while Cumene is an intermediate in the manufacture of Acetone and Phenol. Cumene is at times bought out also. Acetone manufactured by them has similar qualities and characteristics as of imported product.
 - (iii) HCL manufacture basic organic chemicals and specialties like Phenol, Acetone, Phthalic Anhydride, Diacetone Alcohol, Dodecyl Phenol, Nonyl Phenol, Diphenyl Oxide, Isobutyl Benzene, Isophorone, Heat Transfer Media, Acetophenone. The imported Acetone and the Acetone manufactured by them is same in all respects.
 - (iv) Acetone manufactured by HCL/HOC is used in numerous organic synthesis either as an intermediate or as a solvent. The chemicals manufactured from Acetone includes Isophorone, Diacetone Alcohol, Methyl Methacrylate, Bisphenol A,

Rubber Chemicals and Cellulose Acetate. Acetone is also used as a solvent in the manufacture of paints and coatings.

- (v) Acetone imports have been steadily going up at a high growth rate, almost consistently, in the 1990's at an average rate of 78% per annum between 1993-94 and 1998-99 (from 1014 MT to 21870 MT). This spurt in imports, particularly during 1998-99 is on account of sharp decline in global Acetone prices. The spurt in imports accompanied by the drop in margins has adversely affected the industry to such an extent that if the same situation continues to exist the domestic Acetone industry may have to close down.
- (vi) The CIF rates of Acetone imported during 1995-96 was in the range of US \$ 490 to 880; in 1996-97 it was US \$ 380 to 490; in 1997-98 it was US \$ 440 to 530 which came down to US \$ 240 PMT in March 1999. This decline in the cost of import coupled with the reduction in Customs Duty from 50% to around 35% has adversely affected them. The net realisation of the domestic manufacturers have also been affected.
- (vii) Whereas the cost of production has been by and large increasing over a period of time, the domestic prices, which are a function of international prices (CIF India), import duty and the exchange rate have had to be drastically reduced in order to minimise the loss of market share. This has led to compression of margins.
- (viii) In view of the rapid fall in CIF India prices to an all time low in the past 5 years, there is a significant further spurt in (more than doubling of) import over and above the past five year average of 14454 TPA, and there is a further compression of margins equivalent to the compression of landed cost of import over and above current levels. Increased imports leading to loss of market share has led to lower production of sale leading to high fixed costs per ton.
- (ix) Due to these extremely low priced imports, Indian manufacturers had to reduce their prices from Rs.31/- Kg in January 1998 to Rs.21/-Kg in October 1998 to the end March 1999 price level of Rs.18/Kg (all prices being list prices) so that the net price after discounts nearly matches the landed cost of import at around Rs.15/Kg net of CVD setoff. Till end March 1999, there is a drop of Rs.13/Kg in list prices on a January 1998 level of Rs.31/Kg. There has been no corresponding reduction in the raw material prices. In view of this, the cost of manufacture remains high and profitability is under pressure.
- (x) HOC during 1998-99 recorded a profit of Rs.386 PMT in the first quarter, Rs.6980 PMT in the second quarter and Rs.447PMT in the third quarter but incurred a loss of Rs.1722 PMT in the fourth quarter. Similarly Herdillia made profits of Rs.3282 PMT and Rs.2264 PMT in the first and second quarters of 1998-99 but incurred a loss of Rs.1588 PMT and Rs.2096 PMT in the third and fourth quarter respectively.
- (xi) Due to the large scale Acetone imports (at substantially lower costs and long credit periods) flooding the Indian Markets, the situation is forcing the manufacturers to offer more credit period to the customers. The debtors, in case of both the companies have gone up substantially during the past few months elongating the working capital cycle finally resulting in a severe cash crunch. As a result, both the organisations are finding it difficult to pay to the suppliers on time. The debtors of Acetone have increased from 32 days in August 1998 to 38 days in March 1999.

- The organisations have had to borrow funds higher than the prevailing market rate resulting in a further loss of profitability.
- (xii) Herdillia's as well as HOC's performance parameters for credit rating have also deteriorated due to low Acetone prices making it further difficult to access funds at reasonable cost. This will have a further adverse impact on the profitability in the future as interest cost component will go up. This is very much imminent.
 - (xiii) Due to the liquidity crunch (and the consequent loss of profitability), both the manufacturers are finding it extremely difficult to access funds from financial institutions. This is, in turn, resulting in delay of implementation of the long-term plans to build Green-field Acetone capacities.
 - (xiv) Propylene is currently not importable due to grossly inadequate port infrastructure for artificially liquefied gases. Freight on Propylene is very high further making it difficult to import. Domestic prices of Propylene are more than 65% higher than the international f.o.b. prices. Over and above this, the domestic freight on Propylene is as high as another 15-20% of the domestic Propylene price.
 - (xv) In India, the cost of power, fuel, finance, transportation etc. is also higher than in other parts of the world where Acetone is produced. This contributes to higher cost of manufacture of Acetone (in India) and is a factor beyond the control of Indian Acetone producers.
 - (xvi) The international prices of the co-product of Acetone (i.e. Phenol) have also fallen sharply in the last one year because of which the combined landed cost of Acetone and Phenol has fallen sharply during the same period. Domestic prices of Phenol also have had to be lowered. Because of this, the combined net realisations and consequently the margins on Acetone and Phenol have been adversely affected. The combined landed cost of import of Acetone and co-product Phenol has significantly declined indicating deteriorating situation.
 - (xvii) HOC and HCL have been upgrading their technology and debottlenecking manufacturing facilities with the objective of reducing the operating costs per unit and increasing effective capacity to satisfy the increasing domestic demand from most of the sectors. To reduce the power cost, they have taken steps to setting up of captive power generation facilities by the co-generation route and gains would start accruing. They are planning to set up a World Scale Greenfield Phenol manufacturing facility either 100000 TPA or 150000 TPA (corresponding Acetone capacity of 60000 TPA expandable to 90000 TPA) at Dahej in Maharashtra or Gujarat State. There is a possibility of a co-operative effort between HOC and HCL. They intend to become internationally competitive by extending their capacities, upgrade and modernise technology with the help of technology suppliers and consultants.

F. FINDINGS

1. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting governments. Submissions made by various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below.

2. Product under Investigation

- (i) The product under investigation is 'Acetone' (also known as Dimethyl Ketone), a basic organic chemical with chemical formula CH_3COCH_3 .
- (ii) Acetone is manufactured using different processes including the Cumene route which is used by HOC and HCL, the Isopropyl Alcohol (IPA) based route and the Alcohol (Ethanol) based route. In the Cumene route, Acetone is produced by the oxidation of Cumene using air at elevated temperatures and pressures. The product is Cumene Hydroperoxide at lower concentration, which is then alkali washed and concentrated to a higher strength. This is then mixed with H_2SO_4 , which causes a cleavage reaction to give Phenol and Acetone. This is washed to remove acidity and distilled in a series of distillation columns to give Phenol, Acetone and unreacted Cumene (which is recycled for conversion to Phenol and Acetone). Cumene in turn is produced by the reaction between Propylene and Benzene in the presence of solid Phosphoric Acid catalyst at high pressures and elevated temperatures.
- (iii) In the IPA based route, Acetone is manufactured by Dehydrogenation of IPA. This conversion is carried out at elevated temperature in presence of a catalyst which is normally a metal or a metallic oxide supported over an inert material.
- (iv) In the Alcohol based route, Acetone is produced by Catalytic Ketonisation of Alcohol using steam at high temperatures. This process is generally followed by the sugar factories in India.
- (v) Acetone is produced in a single grade as colourless liquid with an agreeable ether-like odour.
- (vi) Acetone is used in numerous organic synthesis (of bulk pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals) either as an intermediate or as solvent. The chemicals manufactured from Acetone include Isophorone, Diacetone Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol-A. Besides, Acetone is used in the manufacture of certain Rubber Chemicals, Oxy-Acetylene, Cellulose Acetate and also as a solvent in the manufacture of Paints/Coatings.
- (vii) Acetone is classified under sub-heading 2914.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and under 29141100 of the Indian Trade Classification based on Harmonised Commodity Description and Coding System (ITC). This classification of Acetone under the Customs Tariff Act, 1975 and the Indian Trade Classification has been indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation.

3. Domestic Industry

- (i) In all eight domestic producers have capacity to produce Acetone with an effective Acetone capacity of 74770 MTpa. M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai (HOC) and M/s Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai (HCL) produce Acetone

through the Cumene route. NOCIL produces Acetone through IPA based route and the other five domestic producers namely Chaltan, Sirsilk, Krishna, Rajaram (Walwa) and Cordite units have production capacity for Acetone based on Alcohol.

- (ii) NOCIL have submitted that imposition of safeguard duty is not in public interest. They have also stated that since manufacture of Acetone through the IPA route is not economical, NOCIL does not produce significant volumes of Acetone for the merchant market and, therefore, the capacity available with NOCIL is effectively not available to the domestic industry. They have further stated that they have chosen to maximise the production of IPA, which offers better value addition/returns on investment. Increased production of IPA has led to reduced production of Acetone. Similarly, Cordite unit has stated that they have stopped production of Acetone since quite sometime and that as a consumer of Acetone, they are happy about the reduction in Acetone prices.
- (iii) M/s Krishna Sahkari Sakhar Karkhana Ltd. and M/s Rajaram Babu Patil SSK Ltd., although did not join the Applicants in filing this application, they have participated in the investigation and extended their support for imposition of safeguard duty on imports of Acetone. They have categorically stated that they had to suspend their production in view of increased imports at sharply reduced prices, which made production of Acetone unviable for them and that levy of safeguard duty will enable them to recommence the production of Acetone.
- (iv) The production of the eight domestic producers (in MT) during the period 1994-95 to 1998-99 is given in the Table below :-

Table 1
Production in MT

Year / Company	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
HOC	23576	27024	21333	27555	25096
HCL	11579	12790	14151	14803	16126
NOCIL	7277	6731	3209	1523	1021
Cordite	300	425	425	380	375
Krishna	0	1157	0	0	0
Rajaram	0	1429	166	0	0
Sirsilk	0	0	0	0	0
Chalthan	0	0	0	0	0
Total	42732	49556	39284	44261	42618

- (v) The application for imposition of safeguard duty on Acetone has been filed by HOC and HCL who had a combined capacity of 45950 MT (1998-99) of Acetone production. During 1998-99, they produced 41222 MT of Acetone out of a total of 42618 MT of Acetone produced in the country during 1998-99. HOC and HCL together, therefore, constitute a major proportion of domestic production. The

application by HOC and HCL is, therefore, considered to have been made on behalf of the domestic industry.

4. **Increased Imports**

- (i) Acetone is imported into India from Canada, China, Chinese Taipei, France, Finland, Germany, Japan, Korea DPR, Korea RP, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, United Kingdom and United States of America. Currently, the major exporters of Acetone to India are Germany, the Netherlands, Russia, South Africa, South Korea, Taiwan and USA. The import duty on Acetone that was 85% in 1993-94 was brought down to 65% in 1994-95, 50% in 1995-96, 40% in 1996-97 and to 30% + 2% + 3% in 1997-98. In 1998-99, Acetone attracted import duty @ 30% + 5% *ad valorem* excluding Additional Duty of Customs and Special Additional Duty of Customs.
- (ii) In 1994-95 a total of 9046 MT of Acetone entered into India mainly from Germany (1001 MT), Netherlands (826 MT), Philippines (1551 MT) and USA (4839 MT). In 1995-96, the imports of Acetone rose phenomenally to 18519 MT with major imports from Belgium (1037 MT), Chinese Taipei (978 MT), Germany (2549 MT), Korea (1452 MT), Netherlands (2100 MT), Singapore (820 MT) South Africa (7498 MT) and USA (1098 MT). The imports during 1996-97 increased further to 26228 MT with major imports from Germany (1429 MT), Netherlands (1415 MT), South Africa (11124 MT), UK (1597 MT) and USA (7561 MT). In 1997-98, the imports, however, declined to 16574 MT with major imports from Korea (1401 MT), Netherlands (637 MT), Singapore (1770 MT), South Africa (9030 MT) and USA (3547 MT). The imports in 1998-99 reached an all time peak to 29182 MT with major imports coming from South Africa (16350 MT), Korea (2975 MT), Netherlands (2571 MT), Russia (2040 MT), USA (1480 MT), Germany (1365 MT) and Taiwan (1005 MT).
- (iii) Doubts have been expressed by some parties about the authenticity of import data provided by the Applicants, particularly in respect of import data for the period 1998-99. The domestic producers in this regard have submitted that the data for the years up to 1997-98 has been taken from the DGCIS, Calcutta. Due to time lag in publication of DGCIS figures, for 1998-99 they have taken the data based on market intelligence sources. In regard to the authenticity of the import data, it is observed that the data provided by the Applicants for the period from 1994-95 to 1997-98 is based on the DGCIS statistics and is authentic. As far as 1998-99 data is concerned, it is observed that the Applicants have provided details of imports giving name of the vessel, date of arrival, quantity, port of loading and price etc. in the application. It is observed that no specific discrepancy in the import data for the period 1998-99 has been pointed out by any party. However, the import data of Acetone was subjected to verification. Kandla Custom House has confirmed imports of 15610.442 MT (15360.737 MT claimed by the Applicants) of Acetone and Mumbai Custom House has confirmed imports of 13472.549 MT (13410.691 MT claimed by the Applicants) of Acetone. The Applicants have claimed imports

of 98.960 MT of Acetone through Chennai Port. The difference between figures of imports confirmed by the Custom Authorities and that claimed by the Applicants is insignificant. The total imports of Acetone during 1998-99 were, therefore, 29182 MT. The Table below gives import figures of Acetone from 1994-95 to 1998-99.

Table 2
Imports in MT

Year	Imports	
	Quantity (MT)	Value (Rs. Mn.)
1994-95	9046	121.7
1995-96	18519	414.9
1996-97	26228	464.7
1997-98	16574	376.9
1998-99	29182	--

- (iv) The imports increased from 9046 MT in 1994-95 to 18519 MT in 1995-96 and to 26228 MT in 1996-97. In 1997-98, however, the imports declined to 16574 MT. Leaving aside 1994-95 when the imports were on the lower side, on an average during 1995-96 to 1997-98 the quantum of imports of Acetone into India was 20440 MTpa. In 1998-99, the imports jumped to 29182 MT i.e. an increase of about 42.8% over the average imports during 1995-98. As compared to the immediately preceding year 1997-98, the imports in 1998-99 increased by 76%. In comparative terms the imports were 21.17% of domestic production in 1994-95, 37.37% in 1995-96, 66.77% in 1996-97, 37.45% in 1997-98 and 68.47% in 1998-99. The domestic production, import figures and imports as % age of domestic production are given below in Table 3.

Table 3
Imports as % age of Domestic Production

Year	Domestic Production(MT)	Imports(MT)	Imports as %age of Domestic Production
1994-95	42732	9046	21.17
1995-96	49556	18519	37.37
1996-97	39284	26228	66.77
1997-98	44261	16574	37.45
1998-99	42618	29182	68.47

- (v) The imports have thus increased both in absolute terms as well as compared to domestic production.

5. Threat of Serious Injury

(a) Domestic Producers Affected by Imports of Acetone

- (i) Clause 6 (c) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, defines 'serious injury' to mean an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry and Sub-clause (d) defines 'threat of serious injury' to mean a clear and imminent danger of serious injury. Further in determining whether increased imports have caused or threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Annex to the Safeguard Duty Rules requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment.
- (ii) An important issue regarding the actual capacity of Acetone available to the domestic industry has been raised by various parties. It is considered necessary to discuss this issue first, before proceeding to analyse various factors of injury.
- (iii) The Applicants have claimed an effective Acetone capacity of 74770 MTpa in 1998-99 available with the eight domestic producers, who in all produced 42618 MT of Acetone, which accounted for only 57% utilisation of the effective Acetone capacity. It has been argued by various parties that the Applicants have included capacity of those companies also who have not been producing any or producing negligible quantities of Acetone since 1994-95. These include NOCIL with capacity of 14000 MTpa who had run their plant at 52% in 1994-95, 48% in 1995-96, 23% in 1996-97, 11% in 1997-98 and 7% in 1998-99. The Alcohol based Acetone manufacturing units Chalthan and Sirsilk with capacity 3000 MTpa and 1500 MTpa respectively did not produce Acetone since 1994-95, Rajaram (Walwa) and Krishna produced only 2586 MT in 1995-96 and 166 MT in 1996-97 against their capacity of 4500 Mtpa each with no production of Acetone thereafter. In respect of Cordite unit with capacity of 1320 MTpa, it has been argued that this unit was set up purely for Ministry of Defence and, therefore, this unit does not meet demand of other domestic consumers.
- (iv) In this regard, it is observed that NOCIL have submitted that manufacture of Acetone through the IPA route is not economical; they do not produce significant volumes of Acetone for the merchant market and, therefore, the capacity available with them is effectively not available to the domestic industry. In view of this specific assertion of NOCIL, their capacity cannot be considered to be effectively available to the domestic industry.
- (v) As regards Chalthan and Sirsilk units, it is observed that these units have not responded to the Notice of Initiation, nor have they submitted reply to the Questionnaires sent to them. These units have not produced Acetone since 1994-95. In view of the above facts, it appears that both Chalthan and Sirsilk are not

- interested in re-commencing their Acetone production and hence their Acetone manufacturing capacity cannot be considered to be effectively available to the domestic industry.
- (vi) The Cordite unit have submitted that in view of the increase in price of Ethyl Alcohol, their raw material for the manufacture of Acetone, they have stopped manufacture of Acetone since quite sometime. They are not affected directly by the excessive imports of Acetone and that as a consumer of Acetone, they are happy about the reduction in Acetone prices. In view of their above submission, their capacity also is not considered to be effectively available to the domestic industry.
- (vii) Krishna and Rajaram (Walwa) units have reaffirmed their intention to produce Acetone and have requested for imposition of safeguard duty on imports of Acetone. They had produced 2686 MT of Acetone in 1995-96 and 166 MT in 1996-97. Both of them have a capacity of 4500 MTpa each to produce Acetone. The argument of some parties to exclude their capacities from the total available Acetone capacity as they have not produced Acetone in the last few years is not acceptable as these Acetone capacities cannot be disregarded simply because these units have not been able to produce Acetone for the last couple of years. This is a manifestation of serious injury suffered by them. While they suffered almost complete loss of production, if they are not allowed to be considered as a part of the domestic Acetone industry on that ground alone, it would amount to adding insult to the injury. They have categorically mentioned their desire to recommence production of Acetone. In this regard, it is also important to observe that world over many units produce Acetone using Alcohol based route. Production of Acetone in India using Alcohol as raw material is, therefore, no exception.
- (viii) In view of the above discussion, it is considered that the injury analysis needs to be carried out in respect of HOC, HCL, Krishna and Rajaram (Walwa) units alone (excluding NOCIL, Cordite, Chalthan and Sirsilk units), hereinafter, referred to as the 'affected domestic producers'. The Acetone capacity and production of the affected domestic producers for the period 1994-95 to 1998-99 were as given in Table 4 below.

Table 4
Capacity and Production of Affected Domestic Producers

Producers	Capacity					Production				
	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
HOC	24640	24640	24640	27650	27650	23576	27024	21333	27555	25096
HCL	12000	14400	16170	16170	18300	11579	12790	14151	14803	16126
Krishna	4500	4500	4500	4500	4500	0	1157	0	0	0
Rajaram	4500	4500	4500	4500	4500	0	1429	166	0	0
Total	45640	48040	49810	52820	54950	35155	42400	35650	42358	41222

(b) Domestic Production

- (i) An analysis of various factors attributing to the present status of the 'affected domestic producers' reveals that the domestic production was 35155 MT in 1994-95. The domestic production increased to 42400 MT in 1995-96 but then declined sharply to 35650 MT in 1996-97. The domestic production then increased to 42358 MT in 1997-98 and declined to 41222 MT in 1998-99. The domestic production that registered a growth of about 18.8% in 1997-98 over the production during 1996-97 registered a fall of 2.68% in 1998-99 over 1997-98.
- (ii) It has been mentioned earlier that eight producers in the country had the capacity to produce Acetone through different manufacturing processes using different raw materials. These producers have been clubbed in three different categories, namely Alcohol based producers, IPA based producers and Cumene based producers. It has been argued by various parties that these producers falling in different categories have different economies of production and that some of the producers have not been producing Acetone for the last few years, besides NOCIL has turned to be an importer than producer of Acetone. The Applicants have explained this peculiar situation of Acetone industry by stating that the injury to the domestic Acetone industry has been caused in stages. The Applicants have explained that the Indian Acetone manufacturing industry started suffering since 1996-97 due to large imports at substantially lower prices. In this regard it is observed that the imports peaked to a high of 26228 MT in 1996-97 at an average CIF price of Rs. 17718 PMT as compared to 18519 MT in 1995-96 at an average CIF price of Rs. 22407 PMT. This resulted in the domestic production (all units included) which reached a peak of 49556 MT in 1995-96 from 42732 MT in 1994-95, to decline to a low of 39284 MT in 1996-97. The first sector of the industry to be affected was Alcohol based producers whose production reduced to 591 MT in 1996-97 which in the previous year i.e. 1995-96 was 3011 MT, 425 MT by Cordite, 1429 MT by Rajaram (Walwa) and 1157 MT by Krishna. After 1996-97, these units except Cordite had to suspend their production. This is in the background of the fact that between 1980-81 and 1996-97, the production of sugarcane in India had increased resulting in improved availability of Alcohol which should have led to increased production of Alcohol based Acetone. On the contrary, these units had to discontinue with their Acetone production after 1996-97.
- (iii) The second sector of the domestic industry to suffer was IPA based Acetone producer – NOCIL who suffered a loss of more than 50% in their production of Acetone in 96-97 which stood at 3209 MT as compared to 6731 MT in 1995-96 and 7277 MT in 1994-95. Its production reduced further to 1523 MT in 1997-98 and to 1021 MT in 1998-99. This also resulted in turning of NOCIL into a major importer of Acetone than a producer of Acetone.
- (iv) The applicant companies, which have been termed as compulsive producers of Acetone by some of the parties also faced a very severe competition from the imports of Acetone, but they were prevented from either suspending or curtailing

their production in order to save their dedicated investment in Phenol/Acetone plants by running their plants optimally so as to minimise the injury, even at the cost of incurring losses. However, they also suffered loss of production. HOC which produced 27555 MT in 1997-98, produced only 25096 MT in 1998-99. HCL achieved a slightly better production of 16126 MT in 1998-99 as compared to 14803 MT in 1997-98. Taken together, the two Cumene based applicant companies produced 41222 MT of Acetone in 1998-99 as compared to 42358 MT in 1997-98.

- (v) The domestic producers of Acetone have thus suffered loss of production of Acetone in 1998-99 as compared to 1997-98.

(c) Capacity Utilisation

- (i) As discussed at (a) above, the Acetone capacity available to the domestic industry is that of four producers, namely HOC, HCL, Krishna and Rajaram (Walwa) units. They had a total Acetone capacity of 45640 MTpa in 1994-95 which increased to 48040 MTpa in 1995-96, 49810 MTpa in 1996-97, 52820 MTpa in 1997-98 and to 54950 MTpa in 1998-99. During this period they collectively accounted for production of 35155 MT, 42400 MT, 35650 MT, 42358 MT and 41222 MT of Acetone respectively. Their capacity utilisation which peaked to a high of 88.3% in 1995-96 from 77% in 1994-95, suffered a severe setback in 1996-97 when it declined to 71.6%. The capacity utilisation again registered a growth to 80.2% in 1997-98 but thereafter declined to 75% in 1998-99. The domestic producers of Acetone have thus suffered a loss in capacity utilisation.
- (ii) It has been argued by some of the interested parties that the Applicants achieved a high level of capacity utilisation of 87% to 102% which are extremely high rates for chemical products and which most of the global major chemical manufacturers are unable to attain. In this regard, it is observed that HOC achieved as high as 103% of capacity utilisation in 1995-96 and HCL achieved 96.5% capacity utilisation in 1994-95. In the year 1998-99, HOC and HCL, however, achieved 91% and 88% capacity utilisation respectively. While it may be possible that these capacity utilisation may be considered to be at a high rate in the context of global major chemical manufacturers, in the context of their own past performance, both HOC and HCL registered a fall in capacity utilisation. The 'affected domestic producers' as a whole also lost on capacity utilisation in 1998-99 which stood at 75% as compared to 88.3% in 1995-96, a loss of 13.3 percentage points.

(d) Sales

- (i) The Table below gives the domestic sales figures of the 'affected domestic producers' (including captive consumptions and sales in the domestic market on deemed export basis) for the period 1994-95 to 1998-99.

Table 5
Domestic Sales in MT

Year	HOC	HCL	Krishna	Rajaram (Walwa)	Total
1994-95	21411	11567	0	0	32978
1995-96	26694	12380	1157	1429	41660
1996-97	19817	14089	0	166	34072
1997-98	26568	14797	0	0	41365
1998-99	25839	16068	0	0	41907

- (ii) It would be seen from this Table that the 'affected domestic producers' achieved domestic sales (including captive consumption and sales on deemed export basis) of 32978 MT in 1994-95 which increased to 41660 MT in 1995-96 and declined to 34872 MT in 1996-97. The domestic sales thereafter picked up in 1997-98 to 41365 MT and then increased by about 1.3% to 41907 MT in 1998-99. This marginal increase in domestic sales in 1998-99 needs to be seen in the background of the growth in the total apparent consumption (domestic sales + imports) of the domestic market (Table 6) which registered a growth of about 21.1% in 1998-99 (72483 MT) as compared to 1997-98 (59842 MT). The domestic producers could achieve this meagre growth of 1.3% in sales as compared to 21.1% increase in apparent consumption only at the cost of a drastic reduction in their average sales price which was reduced to Rs. 18 per kg in March, 1999 as compared to Rs. 28 per kg in March, 1998.

Table 6
Apparent Consumption in MT

Year / Comp any	HOC	HCL	NOCIL	Cord -ite	Kris- hna	Raja- ram	Chal -than	Sir- silk	Imports	Total
1994-95	21411	11567	7277	300	-	-	-	-	9046	49601
1995-96	26694	12380	6731	425	1157	1429	-	-	18519	67335
1996-97	19769	14089	3209	425	-	166	-	-	26228	63886
1997-98	26568	14797	1523	380	-	-	-	-	16574	59842
1998-99	25839	16068	1021	375	-	-	-	-	29182	72483

- (iii) HOC and HCL lost on net sales realisation in 1998-99 as compared to 1997-98. HOC in 1997-98 made an average sales realisation of Rs. 21713 PMT (Bulk) which in 1998-99 declined to Rs. 18919 PMT (Bulk). In the case of HCL, the average

sales realisation of Rs. 24682 PMT (Bulk) in 1997-98 declined to Rs. 20982 PMT (Bulk) in 1998-99. (Average sales realisation in 1998-99 for HOC and HCL have been worked out for Acetone in bulk on the basis of quarterly figures provided by them).

(e) Stocks

The closing stock of the 'affected domestic producers' was 1148 MT at the end of 1997-98 which reduced to 437 MT at the end of 1998-99. In this regard, it is observed that HOC and HCL have claimed that Acetone is a hazardous chemical, storage capacity of which needs to be approved by the Explosives Deptt. They, therefore, maintain the minimum stocks either by selling their production or curtailing the production. In view of this explanation, stocks position of Acetone cannot be considered to be truly reflective of serious injury to them.

(f) Employment

The domestic producers have submitted that the talented, experienced and contributing employees have started resigning from the services of the companies thereby leading to irreparable loss to the knowledge pool and skills inventory of the domestic industry. They are also facing difficulties in attracting new recruits as they see lack of growth prospects in the limping Acetone industry. In this regard, it is observed that the number of employees working in the Acetone plant of HOC reduced from 474 in 1995-96 to 447 in 1998-99 and in case of HCL, the number of employees working in their Acetone plant has reduced from 62 in 1995-96 to 61 in 1998-99.

(g) Productivity

The 'affected domestic producers' have lost production from 42358 MT in 1997-98 to 41222 MT in 1998-99 and they have also lost on productivity i.e. quantum of production per employee engaged by them which has come down from 82.89 MT per employee in 1997-98 to 81.15 MT per employee in 1998-99.

(h) Profitability

- (i) HOC and HCL have submitted that they follow the pricing policy of fixing domestic prices of Acetone in line with the expected landed cost of Acetone. As a result of increased imports and fall in the import prices, they had to make several adjustments in their Acetone prices to prevent their customers from shifting to imports completely. On an average, they reduced their selling price from Rs. 28 per kg in March, 1998 to Rs. 18 per kg in March, 1999 i.e. a decline of about 36% in the list price. HCL's net realisation of Acetone (bulk), which was Rs. 25883 PMT in the first quarter of 1998-99 reduced to Rs. 17787 PMT in the last quarter of 1998-99 i.e. a decline of more than Rs. 8000 PMT. In case of HOC, the net realisation dropped from Rs. 22626 PMT in the first quarter of 1998-99 to Rs.

15230 PMT in the last quarter of 1998-99 i.e. a decline of more than Rs. 7000 PMT. The reduction in net realisation has had serious effect on profitability of HOC and HCL, both of whom have started incurring losses as the reduction in Acetone prices was not accompanied by corresponding reduction in raw material prices.

- (ii) Some of the parties have claimed that safeguard proceedings are product-specific proceedings and, therefore, the profitability of HOC and HCL should be considered only as far as it relates to their Acetone production. This is a valid argument. Both HOC and HCL have furnished their Acetone specific details of cost of production and realisation etc. which have also been subjected to verification. It is observed that both HOC and HCL have suffered severe loss of profit in 1998-99 and incurred losses in later period of 1998-99.
- (iii) HOC and HCL were also forced to offer more credit period to their Acetone customers. The debtors, in case of both the companies have gone up substantially in the later period of 1998-99, elongating the working capital cycle, which led to cash crunch. They have had to borrow funds at inter-corporate deposits at rates substantially higher than the prevailing market rate, resulting in further loss of profitability. Their performance parameters for credit rating have also deteriorated due inter-alia to low Acetone prices making it further difficult to access funds at reasonable cost, having an adverse impact on the profitability in future as the interest cost component will go up. The loss in profitability had also its impact on share prices of both the companies which diminished in 1998-99 at a rate faster than the BSE Sensex. Due to the liquidity crunch and the consequent loss of profitability, both the companies are also finding it difficult to access funds from the financial institutions. This is, in turn, resulting in delay of implementation of their long-term plans to build Greenfield Acetone capacities.
- (iv) In regard to profitability of HOC and HCL, some of the parties have made reference to some Press Reports. Business Line – April 11, 1999 reports HOC's profitability under pressure due to the high interest costs and depreciation on account of its recently completed projects – Chloralkali and Hydrogen Peroxide. Press Trust of India – July 8, 1999 has reported for HOC 7% increase in production, 16% in sales and 4% in capacity utilisation. Business Lines – June 20, 1999 in the context of HCL reported that the company would continue to get swamped by global commodity price swings and demand-supply imbalances and that the adverse impact of global commodity price swings has been aggravated by domestic infrastructure-related problems. The Report also refers to the impact on HCL from other group companies or subsidiaries. They have argued that loss of profitability of the two companies HOC and HCL are thus on account of these factors enumerated in the Press Reports and the same should not be attributed to the Acetone operations of the two companies. In this regard, it is pertinent to mention that for the present investigation what is considered relevant is the Acetone operations related profitability of the two companies and not their overall profitabilities. The Press Reports refer to the overall operations of HOC and HCL.

and are not Acetone specific. The findings in the present investigation are, however, based only on the Acetone-specific factors.

- (v) It has also been argued by some of the parties that the Applicants have in the past made huge profits and, therefore, they should not complain against the losses, if suffered now. As regards the present injury in the wake of past profits, it is observed that for the determination of injury various factors have to be evaluated in an objective manner. If it appears that the domestic industry is suffering a significant overall impairment, a determination of existence of serious injury can be made. It also needs to be kept in mind that the present investigation concerns determination of existence of a threat of serious injury i.e. a situation where serious injury is clearly imminent. The turning of profits into losses is, therefore, to be viewed in the above background and the past profits cannot stand in the way of determination of existence of a threat of serious injury.

(i) Threat of Serious Injury

As already mentioned, Clause 6(d) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines 'threat of serious injury' to mean a clear and imminent danger of serious injury and Clause 6(c) of this Section defines 'serious injury' to mean an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry. An analysis of various parameters as discussed above clearly brings out that the 'affected domestic producers' in 1998-99 have witnessed severely depressed conditions of operation. As compared to 1997-98, they have lost on account of production, capacity utilisation, sales realisation, productivity and profitability. They achieved a small growth in sales but which was far below the growth in apparent consumption, that too only at the cost of a sharp reduction in the sale price. Serious injury to the domestic industry is thus clearly imminent. It is, therefore, observed that the domestic industry is suffering a threat of serious injury.

6. Cause of Injury

(a) Supply-Demand Gap

- (i) A number of issues have been raised by various parties justifying the increased imports or to show that the injury caused to the domestic industry was not on account of increased imports but on account of other factors. The most important amongst these issues is the supply-demand gap. Some of the parties have claimed that the cause of injury to the domestic industry was not increased imports as the imports were necessitated to meet the gap between domestic supply and domestic demand. It may be appropriate to mention at the outset that HCL, which was the first unit to produce Acetone in India was set up in 1968 with an initial capacity of 6000 MTpa of Acetone. In 1979 it requested for expansion of capacity to 12000 MTpa, but the request of the Company was turned down by the Government on 28.7.1980 as per the then prevailing law, observing that HCL was a large undertaking due to interconnection with EID Parry and had a dominant presence in

the Indian market. The question of substantial expansion, therefore, did not arise till HCL came out of MRTTP clutches. HCL tried for MRTTP de-registration for several years but were never successful till the scrapping of relevant Sections of MRTTP Act (in 1991) related to substantial expansion or new projects. However, HCL gradually increased their effective Acetone Capacity to 12000 MTpa in 1994-95, mainly through investments in debottlenecking financed entirely through internal accruals. The capacity has further been increased to 14400 MTpa in 1995-96, 16170 MTpa in 1996-97 and to 18300 MTpa in 1998-99. In the case of HOC, the effective Acetone capacity of 24640 MTpa in 1994-95 has been increased to 27650 MTpa in 1997-98. The other two units namely Krishna and Rajaram (Walwa) have capacity of 4500 MTpa each for the production of acetone. Thus, in 1998-99, the 'affected domestic producers' had an effective Acetone capacity of 54950 MTpa available to the domestic industry. They collectively produced 41222 MT of Acetone in 1998-99 which accounted for 75% capacity utilisation in 1998-99. The apparent consumption of Acetone during 1998-99 was 72483 MT. In the previous years, however, the apparent consumption of Acetone was 49601 MT in 1994-95, 67335 MT in 1995-96, 63886 MT in 1996-97 and 59842 MT in 1997-98. It is clear from the above data that the apparent consumption of Acetone increased substantially in 1995-96 as compared to 1994-95, but declined thereafter in 1996-97 and 1997-98. Obviously, these figures are not reflective of the actual demand during the particular year as the possibility of excess imports and carrying forward of stocks, to take maximum advantage of the existing circumstances cannot be ruled out. It is, therefore, considered appropriate to average out the apparent consumption during this period which works out to 60166 MTpa. As compared to this, the apparent consumption in 1998-99 was 72483 MT which works out to about 20.5% more than the average apparent consumption during 1994-98. The apparent consumption in 1998-99 works out to be about 21.1% more than 1997-98. No one has envisaged or claimed such a growth in the domestic Acetone consumption. M/s Crescent Organics Ltd. have asserted that the actual consumption pattern of Acetone in India is given in an article on "Acetone : A Techno-Commercial Profile" by Dr. Ajit Joshi and Pankaj Dutta, published in Chemical Weekly, December 17, 1996 issue, which stipulates a total actual consumption of Acetone of 29000 MT in 1985-86 which increased to 48000 MT in 1990-91, 54000 MT in 1994-95 and projected demand of 64750 MT in 1999-2000. It is observed from the data provided that the Acetone consumption grew at an average of about 10.6% per annum (compounded) during the period 1985-86 to 1990-91. The growth, however, reduced to about 3% per annum (compounded) on an average during 1990-91 to 1994-95. The growth between 1994-95 to 1999-2000, as per the report works out to about 3.7% per annum (compounded). The Acetone consumption in 1998-99 as per this report should have been 62440 MT. M/s Crescent, however, have mentioned that the available published data has been based on very conservative estimates. As compared to this calculation of 62440 MT in 1998-99, the Applicants have claimed the actual consumption of Acetone to be 68749 MT in 1998-99. They have, however, worked out this figure by simple extrapolation based on the past trend (and by using the material balance method).

In view of the above analysis, it appears that the figure of 68749 MT is a more realistic estimate of Acetone consumption during 1998-99.

- (ii) The actual consumption figure of 68749 MT in 1998-99 also includes the estimated 12000 MT of Acetone requirement of NOCIL. NOCIL themselves accounted for an effective Acetone capacity of 14000 MTpa. The 'affected domestic producers' had a total of 54950 MTpa effective Acetone capacity in 1998-99. Taking NOCIL's capacity also into account, the 'effective Acetone capacity' would have been 68950 MT. Till some time back NOCIL were themselves a major producer of Acetone. They, however, curtailed their production drastically and turned into a major user of imported Acetone. It would, therefore, not be appropriate to expect the 'affected domestic producers' to have taken into account NOCIL's requirement. Excluding NOCIL's requirement, the domestic demand in 1998-99 works out to about 56750 MT as against the effective Acetone capacity of 54950 MTpa available with the 'affective domestic producers', which more or less matches with the domestic demand.
- (iii) Crescent Organics Ltd. have dwelled at length about the inefficiency of the Alcohol based Acetone producers. They have also produced extracts from various reports and have furnished data regarding cost of production of Acetone through Alcohol route etc. In this regard it is observed that the cost of production of Acetone through Alcohol route has been worked out taking market price of Alcohol as the basis. This does not appear to be relevant in the context of Krishna and Rajaram (Walwa) both of which are sugar mills having in-house capabilities of producing Alcohol/Acetone. Many factors such as freight, sales tax etc. would not be relevant for these units and the cost of production in their case will be much lower. Besides, these units already have existing Acetone plants and they may have their own compulsions and commitments to run these plants for production of Acetone. The option to operate their plants or not lies with them which cannot be denied by anyone else. If they in their wisdom have decided to re-commence production on imposition of safeguard duty, it is their decision, which needs to be respected and to be taken into account. They have operated their Acetone plants in the past and produced substantial quantities of Acetone. There is, therefore, no reason now to believe that they shall not do the same again once the safeguard duty is imposed.
- (iv) As mentioned above, the Applicants have upgraded their production capacity gradually from 36640 MTpa in 1994-95 to 45950 MTpa in 1998-99 i.e. an improvement of about 25% in 1998-99 over 1994-95. They, however, could not utilise their production capacity to the full extent and were constrained to produce only 41222 MT in 1998-99. The Applicants did in the past achieve over 100% capacity utilisation. In 1995-96, the Applicants achieved 102% capacity utilisation. They could have made use of the effective capacity available with them in 1998-99 also. HCL and HOC on a quarterly basis produced 7811, 12169, 10177 and 11071 MT in the 1st, 2nd, 3rd and 4th quarter of 1998-99 respectively. In the 1st quarter the lesser production may have been on account of shut-down of the plants of the Applicants for some time for upgrading their production facility etc. In the 2nd

quarter, however, they produced 12169 MT. On a pro-rata basis, they could have produced 44318 MT ($7811 + 12169 \times 3$) but they produced only 41222 MT. The Applicants thus lost about 3000 MT of production and the other two units namely Krishna and Rajaram (Walwa) did not produce any quantity of Acetone. It is, therefore, not correct to say that the domestic producers were not able to produce more Acetone to meet with the domestic demand and that whatever imports have taken place were due to the inability of domestic producers to cater to the domestic demand. On the contrary, the cheaper imports restrained domestic producers to achieve their full capacity utilisation and also caused depression of the Acetone price in the domestic market.

(b) Loss of Exports

It has also been claimed that the reason for the woes of the domestic industry is loss of its export market that has declined to 26 MT in 1998-99 as compared to 2263 MT in 1996-97 and 333 MT in 1997-98 and not the imports of Acetone. In this regard it is important to keep in mind that the production line for production of Acetone is common both for the domestic consumption and for the export market. A domestic industry that was not able to compete in the domestic market could hardly have been expected to compete in the international market, specially when the domestic supplies were the major market for the domestic industry and exports constituted only a fraction of its market. The injury caused to the domestic producers by the increased imports, therefore, had its effect on the export performance of the domestic producers as well. Nevertheless, the domestic producers did supply 2250 MT of Acetone in 1997-98 and 2272 MT in 1998-99 under the Deemed Export Scheme, which are considered as exports without goods physically leaving the Indian shore. This argument, therefore, is not tenable.

(c) Market Share Taken Over by Imports

- (i) The 'affected domestic producers' had a market share of 32978 MT i.e 66.5% in the total apparent consumption of 49601 MT in 1994-95. Their market share fell down to 61.4% in 1995-96 and to 53.1% in 1996-97 before rising to 69.1% in 1997-98 and then again falling to a low of 57.8% in 1998-99. The share of imports in the apparent consumption during this period increased from 33.5% in 1997-98 to 38.1% in 1995-96 and 46.7% in 1996-97 which decreased to 30.9% in 1997-98 but again increased to a high of 42.2% in 1998-99. On a comparative basis the share of imports has increased by about 36.6% in 1998-99 over 1997-98 whereas the share of domestic sales has decreased by about 19.6%. The Table below gives the market share of the domestic producers from 1994-95 onwards.

Table 7
Share of Imports in Apparent Consumption

Year	Domestic Sales (MT)	Total Apparent Consumption (MT)	Share of Dom. Sales in App. Cons. (%)	Share of imports in App. Cons. (%)
1994-95	32978	49601	66.5	33.5
1995-96	41660	67335	61.9	38.1
1996-97	34022	63886	53.3	46.7
1997-98	41365	59842	69.1	30.9
1998-99	41907	72483	57.8	42.2

The total import figures also include the figures of imports by NOCIL who have represented as an importer in this investigation rather than as producer of Acetone. Their demand of Acetone for use in the manufacture of downstream products as well as their Acetone capacity have not been considered in analysing the demand-supply position of Acetone. It would, therefore, have been useful to analyse market share taken over by imported Acetone by excluding NOCIL's imports. They were, therefore, asked to furnish details of Acetone imported by them which they have not provided. In the absence of these figures, this analysis cannot, therefore, be carried out.

- (ii) The total apparent consumption in 1997-98 stood at 59842 MT which increased by 21.1% to 72483 MT in 1998-99. The domestic sales, however, did not grow at the same pace. The 'affected domestic producers' who should have achieved sales of (41365 X 121.1%) 50093 MT could sale only 41907 MT of Acetone in the domestic market during this period (including 2272 MT supplied on deemed export basis by HOC). The domestic producers thus lost a sale of 8186 MT which was taken over by the increased imports which captured an additional market of (29182 – 16574 X 121.1%) 9111 MT taking into account the growth of 21.1% in the apparent consumption.

(d) Price of Imports

- (i) It has been argued by some of the parties that the Applicants have complained of cheaper imports and if the injury caused to them is on account of prices of the imports, the remedy lies elsewhere and not by way of a safeguard action. This argument, however, does not appear to be reasonable. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 which empowers the Central Govt. to impose safeguard duty stipulates that "If the Central Govt., after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article". It is amply clear from a plain reading of this Section that conditions under which the increased imports take place needs to be

investigated for imposition of safeguard duty and, therefore, price at which imports entered into India needs surely to be looked into as price is one of the most important factor that needs consideration in taking a decision to source material. Besides, the Annex to the Safeguard Duty Rules requires that "when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports. In such cases, the Director General may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate". Even in accordance with this provision the price at which imports entered into India would need to be considered to find out whether factors like dumping or subsidisation existed. It is, therefore, considered necessary to examine the prices at which the imports entered into India and whether those prices caused serious injury to the domestic industry and whether factors other than increased imports existed at the same time.

- (ii) No assertion by the Applicants or by any other party has been made, leave aside any evidence having been produced that the Acetone imports into India were dumped or subsidised. From the import data provided in Table-2, it is observed that the landed cost (CIF + import duty) of imported Acetone during the period 1994-95 to 1998-99 on an average was about Rs. 22200 PMT in 1994-95 (13454 X 1.65), Rs. 33610 PMT (22407 X 1.5) in 1995-96, Rs. 24805 PMT (17718 X 1.4) in 1996-97, Rs. 30698 (22739 X 1.35) in 1997-98 and Rs. 18698 (13850 X 1.35) in 1998-99. Tabulated below are the imports of Acetone into India during this period and the landed cost.

Table 8
Landed Cost of Imports

Year	Imports (MT)	Average CIF (Rs.)	Landed Cost (average) Rs. / MT
1994-95	9046	13454	22200
1995-96	18519	22407	33610
1996-97	26228	17718	24805
1997-98	16574	22739	30698
1998-99	29182	13850 *	18698

(* worked out from import data for 1998-99)

Both the Applicants and some Respondents have relied upon the ICIS-LOR data according to which the average price of imported Acetone for Asia – Pacific was US \$ 488 PMT in 1994, US \$ 820 PMT in 1995, US \$ 427 PMT in 1996, US \$ 433 PMT in 1997, US \$ 360 PMT in 1998 and US \$ 265 PMT in the first quarter of 1999. The prices thus after peaking at US \$ 820 PMT in 1995 have been sliding down year after year. The landed cost of imported Acetone, however, did not follow the same trend exactly owing to changes in various factors such as exchange rate and rate of import duty etc. The landed cost of imported Acetone peaked at Rs. 33610 PMT in 1995-96 and declined to Rs. 24805 PMT in 1996-97. With the reduction in landed cost, the imports increased from 18519 MT in 1995-96 to

26228 MT in 1996-97. The landed cost of imports in the next year i.e. 1997-98 increased to Rs. 30698 PMT and the imports declined to 16574 MT. In 1998-99 the landed cost reduced to Rs. 18698 PMT and the imports have shot up to 29182 MT. It is therefore, observed that the quantum of imports of Acetone into India depended upon the landed cost and the cheaper imports compelled the domestic producers to reduce their prices. The domestic producers have submitted that they had to make several adjustments in the price in order to match the domestic prices with the expected landed cost of Acetone. Apart from reducing the list price of Acetone, the domestic producers had to offer various additional discounts to prevent their customers from shifting to imports completely.

- (iii) Another argument that has been made by some of the parties in the context of price of imported Acetone is the cyclic nature of Acetone prices. They have submitted that the chemical industry worldwide is a cyclical industry characterised by periodical ebbs and flows and that the cyclical trend is dependent on various factors which affect the entire demand and supply situation in the context of the global market. In this regard, the Table below gives the details of CIF prices of Acetone in US \$ for the period July, 1994 to March, 1999.

Table 9
CIF Prices of Acetone

Month	US sourced CIF	Europe sourced CIF	Far-East Asia	CIF India
July, 1994	437	392		490
Nov., 1994	767	798		800
May, 1995	909	840		880
July, 1995	926	856		850
Oct., 1995	909	701		725
Mar., 1996	554	470		490
May, 1996	442	420		490
Aug., 1996	365	360		380
Nov., 1996	348	360		380
Mar., 1997	403	403		400
May, 1997	415	437		440
June, 1997	435	465		440
Sept., 1997	552	522		470
Nov., 1997	588	559	570	530
Jan., 1998	595	625	560	480
Feb., 1998	540	606	540	470
Mar., 1998	461	550	480	450
April, 1998	410	480	465	450
May, 1998	360	465	390	360
June, 1998	340	445	385	340
July, 1998	300	440	350	305
Aug., 1998	283	420	340	275

Sept., 1998	273	270	335	260
Oct., 1998	270	260	300	260
Nov., 1998	270	255	295	260
Dec., 1998	270	275	290	260
Jan., 1999	266	275	292	260
Feb., 1999	270	280	295	250
Mar., 1999	270	285	297	240

(Source – Provided by the Applicants)

It is seen from the data in the Table above that the CIF prices of Acetone in US \$ MT started rising sharply in late 1994 and were at their peak in 1995. Thereafter the prices started coming down and reached a level of US \$ 240 PMT in March, 1999. In between the prices increased to some extent during the second half of 1997 and early 1998. The rise, however, was much less than the peak prices prevailing in mid-1995. The changes in CIF prices of Acetone as seen from the Table above does not support that the imported Acetone had any cyclical variations. Besides, the past trends are no guarantee for future behaviour as the global scenario has been changing continuously. The domestic industry suffering injury can also not be left to fend for itself waiting for the cycle to reverse. The revival of the domestic industry may become difficult or impossible, if the serious injury suffered by it is not redressed timely and left to the mercy of import prices firming up.

- (iv) Some of the parties have questioned the need of safeguard duty in the wake of recent improvement in international and domestic prices of Acetone. It has been claimed by them that the prices of imported Acetone have firmed up to a level of about US \$ 450 PMT in the mid-1999. This claim of US \$ 450 appears to be much exaggerated as the Applicants have mentioned actual imports during September, 1999 at CIF price of US \$ 310 PMT into India. They have also provided details of 3448 MT of Acetone imported through Mumbai port during April, 1999 to August, 1999 at CIF prices ranging between US \$ 245 PMT to US \$ 252 PMT except one consignment of 950 MT at US \$ 284.74 PMT and another consignment of 12.64 MT at US \$ 834.27 PMT. The Applicants have also submitted that imports into India are transacted on spot mode and, therefore, only the Arrival prices in India are important and relevant for pricing of Acetone in an apparently rising market. On the other hand, in a falling price situation, to prevent large quantities of imports being booked, one has to go by the Booking Price Parity for fixation of domestic prices. The domestic industry, therefore, tends to lose out in both rising as well as falling markets. Besides, this argument, suffers from various infirmities. The investigation into the serious injury suffered by domestic industry is based on the facts prevailing during the period specified in the Notice of Initiation which is 1994-95 to 1998-99. All the parameters reflecting on the state of the domestic industry, including the cost of production of Acetone by the domestic producers etc. have also been considered for this period. The Applicants have submitted that procurement prices for Propylene and Benzene have gone up by 15% in the case of HCL till end of June, 1999. In the case of HOC, the cracked LPG (Propylene) prices have gone up by 80% between April and beginning September, 1999.

Benzene prices have gone up by 24% and LSHS prices have gone up by 40% during the same period. The increase in the prices of raw materials will have its impact on the cost of production pushing it up substantially. If the import prices for Acetone are considered for the subsequent period, cost of production etc. will also have to be considered for the subsequent period. This is an impracticable situation and depending upon to whom the changes favour, various parties may keep on asking to refer to more recent data and so on. Various parties have made representations based on the facts prevailing during the investigation period. A reference to a fixed period is necessary as otherwise there can be no common meeting ground. The possibility of subsequent imports being influenced by the fact of initiation of an investigation can also not be ruled out. In fact, the Applicants have submitted that the increase in the import prices of Acetone is an attempt on the part of the respondents to thwart the efforts of the Applicants to seek imposition of safeguard duty. They have quoted their experience of the recent safeguard proceedings for Phenol where as soon as the investigation was initiated, the price of Phenol started showing up and went from a level of about US \$ 395 PMT to US \$ 415 PMT and as soon as the duty was levied, the prices started sliding from US \$ 415 PMT on to US \$ 385 PMT and below. They have mentioned that when they approached the Govt. for Phenol safeguard duty, it would have been apparent to the interested parties that the Applicants would approach the Govt. similarly for Acetone as well. In any case, this price rise is going to be short-lived as new capacities are coming up that of Phenolchemie – 240,000 MTpa, Shell – 138,000 MTpa and Mitsui, Singapore –120,000 MTpa etc. In view of the above, the subsequent changes in price of imported Acetone is not considered relevant for the present proceedings.

- (v) It has also been submitted that the import price of US \$ 240 PMT is not the representative price of imported Acetone. In this regard, it may be mentioned here that these findings are not based on any isolated transaction but import prices prevailing over a period of time have been considered on a weighted average basis for the determination of the desirability of imposition of safeguard duty. Another submission that has been made in this regard is that the decline in price of imported Acetone is not peculiar to India and it was keeping in trend of the decline in prices in other parts of the world. This argument, however, is considered irrelevant for the present proceedings as safeguard measures are not targetted against unfair imports but seek to provide protection to the domestic industry, if the imports enter in increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers.
- (vi) In the context of injury to the domestic industry, it is also useful to consider the stand taken by NOCIL. Although NOCIL have chosen not to be considered as a part of the domestic industry affected by the imports of Acetone into India and their right cannot be disregarded, yet it needs to be appreciated as to why have they chosen to do so. Is it a manifestation of injury that has compelled them to import Acetone rather than produce it, or is it a voluntary decision independent of the prices of imported Acetone. NOCIL produced 7277 MT of Acetone in 1994-95, 6731 MT

in 1995-96, 3209 MT in 1996-97, 1523 MT in 1997-98 and 1021 MT in 1998-99. It is seen from the above that the production of Acetone by NOCIL declined drastically in 1996-97 and thereafter. This has to be seen in the background that on the one hand the import prices started falling from an average of about US \$ 425-430 PMT in 1996 and 1997 to US \$ 360 PMT in 1998 and US \$ 265 PMT in the first quarter of 1999, on the other hand there was a reduction in import duty. The Applicants have explained that the competition from increased imports was felt most severely by the Alcohol based Acetone manufacturers followed by the IPA based Acetone producers. NOCIL, who are a producer of both Benzene and Propylene chose to adopt IPA route for the production of Acetone instead of Cumene route. This perhaps explains the background of NOCIL's decision to import Acetone for use in the manufacture of downstream products rather than produce Acetone for captive consumption and to use their resources otherwise in more beneficial activities. This also finds support from the fact that NOCIL have suggested fixing floor price for imposition of safeguard duty on Acetone at a level which perhaps may encourage them to produce Acetone.

- (vii) Some parties have claimed that Chemical Industry at large has been passing through a global recession and the Indian Chemical Industry has also felt its impact. The downtrend in business and prices is, therefore, not peculiar to India. This argument, however, does not appear to be borne out on facts as while on the one hand the imports have increased substantially, the apparent consumption of the domestic market, on the other hand has also increased substantially in 1998-99. The depressed condition of domestic Acetone industry thus is not due to lack of domestic demand or due to general recession, if any, in the Chemical Industry but due to the increased imports of Acetone at cheaper prices.

7. Other Issues

(a) Joint Product Evaluation

It has been argued that Phenol and Acetone are joint products and, therefore, it would not be appropriate to assess injury to the domestic industry for Acetone alone without assessing position with regard to Phenol. In this regard, it is observed that both the domestic producers maintain their records in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the injury in respect of Acetone has been assessed in accordance with GAAP for joint products. Assessment of the position of the domestic industry with regard to Phenol is, therefore, not relevant for the purpose of present investigation.

(b) Monopoly/Duopoly of Domestic Producers

- (i) Some of the parties have argued that the domestic producers of Acetone have enjoyed monopolistic situation as they control upto 97% of the domestic production of Acetone and that the current complaint is with a view to secure and sustain the complainant's duopolistic dominance in the Indian market whereby they can

continue to exploit the domestic market. In this regard it is observed that any monopoly is not to be considered illegal *ipso facto* but a balance needs to be struck between the injury caused as a result of monopolistic or restrictive trade practices and the reasonableness thereof in the context of benefits accruing thereby. Out of the four 'affected domestic producers' of Acetone, HCL is in the private sector, Krishna and Rajaram (Walwa) are co-operative units and HOC is in the public sector. HOC accounts for more than 50% of the production capacity of Acetone. Besides, the import of Acetone is under Open General License. Nearly 40% of the total apparent consumption has been catered to by the imports. The petitioners have not requested for banning the import of Acetone, instead they have requested for imposition of safeguard duty on the imports of Acetone in accordance with the law so as to enable them to adjust to the new situation of competition offered by the increased imports. The domestic Acetone industry with the assured domestic availability of Acetone has acted as a catalyst in the development of a host of downstream industries such as Pharmaceuticals, Pesticides, Explosives, Paints, Rubber chemicals and other down-stream chemical such as Methyl Methacrylate, Bisphenol – A etc. These important sector of industry cover various important fields such as health, agriculture, defence and construction etc. It may also not be out of place to mention here that this situation is not peculiar to India alone. The current major suppliers of Acetone to India namely South Africa have only one manufacturer owning 100% of the Acetone capacity.

- (ii) It has also been alleged that the Applicants changed domestic Acetone prices in unison. The Applicants in this regard have submitted that they try and maintain landed price parity with the imported Acetone, which is under OGL offering tremendous competition to the Applicants. The prices are market driven and if either of the Applicants reduces the prices, the other has to follow suit immediately to prevent loss of sale and the market share. The products of the two companies are identical and, therefore, they have to match the door-delivery prices by following different discounts etc. as the two companies are located in different places and the freight on transport of Acetone forms a significant component of the cost. This allegation, therefore, has no merits.

(c) Import Duty Structure in India

Some parties have submitted that in keeping with the growing policy of liberalisation, the import duty of Acetone has been reduced over the years but still it is the highest in this region and, therefore, provides an in built protection and competitive parity to the manufacturers of Acetone in India. This argument, however, is considered to be irrelevant in the context of safeguard duty as the level of import duty on a particular product depends upon various factors some of which are level of imports duties on comparable and competitive products and on inputs, the need to raise revenue and the disadvantages suffered by the domestic producers vis-à-vis international producers etc. Each country, therefore, decides the level of import duties according to its needs, which cannot be viewed as a reference point for others. It is also relevant here to mention that the import duty differential

between Acetone and its raw materials namely Benzene and Propylene has reduced from 70% in 1993-94 to 50% in 1994-95 and to 20% in 1998-99. The import duty differential between Acetone and Cumene has been reduced from 45% in 1993-94 to 20% in 1998-99. The reduction in import duty of Acetone in India, therefore, has been much faster than the reduction in import duty of Benzene and Propylene which came down from 15% in 1993-94 and 1994-95 to 10% in 1995-96 but has again been restored at the level of 15% in March, 1999. In case of Cumene, the import duty has come down from 30% in 1994-95 to 10% in 1998-99 and raised to 15% in March, 1999.

(d) Uncompetitive Sourcing of Raw Materials

It has been argued by some that the domestic producers have not procured their raw materials competitively, which is one of the causes of injury to them. They have mentioned that the Indian Acetone producers suffered because of uncompetitive price of Propylene – 65% higher than international prices and added transport costs, and uncompetitive in-house production of Cumene rather than importing at cheaper costs by utilising 180 days credit facility etc. In this regard, it is observed that Acetone in India is produced using Cumene, Alcohol or IPA route. The Applicants produce Acetone using Cumene route. They have submitted that it is necessary for them to have a judicious mix of Cumene based on in-house production supplemented by imports. The variable cost of Cumene typically have been consistently comparing favourably with the landed price of imported Cumene. This is partly because imported Cumene prices have a high profit margin built in, which is recovered from the Cumene purchasers and that for every import of Cumene, prices and terms are sought from available sources and most competitive prices are obtained before taking a buying decision. The data regarding cost of production of Cumene has been verified and it is observed that the variable cost of Cumene produced in-house compares favourably with the landed cost of Cumene. It, therefore, cannot be considered prudent to import 100% of the Cumene requirement by the domestic Acetone producers. As regards the import of Propylene, it has been stated by the Applicants that Propylene which is in gaseous form at normal temperatures and pressures has to be artificially liquified making the freight charges very high which renders the import option unviable, particularly for the small parcel sizes. In any case, Propylene is to be used in the manufacture of Cumene and so long the Applicants produced Cumene at prices favourable as compared to imported Cumene, they cannot be considered to be sourcing their raw materials uncompetitively.

(e) Self - Inflicted Injury

It has been claimed that the injury to the Applicants is self-inflicted as HCL have imported substantial quantities of Acetone and HOC floated a tender and negotiated the import prices to be brought down. In this regard, it is observed that HCL imported around 2700 MT of Acetone during 1998-99, most of which was imported against duty free entitlement for use in export production. The total

imports of Acetone into India during 1998-99 were 29182 MT and HCL's imports constituted less than 10% of the total imports in 1998-99. Imports by HCL during the previous year were about 4900 MT. The imports by HCL in 1998-99 have, therefore, come down substantially. As regards floating of tender by HOC, they have submitted that the tender was floated to shore up the depleting stocks of Acetone and due to temporary uncertainty in production in forthcoming days due to possible power shut-downs during monsoon. They had floated the tender for 500 MT but purchased only 250 MT at US \$ 275 PMT. These quantities were lower than normal parcel size. Generally the import parcels are much larger in size. It, therefore, does not appear that the HOC's tender or the alleged negotiations had any effect on the import prices of Acetone into India or that the injury is self inflicted.

(f) Other Capacities Remaining Idle

It has been alleged that HOC and HCL have made Alcohol based units unviable years ago. In this regard it is observed that production of Acetone based on Alcohol is not peculiar to India alone. World over this is a well known route used for the production of Acetone and Acetone so produced competes well with Alcohol produced through other routes. It may also be mentioned that while the domestic producers may face internal competition that is competition amongst themselves, the purpose of imposition of safeguard duty to provide protection to the domestic producers from external competition i.e. from competition offered by imports. Safeguard duty cannot be denied on the ground that the domestic producers suffer from internal competition. In the present investigation, it is observed that the domestic demand in 1998-99 was over 68000 MT and HOC and HCL together produced 41222 MT which still left a gap of about 27000 MT. The Alcohol based units had capacities far below this demand. The Cumene based producers, therefore, did not take away their market but the imports filled this gap. The two Alcohol based producers namely Krishna and Rajaram (Walwa) have specifically supported the Applicants in seeking imposition of safeguard duty on the increased imports, which they have alleged to be the cause of injury suffered by them. It was, therefore, not because of HOC and HCL that the Alcohol based producers could not utilise their Acetone capacities.

(g) Capacity Creation Cannot Be A Cause Of Injury

- (i) It has been argued by Mitsui Chemicals Inc. that if there has been capacity creation then it cannot be said that there is causal link between imports and injury. They have in support cited the 'Certain Categories of Glass Case' - OJ 1986 C128/7. At the outset, it may be mentioned that this is an investigation report of the European Commission which has no binding force in India. The investigation has been conducted in terms of Regulation (EEC) No. 288/82 and not under the Regulation reflecting the provisions of the Agreement on Safeguards which has been incorporated only on 1.1.1995 under the WTO Regime. The facts of that case are quite distinguishable in as much as in that case there were imports into Greece

241 671-99-

other than those investigated. The authorities also considered the level of consumption of glass in Greece, changes in the structure of demand, which were accompanied by technical adaptation by the Greek industry; and the effect of the price control system set up by the Greek authorities on the profitability of the Greek industry. The facts in that case were that the Greek industry made major investments in 1980 in building a drawn glass production line, and not one for float glass. The consumption of drawn glass fell mainly due to slow-down in the building sector and there was an alteration in the structure of demand. Between 1981 and 1984 consumption of drawn glass fell by more than 17000 tonnes, while that of float glass, for which the Greek industry did not have the necessary technology, increased by 12000 tonnes. Drawn glass was thus clearly replaced by float glass. Clearly the facts in the present case are distinguishable as the domestic producers have expanded capacity for the production of Acetone whose demand has increased but the domestic producers have not been able to increase their market share.

- (ii) Mitsui Chemicals Inc. have also sought to draw support from this case to say that if downward trend was earlier discernible then it cannot be said that there is causal link between imports and injury. This also does not help them since in the present case there is no earlier discernible downtrend. In the present investigation it is being examined whether the domestic producers have faced a threat of serious injury as evident on comparison of their performance in 1998-99 with that of earlier period. The case of the domestic producers is that they have faced a severe set-back in performance in 1998-99 as compared to earlier years. It may also be pertinent to observe here that for the purpose of the present investigation, what needs to be considered is the domestic industry as defined under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and not individual units. The performance of the 'affected domestic producers' as a whole, therefore, needs to be considered which does not show any earlier discernible downward trend.
- (iii) Mitsui Chemical Inc. have also argued, relying upon the pronouncement of the European Commission, that if the production and sales have either remained constant or gone up, no causal link can be claimed with imports. This is not in accordance with the provisions of the law which requires determination of injury to be made on an objective evaluation of various factors and not just upon production and sales. In fact, in determination of causal link between imports and injury, the Annex to Safeguard Duty Rules requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of that article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production etc. If, therefore, the increased imports enter in such condition that despite higher domestic production and sales, if the imports occupy a higher market share and thus displace the domestic production, the injury so caused is undoubtedly attributable to increased imports. In the present case, however, there is no increase in production in 1998-99 as compared to 1997-98 although sales have

increased by 1.3% in 1998-99 compared to 1997-98 but which were far below the growth of 21.1% registered in apparent consumption.

- (iv) Mitsui Chemicals Inc. have similarly argued that if there is loss of exports, imports cannot be said to be causing injury. On this count also the facts of the case investigated by the EC were quite distinguishable as in that case the consumption of wired or figured glass fell by about 4400 tonnes between 1981 and 1984 and exports by the Greek industry was an indispensable outlet for the Greek industry, which could not achieve any success on exports front. In the present case, there is no fall in consumption in the domestic market, rather there is an increase in consumption and the Applicants although lost on actual exports but supplied comparable quantities in the domestic market on deemed export basis. Thus, Mitsui on no count succeeds in drawing support from the 'Glass case'.

(h) Substantial Capacities Being Set Up Abroad

It has been submitted by the Applicants that Acetone demand growth worldwide, which was 4.2% per annum in the last few years will take off to 3.1% per annum in the years to come due to factors such as the switch over to water based paints from Solvent based System etc. The current capacity of about 5 million TPA is in excess of the demand estimated at 3.85 million TPA. There is thus a surplus of over 1 million TPA and further new capacities of around 1 million TPA are expected to be set-up in the next 3-4 years. The recent and near future expansion include Phenolchemie, Gladbeck – 43000 MTpa, DSM – 12000 MTpa, Ertisa, Spain – 90000 MTpa, Phenolchemie – Mobil – 244000 MTpa, China – 60000 MTpa and Mitsui, Singapore – 120000 MTpa. The surplus 3-4 years hence is, therefore, expected to be over 1.75 million TPA which would mean more than 40% excess capacity over demand. This excess capacity is going to have its impact on the Acetone producers in India as well. It has been claimed that Mitsui has technology to convert Acetone back into Propylene. In this regard, it is observed that this is one of the technical option available with Mitsui, but whether they would resort to this option and whether it will be economical for them is to be seen in the future. The impact of Mitsui's setting up an Acetone plant on the domestic producers, however, cannot be denied.

8. Adjustment Plan

- (i) The Applicants have submitted a restructuring plan indicating details of efforts being taken and planned to be taken to make a positive adjustment to improve their competitiveness. Both the domestic producers have categorically stated that they understand that the relief granted as safeguard duty is a short-term measure. The existing facilities were built in the pre-liberalisation, MRTP era and lacked economies of scale leading to high fixed costs. However, the Indian industry has been regularly upgrading its technology and debottlenecking its manufacturing facilities with the objective of reducing the operative costs per unit and increasing its effective capacity to satisfy the increasing domestic demand from most of the

sectors. On the capacity enhancement front (with consequent reduction in the fixed costs of manufacture), HCL, which has very recently increased its capacity from 12000 MTpa in 1994-95 to 18300 MTpa in 1998-99 has active plans to increase it to 24000 MTpa. To reduce the power cost, steps have already been taken by HCL towards setting up of captive power generation facilities by the Co-generation route. The facility has already been installed and would get stabilised soon. Apart from this external consultants had been appointed to suggest various cost reduction measures. Some such suggestions e.g. improvement in quality of feedstock (Cumene) are extremely valuable from the point of view of reduction in the cost of manufacture of Acetone. All this is an ongoing exercise, which would continue. In the medium term Propylene will be imported by the industry through the new facilities being generated at ports like the J.N.P.T. near Mumbai (for which both HOC and HCL have been the promoters and which has got clearances from the Ministry of Surface Transport and the Ministry of Environment and Forests) and GCPTL at Dahej. The capacity of IOC refinery at Panipat is being increased and the process would be completed by mid 1999. Also the global sized refinery of Reliance Industries Limited at Jamnagar is expected to be commissioned in 1999. With the cracker complexes at GAIL and Haldia also expected to be commissioned in the near future and with debottlenecking of the existing facilities, the domestic Propylene availability could ease out and prices could soften and sourcing would be possible from the new sources. HCL is also planning to set up world scale Greenfield Phenol manufacturing facilities (either 60000 MTpa or 90000 MTpa). The HCL facility is being planned at Dahej in Gujarat state. Technologies have also been tied up. State-of-the-art Zeolite technology for Cumene has been tied up with UOP of USA. Similarly, latest generation technology has been tied up for Acetone manufacture with ABB Lummus Global of USA. Both technologies are environment friendly and would give HCL certain operational and cost advantages. The raw materials would either be imported or could be sourced from the new facilities such as the ones mentioned above. Land has been allotted for the HCL project. Environmental Impact Assessment study has been completed. The Gujarat Pollution Control Board has granted N.O.C. for the project. HCL's water requirements have been included in the common water supply schemes of GIDC at Dahej and they have made initial payments towards the same. Power is planned to be generated captively by the co-generation route. On the funding aspect, HCL has already approached the financial institutions. The raw material and finished product traffic figures of the HCL project have been factored in the overall traffic figures of Gujarat Chemical Port Terminal Complex coming up at Dahej. This port is expected to be operational by the end of 1999. There is a further possibility of a co-operative effort on this front between the two manufacturers, HOC and HCL.

- (ii) HOC in this regard have stated that on the capacity enhancement front (with consequent reduction in the fixed costs of manufacture), HOC is planning to increase its capacity to 39000 MTpa accompanied by upgradation of technology for manufacture of Cumene by the use of modern Zeolite Catalyst System. Apart from this, various energy conservation schemes would be implemented by them at an expected investment of Rs. 65 crores. All this is an ongoing exercise which would

continue. As a long term measure, HOC is planning to set up world scale Greenfield Phenol manufacturing facilities of 60000 MTpa or 90000 MTpa. The investments would be in the region of Rs. 650 crores or more depending upon the size of the facility. A part of the quantity produced will be exported. They have also mentioned that there is a possibility of a co-operative effort on this front between HOC and HCL.

- (iii) Based on the schemes pursued by HOC to improve their competitiveness, they expect to achieve a total cost saving of Rs. 3939 PMT in 2001-2002. They also expect to achieve a further cost-saving of Rs. 655 PMT by pursuing Acetone specific improvement measures, the full potential of which will be realised in 2002-2003. Similarly, HCL expects to achieve a cost-saving of Rs. 5956 in 2001-2002 and a further cost saving of Rs. 1511 PMT by pursuing Acetone specific improvements, the full potential of which will be realised in 2002-2003.
- (iv) The Applicants have thus identified the reasons for their being not able to meet with the competition offered by the increased imports. One of the reasons identified by them is the lack of economies of scales. The domestic producers have constantly been upgrading their production facilities. During the last few years, they have enhanced their capacity gradually from 36640 MTpa in 1994-95 to 45950 MTpa in 1998-99, which accounts for an increase of about 25% in the capacity. The domestic producers have furnished essential details of cost saving schemes being pursued by them and the cost reduction likely to be achieved therefrom in response to the Questionnaire. This appears to be a viable adjustment plan, which is likely to be implemented and give results in 2001-2002 i.e. in two and a half years. It is, therefore, observed that the domestic industry is in the process of making positive adjustment to compete with imports and that they require two and a half years to become competitive.

9. Public Interest

- (i) Some of the parties have argued that imposition of safeguard duty would not serve any public interest. On the contrary imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industry may close down. In this regard, it is observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term, which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported Acetone in the hand of buyers and therefore, it may also effect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent just adequate, would, therefore, not only minimise the adverse effect, if any, for the customers but also allow them a wider choice to source their requirements, and at competitive prices. The domestic producers who

have set up plants with huge public investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Safeguard duty, which would enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports, will, therefore, also be in the long-term interest of the buyers of Acetone as well as of the buyers of products manufactured therefrom. It is, therefore, considered that imposition of safeguard duty on Acetone will be in the Public interest.

10. **Provisional Safeguard Duty**

In view of the fact that critical circumstances indicating that the domestic industry is likely to suffer irreparable damage in case imposition of safeguard duty was delayed till the completion of the investigation did not exist, no recommendation to impose provisional safeguard duty was made.

11. **Share of Countries in Exports to India**

The individual shares of countries / Territories in the exports to India in 1998-99 were as under :-

Table – 10

Country/Territory	Imports MT	% age share
Germany	1603	5.49
Japan	583	2.00
Netherlands	2572	8.81
Russia	2040	6.99
South Africa	16384	56.15
South Korea	2975	10.19
Taiwan	1005	3.44
USA	1480	5.07
Others	540	1.86
Total	29182	100.00

G. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

1. In view of the findings above, it is concluded that increased imports of Acetone into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Acetone and it will be in the Public interest to impose safeguard duty for a period of two and a half years on imports of Acetone into India.
2. In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of production for HCL and HOC has been taken into account for the entire 1998-99, being more reflective of the true costs for the whole year. The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of

expected return on capital employed etc. which is considered to be on the higher side and, therefore, a lower amount of profit (confidential) based on the weighted average cost of production has been considered appropriate and allowed. Similarly, the C.I.F. import prices of Acetone also have been considered on weighted average basis for the last six months i.e. October, 1998 – March, 1999. Adjustments have been made in the C.I.F. import price for credit terms and handling charges on an average basis. Change in the applicable rate of customs duty has been taken into account in working out the landed price of imported Acetone.

3. Considering the need to progressively liberalise the safeguard duty in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of Acetone into India at the rates specified below on ad-valorem basis for a period of two and a half years as under being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Acetone.

Period	Level of total protection recommended %	Existing protection %	Safeguard duty recommended % (2)-(3)
(1)	(2)	(3)	(4)
First year	38.5 + 28	38.5	28
Second year	38.5 + 21		21
Balance six months	38.5 + 9		9

[F. No. SG/INV/1/99]

R.K. GUPTA, Director General

